संपादकीय

नई दिल्ली, शुक्रवार 28 जून 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. माया राम सुरजन

आपातकाल विरोधी कोरस में राष्ट्रपति का स्वर

भारत के संविधान में वैसे तो राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च बतलाया गया है लेकिन जो संसदीय प्रणाली देश ने अपनाई है, उसके अंतर्गत इस पद पर बैठे व्यक्ति की सत्ता कार्यपालिका द्वारा निर्धारित होती है। स्वविवेक से राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता, कह भी नहीं सकता। राष्ट्रपति के मन्तव्य दरअसल उसकी सरकार की मंशा होती है। कार्यपालिका प्रमुख यानी प्रधानमंत्री ही उसके हर कहे या लिखे गये शब्द को निर्धारित करता है जिसका सम्बन्ध प्रशासन से होता है। वर्ष भर में कम से कम दो मौके ऐसे होते हैं जब राष्ट्रपति के भाषणों का पूरा देश उत्सुकता से इंतज़ार करता है, पहला होता है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को दिया जाने वाला संदेश और बजट सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उनका अभिभाषण। नयी लोकसभा के प्रथम सत्र के अवसर पर भी राष्ट्रपति के इस वक्तव्य का राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दोनों ही परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्व होता है।

यह जानने के बावजूद कि यह सरकार की ओर से तैयार कर राष्ट्रपति के जरिये इन दो मंचों से जनता को दिया गया संदेश होता है, उसकी अहमियत बनी रहती है और उसे केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाता कि उसमें राष्ट्रपति का व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। दोनों ही भाषणों की देश के साथ दुनिया भर में मीमांसा होती है क्योंकि इसके माध्यम से सरकार की केवल उपलब्धियां नहीं दर्शाई जातीं बल्कि उसके नज़रिये और भावी कार्यक्रमों की भी मीमांसा होती है।

ऐसे में बहुत आवश्यक होता है कि जब भी सरकार राष्ट्रपति के हाथों में पढ़ने के लिये कुछ पकड़ाये तो उसे देखना चाहिये कि वह सत्ताधारी पार्टी के हितों से ऊपर उठकर बात करे। राजनीतिक एजेंडा संसद के दोनों सदनों व चुनावी रैलियों में तथा सार्वजनिक मंचों पर तो चलाया जाता है परन्तु अभिभाषण किसी व्यक्ति या दल के राग-द्वेष तथा हितों से प्रभावित होकर नहीं लिखे व पढ़े जाने चाहिये। भारत की संसदीय परम्परा में ज्यादातर राष्ट्रपतियों ने वास्तविकता में रबर स्टांप की हैसियत होने के बावजूद अपने वजूद व पद की गरिमा हमेशा बनाये रखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी महान शख्सियत के साथ काम करने के बावजूद डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इस पद की ताकत व गौरव को उस पीएम के बराबर ला खड़ा किया था जिसे नेहरू सम्हाल रहे थे। बहुत कम पढ़े-लिखे होने के बाद भी ज्ञानी जैल सिंह ने इंदिरा गांधी की असामयिक मृत्यु के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर देश को राजनीतिक व संवैधानिक संकट से बाहर निकाला था, वह भी सभी ने देखा था। इंदिरा की हत्या के कारण भड़के दंगों के दौरान दिल्ली में सिखों के हुए नरसंहार को अपने समुदाय से न जोड़कर वे पद की गरिमा को नयी ऊंचाई तक ले गये। इतना ही नहीं, जब राजीव गांधी सरकार के एक मंत्री केके तिवारी ने 'राष्ट्रपति भवन को खालिस्तानी आतंकवादियों का अड्डा' बतलाया तो उन्हीं जैल सिंह ने राजीव गांधी को पत्र लिखकर तिवारी को हटवाया था। एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणव मुखर्जी ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके कार्यकाल के दौरान दो विपरीत विचारधाराओं वाले दलों के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन हुआ परन्तु दोनों ने ही उसे बेहद सहज ढंग से लेकर संविधान की सत्ता को बरकरार रखा।

जिस तरह से मोदी के कार्यकाल में तमाम संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन हुआ है, उनमें राष्ट्रपति पद भी है। वैसे भी यह पद वास्तविक अधिकारों वाला नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उस पर हर बार ऐसे व्यक्ति को बैठाया है जो पहले से कमजोर हो। पहले जिन रामनाथ कोविंद को बिठाया गया वे भी हमेशा मोदी से दबकर रहे। अब द्रौपदी मुर्मू हैं जो इतनी शक्तिहीन हैं कि उनके खड़े रहते मोदी के बैठे रहने की तस्वीरें तक आई हैं। अयोध्या स्थित रामलला मंदिर का जब शिलान्यास हुआ तो श्री कोविंद को नहीं बुलाया गया और जब उसका प्राणप्रतिष्ठा समारोह हुआ तब सुश्री मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया गया। वैसे देखें तो खुद को कमजोर बनाने में इन दोनों का अपना योगदान भी कुछ कम नहीं है। श्री कोविंद ने जहां अपने सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार द्वारा 'एक देश एक चुनाव' पर बनी कमिटी का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया, वहीं सुश्री मुर्मू ने मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें दही-शक्कर खिलाई थी। दोनों ने बता दिया था कि वे चाहे जिस पद पर हों, पार्टी कार्यकर्ता बने रहेंगे।

18वीं लोकसभा के पहले सत्र के प्रारम्भ होने के पहले मीडिया के सामने अपने उद्बोधन में मोदी ने कोई सकारात्मक शुरुआत करने की बजाये 50 वर्ष पहले लोगों द्वारा भुला दी गई इमरजेंसी की याद कराई। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बने ओम बिरला ने इस पर एक प्रस्ताव लाकर बतला दिया कि जिस काम के लिये उन्हें यह सीट पुन: मिली है, उसका निर्वाह वे करते रहेंगे- वह है भाजपा का एजेंडा चलाना। इसी सहगान में अपना स्वर मिलाती हुईं राष्ट्रपति मुर्मू भी गुरुवार को नज़र आईं जब उन्होंने अपने अभिभाषण में आधी सदी पहले ढाई साल के अल्पकाल के लिये खुलकर बंद हो गये आपातकाल के अध्याय को फिर से खोला। उन्होंने भारत के कथित रूप से 'लोकतंत्र की जननी' वाले मोदी के जुमले को दोहराया जबकि वे जिस समाज (आदिवासी) से आती हैं उसके हिस्से में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले कितना लोकतंत्र आया था, यह वे बखूबी जानती हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबों-वंचितों के उत्पीड़न पर उनकी सरकार क्या कर रही है, उसका उल्लेख होता तो बेहतर था। खैर, लोग जानते हैं कि अभिभाषण में उनका कोई योगदान नहीं। जिस राष्ट्रपति की दिनचर्या तक प्रधानमंत्री कार्यालय से तय होती हो, उनसे कोई उम्मीद नहीं है।

पुराना रवैया वापस होने के खतरे

आम तौर पर सत्ता पक्ष और कई बार विपक्ष के लिए भी चुनावी जनादेश लट्टू या झाड़ू की तरह का होता है लेकिन सामान्य रूप से मतदाता बहुत बारीक निर्णय देता है। लोकतंत्र असल में बारीकी का ही खेल है और साम्यवाद की तरह लट्ठमार समानता, तानाशाही या बादशाहत की जगह यह दुनिया भर में सफल होता गया है तो उसकी यह बारीकी ही असली चीज है। और इसे 365 दिन और चौबीस घंटे राजनीति करने वाले राजनेता न समझ सके तो यह स्थिति चिंता की है। अठारहवीं लोकसभा के लिए हुए हाल के चुनाव से आए जनादेश के मामले में ऐसा ही लगता है। चुनाव नतीजे आने और भाजपा को उसके दावे या उम्मीद से काफी नीचे तथा विपक्ष को कई राज्यों में उम्मीद से ज्यादा मिली सफलता के तत्काल बाद तो पक्ष और विपक्ष, दोनों के हाव-भाव से यह लग रहा था कि दोनों ने मतदाताओं के संदेश को ठीक से ग्रहण किया है। प्रधानमंत्री और भाजपा को अचानक एनडीए प्रिय हो गया, वे कई बार नजर चुराते भी लगे तो उनके दरबार के सबसे ताकतवर बताए जाने वाले अमित शाह को 'छुपाना' शुरू कर दिया गया। मोदी जी अपने फ़ोटो के फ्रेम में नीतीश और चंद्रबाबू ही नहीं प्रफुल्ल पटेल और ललन सिंह जैसों को भी आने दे रहे थे। विपक्ष तो न जीतकर भी जीतने से ज्यादा उछल रहा था। विपक्षी उत्साह बरकरार है लेकिन मोदी जी के रंग-ढंग पुराने लगने लगे हैं। मंत्रिमंडल के गठन से लेकर विभागों के बंटवारे या मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार जैसों की बात का जबाब ही नहीं नीट घोटाले में मुंह न खोलने से भी यह रंग दिखने लगा था।

लेकिन नई लोक सभा के पहले दिन उन्होंने जिस तरह विपक्ष पर हमला किया, उसके संविधान प्रेम को नाटक बताया और पचास साल पहले लगे आपातकाल के मुद्दे से कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया वह साफ संकेत था कि वे जनादेश को बहुत साफ ढंग से अपने हक में मानते हैं, अपनी जीत को ऐतिहासिक और अपूर्व मानते है। अपने सांसदों की संख्या घटना, सहयोगी दलों पर निर्भरता और विपक्ष की बढ़ी ताकत से उनके मन पर कोई असर नहीं पड़ा है। वे अपने रंग से सरकार और राजनीति चलाने के मूड में हैं और हाल-फिलहाल वे नई स्थितियों अर्थात चुनाव से निकले जनादेश की कम से कम परवाह करने वाले हैं। विपक्ष की ताकत बढ़ी भले हो लेकिन अभी भी उसकी एकता ही नहीं कार्यक्रम और नजरिए का असमंजस प्रधानमंत्री को ताकत दे रहा है। और जो व्यवहार उन्होंने नतीजे आने के बीस दिन में ही दिखाने शुरू किए हैं उससे लगता है कि उनकी तरफ से पिछला रवैया ही जारी रहेगा-अर्थात चौबीसों घंटे चुनावी चिंतन और तैयारी, हर काम का उद्देश्य चुनाव जीतना और इसमें विपक्ष को हड़पने और निगलने की जरूरत लगे तो उससे भी परहेज नहीं।

अरविन्द मोहन

> यह चुनाव भाजपा की सीटें कम होने या विपक्ष की सीटें बढ़ना और संसद में काफी समय बाद विपक्ष के ताकतवर बनने(जिसको लेकर बात-बात में टकराव और कामकाज बाधित होने की आशंका प्रबल हुई है) भर का नतीजा या जनादेश लेकर नहीं आया है। यह सत्ता, साधन और दिन-रात के प्रबंधन, जिसमें मीडिया से लेकर हर बारीक चीज का ध्यान रखा गया था।

यह चुनाव भाजपा की सीटें कम होने या विपक्ष की सीटें बढ़ना और संसद में काफी समय बाद विपक्ष के ताकतवर बनने(जिसको लेकर बात-बात में टकराव और कामकाज बाधित होने की आशंका प्रबल हुई है) भर का नतीजा या जनादेश लेकर नहीं आया है। यह सत्ता, साधन और दिन-रात के प्रबंधन, जिसमें मीडिया से लेकर हर बारीक चीज का ध्यान रखा गया था, के खिलाफ आम आदमी की नाराजगी की अभिव्यक्ति का था। मोदी की सत्ता और अमित शाह के प्रबंधन से कांग्रेस या सपा नहीं लड़ी, लोगों का गुस्सा चैनलाइज्ड होकर उनके पक्ष में गया। हल्का संगठित विरोध सिर्फ तमिलनाडु और बंगाल जैसे राज्यों में दिखा। यह प्रबंधन, साधन और सत्ता के सहारे चुनाव जीतने के भ्रम का टूटना भी था। और यह कहने में हर्ज नहीं है कि अगर भाजपा की तरफ से एक-एक सीट के लिए इतनी चौकसी न रहती, इतना साधन न लगता और सत्ता का इतना खुला दुरुपयोग न होता तो उसे कम से कम पचास और सीटें कम मिलतीं। साधन भी एलेक्ट्रोरल बांड जैसे उपायों से किस तरह जुटाए गए और ईडी-सीबीआई वगैरह के दुरुपयोग हो रहा है यह देश ने बहुत साफ देखा। इन कदमों ने भले तत्काल मदद कर दी हो लेकिन लोगों का गुस्सा इनकी वजह से भी बढ़ा।

अकेले प्रधानमंत्री का रुख भले पुराने गियर में वापस आ गया हों लेकिन मुल्क, राजनीति और प्रतिपक्ष का रुख तो बदल चुका है। लोग महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब चाहते हैं और आप मौजूदा नीतियों से बंधे हैं जिनसे इनका उपाय संभव नहीं है। आपने साफ-साफ सांप्रदायिक प्रचार करके भी नतीजा देख लिया और मुल्क जाति के विमर्श को आगे बढ़ा रहा है। आपको लगता है कि मंत्रिमंडल के गठन में कुछ पिछड़ों को लेने जैसी कर्मकांडी नियुक्तियों से बात बन जाएगी। आपको कांग्रेस मुक्त भारत के तहत विपक्ष की राज्य सरकारें गिरवाने का शौक रहा है (उनके अपने विरोधाभास भी रहे हैं) लेकिन अब आपको अपने और सहयोगी दलों की राज्य सरकारों से भी बेहतर ढंग से डील करना होगा। आप आंध्र, बिहार और ओडिशा को पैकेज दें न दें लेकिन ज्यादा साधन देने होंगे। मुसलमानों और औरतों के प्रतिनिधित्व का सवाल भी आपको सुलझाना ही होगा क्योंकि संसद में जैसी विपक्षी महिला सांसद आ गई हैं या मुसलमानों ने जिस तरह नतीजों में असर डाला उनको आप आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर महाराष्ट्र हो या हरियाणा, झारखंड हो या दिल्ली अभी जिन राज्यों के चुनाव आने वाले हैं वहां आपकी स्थिति इस चुनाव में दयनीय ही रही है।

इन सबके ऊपर आपको भाजपा और संघ परिवार को भी संभालने में ज्यादा परेशानी आनी है क्योंकि जनादेश सामने आते ही सिर्फ एनडीए के सहयोगी दल ही नहीं, अपने अंदर से भी ऐसी आवाजें सामने आने लगी हैं जिन्हें आप जेपी नड्डा जैसों से बयान दिलवाकर नहीं निपटा सकते। अब तो विद्यार्थी परिषद खुलेआम धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा मांगने से लेकर देश भर में नीट कांड पर आंदोलन चला रहा है। मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार ने सीधे-सीधे मोदी जी पर ही तीर बरसाए। प्रधानमंत्री के चुनाव की औपचारिकता एनडीए सांसदों की बैठक में पूरी की गई भाजपा संसदीय दल की बैठक ही नहीं हुई। ऐसा संभवत: वहां से विरोध का स्वर उठने की आशंका के चलते किया गया। महाराष्ट्र समेत की राज्यों में घमासान मचा है लेकिन पार्टी का एक धड़ा योगीजी को निपटाने में लगा है। चुनाव की कर्मकांडी समीक्षा हो तब भी टिकट बांटने से लेकर मुद्दे और शैली की चर्चा तो होगी और आप इन सबके लिए किसको दोषी बता पाएंगे। यह सब इसी बात का संकेत करते हैं कि आप भले ही जनादेश को ठीक से न समझें या समझकर दरकिनार करें पर विपक्ष, सहयोगी दल, संघ जैसा समर्पित सहयोगी और भाजपा के सारे लोग भी जनादेश से 'प्रभावित' न हों और पुराना आचरण जारी रखें यह संभव नहीं है।

कांग्रेस की राजनीति में प्रियंका गांधी का उदय और विकास

■ हरिहर स्वरूप

आखिरकार दो दशकों के 'वह करेंगी, वह नहीं करेंगी' के बाद प्रियंका गांधी अब चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। वह केरल के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी। यह वह सीट है जिसे उनके भाई राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में रायबरेली सीट पर कब्जा करने के लिए खाली किया है।

इस घटनाक्रम से पता चलता है - अगर इस बारे में कोई संदेह था - कि राहुल कांग्रेस के प्रमुख नेता होंगे (और जब भी समय आयेगा, प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे)। प्रियंका सहायक भूमिका निभायेंगी। राहुल के लिए हिंदी पट्टी, खासकर उत्तर प्रदेश से जुड़ना जरूरी था, जहां रायबरेली को छोड़कर 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का सफाया हो गया था। यह उत्तर प्रदेश ही है जिसने अब तक आठ प्रधानमंत्री दिये हैं और यह नेहरू-गांधी परिवार की कर्मभूमि रही है।

> अनिश्चितता का वह दौर अब खत्म हो चुका है। 2024 में प्रियंका गांधी न केवल कांग्रेस पार्टी की महासचिवों में से एक हैं, बल्कि वह पार्टी की स्टार प्रचारक हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में चुनावी रैलियों में वक्ता के तौर पर उनकी काफी मांग थी। उनके भाषण केंद्रित होते थे और नामांकन प्रक्रिया के दौरान एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने के लिए उनके नाम पर गंभीरता से विचार किया गया था।

प्रियंका ने हमेशा एक गौण भूमिका निभाई है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वह दोनों भाई-बहनों में से अधिक राजनीतिक रूप से समझदार हैं। 2004 में, यह 'एक पारिवारिक निर्णय' था कि राहुल (और प्रियंका नहीं) सक्रिय राजनीति में आयेंगे और चुनाव लड़ेंगे। उनकी मां सोनिया गांधी ने पड़ोसी रायबरेली सीट से अमेठी में उनके लिए जगह बनाई। उस समय, उन तीनों के चुनाव लड़ने की संभावना पर विचार किया गया था- लेकिन यह प्रियंका ही थीं जिन्होंने स्पष्ट रूप से इसे खारिज कर दिया था। 20 वर्षों तक, उन्होंने अपने भाई और मां की ओर से अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों को संभाला।

हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान एक समय चर्चा थी कि प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और राहुल वायनाड के अलावा अमेठी (जहां वे 2019 में हार गये थे) से फिर से लड़ेंगे। लेकिन यह राहुल ही थे जिन्होंने अपनी दूसरी सीट के रूप में अपेक्षाकृत सुरक्षित रायबरेली को चुना क्योंकि 'पारिवारिक समझ' के अनुसार प्रियंका उस सीट से चुनाव लड़ेंगी जो बाद में वह उन्हें देंगे।

एक चौथाई सदी पहले, सोनिया गांधी ने करिश्माई सुषमा स्वराज (उनकी बेटी बांसुरी स्वराज ने हाल ही में भाजपा के टिकट पर नई दिल्ली सीट से जीत हासिल की) को कर्नाटक की एक सीट पर हराया था। प्रियंका अपनी मां के साथ चुनाव प्रचार में उतरी थीं। तब कर्नाटक (और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु) की कई महिलाएं प्रियंका को पुरानी यादों से देखती थीं क्योंकि वह उन्हें उनकी दादी इंदिरा अम्मा, दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद दिलाती थीं। लेकिन आज, अधिकांश भारतीय लोगों-जिनमें से आधे से अधिक 30 वर्ष से कम उम्र के हैं-को इंदिरा के बारे में बमुश्किल ही कुछ याद है, सिवाय किताबों में पढ़ी गई बातों के।

पिछले कुछ वर्षों में, प्रियंका अपने वन-लाइनर के लिए जानी जाती रही हैं। 1999 में, जब उनके पिता राजीव गांधी के चचेरे भाई और एक समय के भरोसेमंद अरुण नेहरू भाजपा के टिकट पर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने वहां लोगों से बस इतना ही पूछा-'क्या आप ऐसे व्यक्ति को वोट देने जा रहे हैं जिसने मेरे पिता को धोखा दिया'? अरुण नेहरू चुनाव हार गये। वह उनके पिता से अलग हो गये थे और वी.पी. सिंह से हाथ मिला लिया था, जिन्होंने 1989 में राजीव की जगह प्रधानमंत्री पद संभाला था। अपनी राजनीतिक भूमिका के बारे में रहस्य बनाये रखने के लिए उन्होंने कभी-कभार साक्षात्कार भी दिये।

अनिश्चितता का वह दौर अब खत्म हो चुका है। 2024 में प्रियंका गांधी न केवल कांग्रेस पार्टी की महासचिवों में से एक हैं, बल्कि वह पार्टी की स्टार प्रचारक हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में चुनावी रैलियों में वक्ता के तौर पर उनकी काफी मांग थी। उनके भाषण केंद्रित होते थे और नामांकन प्रक्रिया के दौरान एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने के लिए उनके नाम पर गंभीरता से विचार किया गया था। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी सहित सहयोगी दलों की ओर से भी अनुरोध किये गये थे।

प्रियंका ने यह बात कहने पर सहमति नहीं जताई कि वह कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्रीय अभियान के लिए उपलब्ध रहना चाहेंगी। यह बात सही साबित हुई क्योंकि उन्होंने प्रचार रैलियों में भारी भीड़ जुटाई और खास तौर पर महिला मतदाताओं के बीच उनकी खासी लोकप्रियता रही। प्रियंका ने कांग्रेस की ओर से एक अच्छे वार्ताकार के तौर पर भी अपनी क्षमता दिखाई। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ हुई अहम चर्चा में यह बात सामने आई। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ प्रियंका के निजी स्तर पर समीकरण जम गये। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटों को कम करने में मदद की।

यह साफ है कि वायनाड में प्रियंका की जीत आसान होगी और वह जल्द ही लोकसभा में प्रवेश करेंगी। तब राहुल और प्रियंका दोनों ही लोकसभा के सदस्य होंगे, जबकि उनकी मां सोनिया गांधी राज्यसभा में होंगी। राहुल को विपक्ष का नेता नामित किया गया है, जिसका मतलब है कि वह कांग्रेस और विपक्ष की ओर से छाया प्रधानमंत्री की भूमिका में होंगे। राहुल के पास लोकसभा में प्रधानमंत्री से बराबरी के स्तर पर भिड़ने का मौका होगा। लोकसभा सत्र में प्रियंका के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें रहेंगी। क्या वह लोकसभा में अपने भाई राहुल गांधी को मात दे पाएंगी? आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा।

पावन प्रसंग

भावनात्मक बुद्धिमता

पहले आईर क्यू के आधार पर व्यक्ति की दक्षता का परीक्षण किया जाता था, लेकिन आज ईक्यू, एसक्यू जैसे पैमाने आ गए हैं, जिसमें ईक्यू भावनात्मक बुद्धिमता से जुड़ा हुआ है। कभी उच्च आईक्यू को व्यक्ति की योग्यता व जीवन की सफलता से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन इसके आधार पर जब व्यक्तिगत जीवन में सफल व्यक्तियों को पारिवारिक, सामाजिकएवं सामूहिक स्तर पर प्राय: एक असफल जीवन जीते देखा गया तो, समझ आया कि आईक्यू पर्याप्त नहीं। इसके साथ भावनात्मक समझ से जुड़े ईक्यू की बात उठी। सन् 1950 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'इमोशनल इंटेलिजेंस:व्हाई इट केन मैटर मोर देन आईक्यू' में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन ने सबसे पहले इसकी पर्याप्त विस्तार से चर्चा की, हालांकि इस शब्द का सबसे पहले उपयोग यूनानी दार्शनिक अरस्तु को करने वाला माना जाता है।

डेनियल गोलमैन अरस्तू का दावा रहा कि व्यावहारिक जीवन की समग्र सफलता में 80 प्रतिशत से अधिक भावनात्मक बुद्धिमता की भूमिका रहती है, जबकि आईक्यू का महत्व 20 प्रतिशत से भी कम है साथ ही उनका यह भी मानना था कि महिलाओं में प्राय: भावनात्मक बुद्धिमता अधिक पाई जाती है और वर्तमान परिस्थितियों में भावनात्मक बुद्धिमता का महत्व बढ़ता जा रहा है। इस आधार पर भविष्य में अधिकांश उच्च पदों पर महिलाओं के पहुंचने की संभावनाएं बढ़ेंगी। डेनियल गोलमैन ईक्यू को 5 क्षमताओं का समूह मानते हैं, जिसके अंतर्गत सेल्फ अवेयरनैस अर्थात स्व जागरुकता, सेल्फ रेग्यूलेशन अर्थात आत्म-नियमन, सेल्फ मोटिवेशन अर्थात आत्म-अभिप्रेरणा, एम्पैथी अर्थात समानुभूति तथा सोशल स्किल्ज अर्थात सामाजिक दक्षताएं शामिल हैं। इस तरह भावनात्मक बुद्धिमता का अर्थ है, व्यक्ति का अपने तथा दूसरों के मनोभावों को समझना, उन पर नियंत्रण करना तथा अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु उनका सर्वोत्तम प्राप्त करना।

भावनात्मक बुद्धिमता के आधार पर ही व्यक्ति अपने गुणों को समझ व परिस्थितियों को पहचान आसानी से कर पाता है। इसके आधार पर व्यक्ति अपने बातचीत के ढंग, आचरण तथा संबंधों को मजबूत करने में सफल होता है। अपने आंतरिक संतुलन के साथ कार्यक्षेत्र में अंतर्संबंधों को बेहतर बनाने में ईक्यू महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह व्यक्ति अपने भाव संवेगों के प्रति संवेदनशील होता है, दूसरों के वाणी- व्यवहार के साथ उनकी दैहिक भाषा के माध्यम से भी समझने में सक्षम होता है। अपने संवेगों को अपने विचारों के साथ संबद्ध कर, उचित निर्णय के साथ समस्या के समाधान की ओर बढ़ता है। अपने संवेगों की प्रकृति व तीव्रता को समझते हुए नियंत्रित व्यवहार करता है, जिससे कि आपसी सामंजस्य के साथ शांति को प्राप्त हो सके।

भावनात्मक बुद्धिमता के साथ व्यक्ति अपना सटीक स्व-मूल्यांकन कर पाता है और भावनाओं को अभिव्यक्त करने में सक्षम होता है। यह उसके अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल को बेहतर बनाता है, जिससे आपसी संबंधों में उचित समझ, उदारता व सहिष्णुता का समावेश होता है ईक्यू एक प्रेरक व आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखने में सहायक रहता है और यह व्यक्ति व समूह की कार्यक्षमता की बढ़ोतरी करता है तथा नेतृत्वक्षमता के विकास व सशक्तिकरण में सहायक रहता है। इसके रहते विभिन्न प्रकार की प्रकृति के व्यक्तियों के बीच भी सामंजस्य को स्थापित करना संभव होता है तथा यह उचित व सही निर्णय लेने में सहायता करता है।

इस आधार पर जीवन के हर क्षेत्र में ईक्यू के महत्व को समझा जा सकता है। प्रशासन, नौकरशाही से लेकर सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में इसकी उपयोगिता को देखा जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य एवं संतुलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके साथ तनाव प्रबंधन प्रभावी ढंग से हो पाता है जिससे उच्च रक्तचाप, हृदयाघात, मधुमेह जैसे रोगों का खतरा कम हो जाता है।

अखंड ज्योति

आपके पत्र

भारत की जनसंख्या और विश्व-बाजार का संतुलन

भारत की वर्तमान में जनसंख्या भारी-भरकम देश चीन की जनसंख्या से भी ज्यादा हो गई है। यानी कुल मिलाकर एक अरब चालीस करोड़ आबादी वाले भारत में जनसंख्या के बोझ तले विकास और उन्नति बेहद धीमी और अविकसित है। विकसित तथा समृद्ध देश भारत की जनसंख्या में एक संभावना वाला उपभोक्ता बाजार तलाशते हैं और इसे बहुत बड़ी पूंजी भी मानकर अपनी उपभोक्ता सामग्री भारत में बेचने का प्रयास करते हैं। केवल बाजार में निवेश और बाजारी ताकत ही विकास का पैमाना नहीं हो सकती है। बहुत बड़ी जनसंख्या सीमित संसाधनों को नष्ट कर देती है और विकास की धार को कमजोर करने का काम करती है। यदि हम जनसंख्या पर नियंत्रण करते हैं तो देश में बिजली, पानी की कमी बढ़ती महंगाई, फैलती विनाशकारी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, अशिक्षा के फैलाव पर नियंत्रण, गरीब व्यक्ति को और गरीब होने से रोकने का प्रभावी तरीका तथा सांप्रदायिक दंगों पर रोक लगाई जा सकती है। कम और नियंत्रित जनसंख्या तेजी से विकास का पैमाना हो सकती है। 1951 से लेकर 81 तक भारत में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है और इसे जनसंख्या विस्फोट का भी नाम दिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं पर नजर रखने हेतु प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्तमान जनसंख्या का विशाल स्वरूप 1981 के बाद भारत में विशालतम हो गया है और आज की जो जनसंख्या का विस्फोट उसी की परिणति है। भारत में जनसंख्या बढ़ने का प्रमुख कारण अशिक्षा, अंधविश्वास और घटती मृत्यु दर भी है।

विकास के विभिन्न स्वरूपों को देखा जाए तो इसमें हम समावेशी विकास के रूप में देखकर आर्थिक विकास की उत्तर जनित राष्ट्रीय आय के विस्तृत नियोजन में समाज के सबसे गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को सही लाभ मिलने का नजरिया भी तलाशते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कर गरीबी को नीचे से ऊपर की ओर सुधारने का काम हमें करना होगा और इसके लिए यह जरूरी है की कमजोर और वंचित वर्गों जिनमें महिला, वृद्ध, एससी, एसटी, श्रमिक आदि शामिल हैं- को समुचित लाभ मिलना चाहिए। बच्चे आने वाले देश के नागरिकों के लिए उचित एवं आवश्यक शिक्षा की सुविधा मुहैया होनी चाहिए। वैसे जनसंख्या नियंत्रण ही विकास की समुचित धारा नहीं हो सकती हमें जनसंख्या के साथ सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा एवं सीमित संसाधनों के साथ तालमेल बिठाकर निरंतर आगे बढ़ना होगा लेकिन आवश्यकता संसाधनों के उचित दोहन नीतियों एवं कार्यक्रमों की है और आवश्यकता है नवाचार एवं उचित तकनीकी प्रौद्योगिकी की भी। वर्तमान में भारत विश्व में सबसे युवा आबादी वाला देश है। उसके विपरीत चीन और जापान में निरंतर जनसंख्या में वृद्धों का अनुपात बढ़ रहा है। इस तरह भारत में प्रचुर मानव संसाधन के स्रोत उपलब्ध हैं जिसका सही उपयोग करके भारत अपनी आर्थिक तथा सामरिक शक्ति को अत्यंत शक्तिशाली कर सकता है। इसके विपरीत भारत में विस्तृत रूप से गरीबी, बीमारियां, बेरोजगारी, जैसी विकराल समस्या में विद्यमान है। जबकि अन्य देश कम जनसंख्या के बावजूद विकास नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देशों में चीन और अमेरिका विकसित राष्ट्रों की कतार में हैं एवं विकास के शीर्ष पर हैं। भारत के पास सभी संसाधन और विकसित होने के सारे अवयव हैं इसके बावजूद भारत विज्ञान, टेक्नोलॉजी में काफी पीछे होकर अशिक्षा, अंधविश्वास ,कृषि कार्यों का निम्न स्तर आर्थिक असमानता की समस्याएं झेल रहा है।

सजीव ठाकुर

https://t.me/Allnewspaperpdf

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770 ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । शुक्रवार, 28 जून 2024

पार्टियों की बेचैनी

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर एक तरह की बेकरारी और बेचैनी दोनों ही खेमों में दिख रही है। यह बेवजह नहीं है। जिस तरह के हालात प्रदेश की राजनीति में पिछले करीब दो वर्षों से बने हुए हैं, वे इस राज्य के लिए सामान्य नहीं कहे जाएंगे।

पार्टियों में टूट-फूट | सबसे बड़ा मसला पार्टियों के टूटने का है। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद शिवसेना, NCP और कांग्रेस ने मिलकर जो सरकार बनाई थी, वह जून 2022 में शिवसेना में हुई टूट की वजह से गिर गई। फिर BJP और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सरकार बनाई। कुछ ही समय में NCP का भी एक धड़ा उस सरकार से जा मिला। राज्य के इतिहास में यह पहला मौका था, जब दो प्रमुख पार्टियां न केवल दोफाड़ हो गई बल्कि अलग हुए धड़ों को असली पार्टी की मान्यता भी मिल गई।

महाराष्ट्र: आगामी चुनाव पर नजर

सवाल विरासत का | इससे एक बड़ा सवाल यह उठा कि शरद पवार और ठाकरे परिवार की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी किसे माना जाए? प्रश्न यह भी था कि पार्टी और परिवार में हुई टूट-फूट स्वतःस्फूर्त थी या उसके पीछे किसी ताकत का हाथ था। लोकसभा चुनावों में भी, कम से कम महाराष्ट्र में इसी सवाल का जवाब खोजा जा रहा था। विधानसभा चुनाव भी इसी के इर्दगिर्द लड़े जाने के आसार हैं।

बढ़ा हुआ आत्मविश्वास | चूंकि लोकसभा चुनावों के नतीजे अलग हुए धड़ों के बजाय पारंपरिक नेतृत्व की तरफ झुके दिखाई दिए, इसलिए स्वाभाविक ही महाराष्ट्र विकास आघाडी के तीनों दलों- कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव) और NCP (शरद पवार)- का उत्साह बढ़ा हुआ है। 48 में से 30 लोकसभा सीटें जीतने के बाद MVA विधानसभा चुनावों में भी अपना हाथ ऊपर मानकर चल रहा है।

महायुति में अनिश्चितता | इसके बरक्स सत्तारूढ़ महायुति के दलों में थोड़ी अनिश्चितता दिखती है। विधायकों के टूटने संबंधी अटकलों और दावों को अभी छोड़ भी दिया जाए तो सीट बंटवारे से जुड़ी असहमतियां अलग-अलग रूपों में सामने आ रही हैं। अभी NCP (अजित पवार) के एक नेता ने कह दिया कि जिस तरह के दावे तीनों पक्षों की ओर से हो रहे हैं, उसमें लगता है कि बड़ी संख्या में लोगों को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ना पड़ेगा।

इंतजार करना होगा | बहरहाल, चुनावों से पहले का आत्मविश्वास और उससे पहले की चिंता में से क्या नुकसानदेह साबित होगा और किस चीज का फायदा मिल जाएगा, यह पहले से नहीं कहा जा सकता। लिहाजा, जो सवाल चुनाव से तय होने हैं, उनके लिए चुनाव नतीजों का ही इंतजार करना होगा।

रोज़-ब-रोज़

दादी ने मानी गलती

शैलेंद्र पांडेय

बच्ची की शिकायत बंद ही नहीं हो रही थी। वह बहुत गंभीर थी अपनी बात को लेकर और चाहती थी कि उसकी दादी भी उसे उतनी ही गंभीरता से लें। लेकिन, दिक्कत यह थी कि वह बच्ची जितना ही शिकायत करती, उसकी दादी उस पर दुलार में उतना ही न्योछावर होती जातीं। 'अब नहीं करूंगी, कह दिया न।' दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्ची को मुस्कान नहीं चाहिए थी। उसे लग रहा था कि गलती करने के बाद भी दादी हंस रही हैं, इसका मतलब वह आगे फिर गलती करेंगी। 'नहीं-नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपने गिलास फेंका ही क्यों? अपने पास रख लेतीं?' अपनी बातों में और वजन डालने और यह दिखाने के लिए कि बहुत ज्यादा नाराज है, वह दोनों हाथ बांधकर बैठ गई। दादी को लग गया कि मामला गंभीर हो रहा है। अगर अभी सुलह नहीं की, तो फिर शांति समझौते की कीमत ज्यादा चुकानी पड़ जाएगी। उन्होंने एक नजर ई-रिक्शे पर बैठे बाकी लोगों पर डाली, फिर अपनी पोती की ओर देखते हुए दोनों हाथों से कान पकड़ कर कहा, 'सॉरी, अब से नहीं करूंगी।' इस बार मुस्कान बच्ची के चेहरे पर आई, वह जीत चुकी थी। उसकी जीत इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि बगल में बैठी एक सवारी ने अपने प्लास्टिक के गिलास को तुड़-मुड़ करके मुट्ठी में बंद कर लिया था। उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि 8-9 साल की उस बच्ची के सामने गिलास को सड़क पर फेंक सके। दादी-पोती के बीच सारी मान-मनुहार इसी बात को लेकर तो थी कि दादी ने शरबत पीने के बाद गिलास को सड़क पर क्यों फेंक दिया। छबील लगाने वालों ने शरबत पिलाया, तो इसका क्या मतलब कि खाली गिलास को सड़क पर फेंक देंगे। दादी ने एक बार सफाई पेश करने की कोशिश भी की, 'सारे ही लोग सड़क पर फेंक रहे हैं। छबील खत्म होने के बाद झाड़ू लगाई जाएगी। सफाई हो जाएगी यहां।' लेकिन, बच्ची का सवाल कायम था कि गंदगी फैलानी ही क्यों। उसने अपने गिलास को हाथ में पकड़ा हुआ था कि डस्टबिन में ही डालूंगी। उस बच्ची के साथ का सफर बहुत छोटा रहा, रामफल चौक से बस पालम मेट्रो स्टेशन तक। लेकिन, इतने में ही उसने एक बड़ा सबक दे दिया उन सभी लोगों के लिए जो सड़कों पर कूड़ा यूं गुमान से उछालते हैं गोया ओलिंपिक्स में गोल्ड मेडल के लिए गोला फेंक रहे हों। उस बच्ची का सवाल ऐसे सारे लोगों के लिए है, 'कूड़ा बाहर क्यों फेंका?' दादी का हाथ पकड़ कर मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियां उतरती उस बच्ची को देख यकीन हो गया कि इसके आसपास रहने वाला कोई शख्स अपने आस-पड़ोस को गंदा करने की हिमाकत नहीं कर सकता। काश, हम सभी को अपने-अपने सफर में ऐसा कोई एक यात्री मिल जाए!

एकदा

नेहरू की परंपरा

आजादी से पहले देश में अंतरिम सरकार थी। तब स्पीकर के पद पर जीवी मावलंकर को चुना गया। जब 1952 में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, तब संविधान के अंगीकार होने के बाद भी स्पीकर के पद पर जीवी मावलंकर को ही चुना गया। डेप्युटी स्पीकर बने एमए अयंगर। लेकिन कार्यकाल के बीच में ही जीवी मावलंकर का देहावसान हो गया। तब स्पीकर के पद पर तत्कालीन डेप्युटी स्पीकर एमए अयंगर का चुनाव हो गया। अब खाली था डेप्युटी स्पीकर का पद। कांग्रेस पार्टी में सब तरफ होड़ मची थी कौन डेप्युटी स्पीकर

Subrata Dhar

बनेगा। एक से एक नाम चल रहे थे। पं. जवाहरलाल नेहरू के पास, तो राजाजी के पास तो कभी दूसरे बड़े कांग्रेस लीडर्स के पास इसके लिए नामों की लाइन लगी हुई थी। लेकिन पं. जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की मीटिंग में एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी। उनका लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए ताकतवर विपक्ष होने पर अटूट भरोसा था। वह चाहते थे कि विपक्ष सत्ता पर अंकुश लगाए रखे, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि डेप्युटी स्पीकर विपक्ष को दिया जाए। केवल दो सदस्यों वाले अकाली दल के सांसद सरदार हुकुम सिंह को डेप्युटी स्पीकर का पद दिया गया। जबकि उस समय कांग्रेस के पास 489 सीटों में 364 सीटों का प्रचंड बहुमत था। पं. जवाहरलाल नेहरू ने उस रोज देश को एक नई परंपरा भी दी और यह भी बता दिया कि जनता के लिए ताकतवर विपक्ष ही उसका हितैषी होना है। जो विपक्ष को सम्मान देगा, वह वास्तव में जनता को सम्मान देगा। लोकतंत्र में मतभिन्नता उसका एक अहम हिस्सा है। पं. नेहरू की शुरू की हुई यह परंपरा बहुत वर्षों तक जारी रही और विपक्ष को डेप्युटी स्पीकर का पद दिया जाता रहा।

संकलन : **हफीज किदवई**

लोकसभा चुनाव नतीजों से उपजी निराशा में कई लोग सरकार की उपलब्धियों को अनदेखा कर रहे हैं

नाराज़ हों, मगर सरकार का काम भी देखें

अवधेश कुमार

इन दिनों BJP लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पर लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान है। इन दो राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाओं के बिल्कुल उलट रहा है, जिससे BJP हिल गई है। पार्टी को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी और निराशा उसके अपने कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और प्रतिबद्ध समर्थक प्रकट कर रहे हैं।

जायज शिकायतें | इन्हें या इनके जैसे लोगों को अनदेखा किया जाना, उम्मीदवारों का उनकी कसौटी पर सही नहीं होना और केन्द्र व प्रदेशों में उच्च पदों पर बैठे अनेक लोगों का सही व्यवहार न होना, जैसी शिकायतों को स्वीकार करने में समस्या नहीं है। किंतु इनमें ज्यादातर लोग हिंदुत्व, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, इतिहास, सामाजिक न्याय आदि के आधार पर अपने विचार और व्यवहार निर्धारित करते हैं।

काम करने वाली सरकार | भावावेश में ये लोग इस सच को नजरअंदाज कर रहे हैं कि इन मसलों पर स्वतंत्रता के बाद किसी सरकार ने काम किया है तो वह नरेंद्र मोदी सरकार ही है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मायने में राजनीति में आज तक के सबसे प्रखर, मुखर और निर्णय लेने वाले नेता बन चुके हैं। 2019 में अमित शाह द्वारा गृह मंत्रालय संभालने के बाद हिंदुत्व और भारतीयत्व से जुड़े मसलों पर सरकार ज्यादा दृढ़ हुई है।

तुलनात्मक नजरिया | समर्थकों की अपेक्षाएं से अलग हटकर इस नेतृत्व की दूसरे दलों और नेताओं से तुलना करें तो तस्वीर साफ हो जाएगी। निस्संदेह, BJP के संगठन और सत्ता को लेकर सोच, आचार और व्यवहार में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है और यह आसानी से नहीं हो सकता। राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर ऐसी समितियां बनें जो स्थानीय कार्यकर्ताओं, नेताओं, समर्थकों से बातचीत कर तथ्य इकट्ठा करें और उनके अनुसार तात्कालिक और दूरगामी दृष्टि से जो भी जरूरी हों, वे बदलाव किए जाएं।

बड़ी लकीर खींची है मौजूदा नेतृत्व ने

- 370, तीन तलाक जैसे साहसिक कदम
- दुनिया देख रही एक बदला हुआ भारत
- एक स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति

वामपंथी नैरेटिव कायम | सच यह भी है कि मंत्रालयों को छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा सरकार से जुड़ी हुई संस्थाओं में ज्यादातर अपनी भूमिकाओं पर लचर साबित हुई हैं। शिक्षा, इतिहास, संस्कृति, कला ,साहित्य, समाज विज्ञान आदि से जुड़ी संस्थाओं ने वाकई 10 वर्षों में ऐसे रेखांकित करने वाले काम नहीं किए, जिससे आरोपित विकृत वामपंथी सिद्धांत, धारणाएं और नैरेटिव ध्वस्त हो सकें। सरकारी विभागों की तो छोड़िए विश्वविद्यालयों आदि के संरचनात्मक ढांचे में भी बदलाव नहीं हुए।

अभूतपूर्व कदम | दूसरी ओर यह भी सच है नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के दूरगामी भविष्य का ध्यान रखते हुए ऐसे कार्य किए जिनकी कल्पना पहले नहीं की गई थी। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति, नागरिकता संशोधन कानून, एक साथ तीन तलाक के विरुद्ध कानून, BJP की राज्य सरकारों द्वारा गोहत्या निषेध की कानूनी व्यवस्था, आतंकवादी हमले के विरुद्ध पाकिस्तान सीमा के अंदर कार्रवाई, भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुरूप G20 और ऐसे कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन, विदेश यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतवंशियों के बीच कार्यक्रमों और संबोधनों से भारत, भारतीय सभ्यता-संस्कृति और हिंदुत्व को लेकर फैलाया गया गर्व भाव, हिंदुओं के आस्था केन्द्रों का भव्य पुनर्निर्माण जैसे कार्य विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए संतोष के विषय होने चाहिए।

बदला हुआ भारत | सच यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेतृत्व संभालने के साथ पिछले 10 वर्षों में हमें एक बदला हुआ भारत दिखता है। आज अमेरिका सहित विश्व के कई प्रमुख देश आरोप लगा रहे हैं कि भारत उनकी धरती पर हत्याएं करवा रहा है। पाकिस्तान में मारे जाने वाले भारत विरोधी वांछित आतंकवादियों की संख्या दो दर्जन से ज्यादा हो चुकी है। यह कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है इस पर प्रमाणित तथ्य देना कठिन है, किंतु पूर्व में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।

राष्ट्रहित सबसे ऊपर | अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक ऐसे नए मुखर भारत का उदय हुआ है जो अपने राष्ट्रीय हित पर केंद्रित विचार से निर्णय करते समय यह नहीं सोचता कि कौन देश इससे नाराज होगा और कौन खुश। एक समय निर्गुट आंदोलन के नाम से अवश्य वैश्विक संगठन चला लेकिन निर्गुटता का साकार रूप हमने नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान ही देखा है। आज भारत किसी के गुट में नहीं लेकिन किसी के विरुद्ध भी नहीं। सबसे बड़ी बात कि भारत को भारत के रूप में जानने और उसी तरह से व्यवहार करने की सोच विश्व समुदाय के अंदर गहरी हुई है और यह असाधारण बदलाव है।

विरोधियों का अजेंडा | इसी कारण दुनिया के अनेक सरकारी गैर सरकारी शक्तियां नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हें सत्ता से बाहर करने की कोशिशों में भी लगी हुई हैं। इसलिए BJP और सरकार के चेहरे चरित्र और चाल में बदलाव के लिए आवाज उठे यह तो ठीक है, लेकिन इससे जुड़े दूसरे पहलुओं का ध्यान रखना भी जरूरी है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और विचारक हैं)

बिहार में नया कोटा कानून खारिज, आगे क्या

विराग गुप्ता

संसद का सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र में शिक्षा और रोजगार से जुड़े NEET, Net, अग्निवीर और आरक्षण के मामले पर सबसे ज्यादा शोर हो सकता है। वहीं, चुनाव बाद पिछले दिनों आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसने गर्मी और बढ़ा दी है।

खारिज का आधार | नवंबर 2023 में बिहार विधानसभा ने 65% आरक्षण के लिए कानून बनाया था। उसमें 10% EWS जोड़ने से कुल 75% आरक्षण हो गया। 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की थी। उसके बाद इस मामले में कई फैसले आए। उनके अनुसार, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया।

सीमा के पार | विधानसभा और लोकसभा में वंचित वर्ग के लिए संविधान में अल्पकालिक आरक्षण का प्रावधान था। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अपवाद स्वरूप आरक्षण की व्यवस्था थी। SC/ST के लिए 22.5% आरक्षण के बाद मंडल कमिशन से OBC के लिए 27% आरक्षण लागू हुआ। 2019 में EWS के लिए 10% आरक्षण से अधिकतम 50% सीमा का उल्लंघन होता है, लेकिन सरकार उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। EWS के लिए 8 लाख रुपये से कम की आमदनी के मापदंड की वजह से 95% से ज्यादा आबादी आरक्षण के दायरे में आ गई है। EWS के आर्थिक मापदंड के बाद अन्य आरक्षित वर्गों के लिए केंद्रीय स्तर पर क्रीमीलेयर का नए सिरे से निर्धारण करने की जरूरत है।

वैचारिक मतभेद | EWS के दायरे में मुस्लिम समुदाय के लोग भी आते हैं। लेकिन ईसाई या मुस्लिम धर्म में शामिल होने के बाद SC/ST के लोगों को आरक्षण की सहूलियत नहीं मिलती। धार्मिक अल्पसंख्यकों के आरक्षण के बारे में BJP का TDP और JDU के साथ वैचारिक मतभेद है। इस बार लोकसभा के चुनावों के पहले आनन-फानन में महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन कानून पारित कर दिया गया। लेकिन उसे लागू करने के लिए निश्चित समयसीमा और तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। वहीं सरकारी नौकरियों के बीच संविदा के पदों पर भी आरक्षण लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है।

AI Image

कॉमन रूम

जातिगत जनगणना | इस बारे में सियासत के अखाड़े में उठापटक के साथ अदालतों में बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी चल रही है। कई राज्यों में माटीपुत्रों के लिए और निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के मनमाफिक प्रयोग हो रहे हैं। ज्योतिबा फुले ने जाति के आधार पर आरक्षण की संकल्पना की थी। लेकिन संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। जाति के आधार पर आरक्षण को सरकार, संसद और सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। इसलिए जातिगत जनगणना करवाना विकल्प नहीं, बल्कि संवैधानिक बाध्यता है।

9वीं अनुसूची | हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव जल्द होने हैं। वहां भी OBC के आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए कई जातियां और वर्ग आंदोलनरत हैं। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला आना तय है। जयललिता सरकार के दबाव पर कांग्रेस की नरसिंह राव सरकार ने 76वें संशोधन से तमिलनाडु के आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया था। नीतीश सरकार बिहार में आरक्षण की लिमिट बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से ऐसे ही संविधान संशोधन की मांग कर सकती है।

सचाई और खतरा | अनेक राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण एक सचाई है। संसद से संविधान संशोधन की पहल हुई तो अदालतों में मुकदमेबाजी के नए दौर की शुरुआत हो सकती है। केंद्रीय कानून नहीं बनने और राज्यों में मनमाफिक आरक्षण से अराजकता और मुकदमेबाजी बढ़ना संविधान के लिए ज्यादा बड़े खतरे की बात है।

(लेखक सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं)

विशुद्ध राजनीति
पॉलिटॉक

जगन की दुविधा

आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी अपने अगले कदम को लेकर बहुत उलझन में हैं। उनकी पार्टी YSR कांग्रेस के लिए आगे का रास्ता बहुत आसान नहीं दिख रहा। पिछले 10 बरसों से पार्टी ने केंद्र में नरेंद्र मोदी की

अगुवाई वाली BJP सरकार को हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन इस बार उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी TDP केंद्र में BJP के साथ सरकार में है। ऐसे में अब केंद्र में भी सीधा सपोर्ट करना आसान नहीं होगा। और अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनके कुछ राज्यसभा सांसद आगे क्या करेंगे, इसे लेकर पार्टी आश्वस्त नहीं है। उनके कुछ पार्टी सांसद BJP के संपर्क में बताए जा रहे हैं। साथ ही, पार्टी बहुत दिनों तक बिना स्टैंड लिए राज्य में बैठ भी नहीं सकती, क्योंकि वहां अब कांग्रेस भी जगन की बहन वाईएस शर्मिला के नेतृत्व में आक्रामक रूप से खुद को विकल्प के रूप में पेश कर रही है। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच वहां से एक और दिलचस्प खबर आई कि जगन भी अब कांग्रेस के कुछ नेताओं के संपर्क में हैं। यहां तक चर्चा उठी कि वह अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस और YSR कांग्रेस, दोनों दलों ने इस खबर का खंडन किया। लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों ने बता दिया कि जगन आज किस तरह आंध्र प्रदेश में राजनीतिक चौराहे पर खड़े हैं और अगले कुछ दिनों में उन्हें अपनी दिशा तय करनी होगी।

बिहार में कब होगा चुनाव

JDU ने केंद्र में BJP की अगुवाई वाली NDA सरकार में अपने लिए हिस्सेदारी की कोई शर्त नहीं रखी। तभी से इस बात को लेकर राज्य में चर्चा है कि पार्टी को BJP से क्या चाहिए? JDU के नेता दावा कर रहे हैं कि अभी उनके लिए सबसे पहला काम राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करना है। इसके लिए JDU राज्य में जल्द चुनाव चाहती है। JDU नेता बताते हैं कि वे BJP से इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव कराने का आग्रह करेंगे, जब

महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके पीछे JDU का सियासी आकलन है कि उन्हें राज्य में सीटों कीबारगेनिंग में भी मदद मिलेगी। JDU राज्य में कह रही है कि इस लोकसभा चुनाव में BJP से बेहतर स्ट्राइक रेट उसका रहा है। पार्टी ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 पर जीत दर्ज की। वहीं, BJP ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 जीती। दरअसल 2020 विधानसभा चुनाव में JDU का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। तब वह RJD और BJP के मुकाबले बहुत पीछे, तीसरे नंबर पर रह गई थी।

बजट को लेकर मंथन

नई केंद्र सरकार का पहला बजट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आम चुनाव के नतीजे के बाद BJP बहत सतर्क है, खासकर मिडिल क्लास तबके से। पिछले 10 बरसों में BJP के नैरेटिव को सपोर्ट करने में सबसे बड़ा योगदान मिडिल क्लास का रहा है। लेकिन यह वर्ग सरकार से अधिक राहत नहीं मिलने की शिकायत भी करता रहा है। ऐसे में विपक्ष के मजबूत होने के बाद BJP इस वर्ग को किसी तरह से निराश नहीं कर सकती। इसी वजह से माना जा रहा है कि इस बार बजट में इस वर्ग को और निराश नहीं किया जाएगा। संघ का भी यही मानना है कि इस बार अगर शहरी तबके को कुछ भी न दिया गया तो वहां से भी प्रतिरोध आ सकता है।

पीएम की नाराज़गी

NEET परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासे नाराज बताए गए। खासकर अधिकारियों के रवैये को लेकर वह बेहद खफा बताए जा रहे हैं। उन्होंने जब फीडबैक लिया तो अंदाजा लगा कि अधिकारी इस मामले को बेहतर संवेदनशील तरीके से निपट सकते थे, लेकिन उन लोगों ने चीजें हाथ से निकल जाने दीं। यह फीडबैक भी मिला कि कई सूचनाएं दबाने की कोशिश की

गईं। इसके बाद मोदी ने PMO में अपने विश्वस्त अधिकारियों से कोर्स करेक्शन करने को कहा। तभी NTA में PMO के करीबी अधिकारी को नियुक्त किया गया है। संकेत मिल रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में वहां और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल सरकार का पूरा ध्यान मौजूदा NEET विवाद को सुलझाने पर लगा हुआ है।

राहुल-खरगे का सख्त संदेश

आम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद अब कांग्रेस का सारा फोकस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। लेकिन पार्टी की चिंता खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा में गुटबाजी को लेकर है। इसके लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी सख्त मोड में हैं। इसी हफ्ते उन्होंने दोनों राज्यों के पदाधिकारियों की मीटिंग की।

इसके जरिए साफ संदेश दिया गया कि महाराष्ट्र में चुनाव महाविकास अघाड़ी के समूह के तौर पर ही लड़ा जाएगा। यह भी पूरी सख्ती के साथ स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य में कोई भी उद्धव ठाकरे या शरद पवार के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा। दरअसल आम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उद्धव ठाकरे की पार्टी पर प्रतिकूल टिप्पणी की थी। राहुल-खरगे ने हरियाणा में भी गुटबाजी दूर करने को कहा। दोनों राज्यों की मीटिंग में जब कांग्रेस के नेताओं ने गुटबाजी या बयानबाजी की बात से इनकार किया तो राहुल गांधी और खरगे ने उन राज्यों के नेताओं को पूरी लिस्ट दिखा दी जो पिछले कुछ दिनों से वहां गुटबाजी में लगे हैं। इन नेताओं से दो टूक कहा गया कि पार्टी ऐसी चीजों को अब बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेगी, भले इससे एक-दो नेताओं को बुरा लगे और वे पार्टी छोड़कर चले जाएं।

मत-सम्मत

www.edit.nbt.in

विषय: पेपर लीक विवाद पर आपका क्या कहना है?

■ सवालों के घेरे में सिस्टम

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब तक 11 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई को पता चला है कि अभिभावकों ने 40 लाख रुपये में पेपर खरीदा है। 26 अभ्यर्थियों के लिए प्ले स्कूल मनीष ने बुक कराया था, जहां प्रश्नपत्र के जवाब रटाए गए। यह गैंग बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, प्रयागराज, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में सक्रिय है। इस मामले की निष्पक्ष व पारदर्शी जांच होनी चाहिए। कड़े कानून बनाकर दोषियों और भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए।

-डॉ. मंजु गुप्ता (नवी मुंबई), ईमेल से

■ गलती दोहराई न जाए

नीट और यूजीसी-नेट सहित एक के बाद एक महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक होने से स्टूडेंट्स के भविष्य और आकांक्षाओं पर कोहरा छा गया है। यह परीक्षा तंत्र की नाकामी पर भी सवाल है। विपक्ष इस मुद्दे पर आक्रामक है। शिक्षा मंत्रालय ने उच्चस्तरीय कमिटी बनाकर परीक्षा प्रणाली में सुधार की ओर पहला कदम तो बढ़ाया है, लेकिन धीमी रफ्तार को देखकर लगता है कि लाखों बच्चों का कीमती सत्र कहीं अधर में न लटक जाए। सीबीआई ने विभिन्न राज्यों से इसमें संलिप्त दोषियों की धर-पकड़ शुरू कर दी है, लेकिन कहीं छोटी मछली को पकड़ने में बड़ी मछली बच कर न निकल जाए। इसका भी ख्याल रखना चाहिए।

-दीपा सिन्हा (मुंबई), ईमेल से

■ ये जो सपनों के सौदागर हैं...

उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का प्रथम सोपान है शिक्षा। हर अभिभावक की इच्छा होती है कि उसकी अगली पीढ़ी उससे भी अधिक शिक्षित हो। इसी प्रबल इच्छा के तहत वो तन-मन और धन से बच्चों की शिक्षा पर जोर देता है। लाखों बच्चे परिजन के सपने और खुद के उज्जवल भविष्य के निर्माण में पूरी शक्ति लगा देते है। यहां तक तो सब सही है, लेकिन इन सपनों को पूरा करनेवाले जो सपनों के सौदागर बैठे हैं, वो चंद पैसों की खातिर इनके भविष्य को अंधकारमय करने में कोई संकोच नहीं करते। कुछ भ्रष्ट लोग धनाढ्य वर्ग के बच्चों की थाली में खुलेआम गरीबों और मेहनतकश बच्चों का सपना परोस दे रहे हैं। यह कितना अन्याय है देश के लाखों मेहनती युवाओं के साथ? शिक्षा के क्षेत्र में यह खिलवाड़ देश को कितना महंगा पड़ सकता है, यह सोचने की बात है।

-लक्ष्मी यादव (डोंबिवली), ईमेल से

अगली बार का विषय: 10 साल बाद सदन में मजबूत विपक्ष को लेकर आपका क्या कहना है?

mat.nbt@gmail.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

प्रेम के बगैर हमें जीवन का सच्चा अर्थ नहीं मिलता

अमित वर्मा

प्रेम एक ऐसा अशांत सागर है, जिसकी सतह पर सुंदर तरंगें तो उठती हैं, मगर इसके अंदर अथाह गहराई छुपी रहती है। प्रेम की खोज अपने अंदर की उस अथाह गहराई में उतरने की यात्रा है, जहां 'मैं' का अस्तित्व धुंधला पड़ जाता है, और केवल 'हम' का अहसास बाकी बचता है। प्रेम हमें अपनी सीमाओं से तो परिचित कराता ही है, यह हमें अनंत संभावनाओं की ओर भी लेकर जाता है।

प्रेम को शब्दों में बांधना नामुमकिन है। यह एक अनुभव है, एक भावना है, एक शक्ति है जो हमारी आत्मा को छूती है। प्रेम के लिए न तो कोई परिभाषा है, न कोई सीमा है। यह हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग है। माता-पिता का अपने बच्चों के लिए प्रेम, प्रेमी-प्रेमिका का एक-दूसरे के लिए प्रेम, मित्रों का आपसी प्रेम, ईश्वर के लिए भक्ति का प्रेम। हर तरह का प्रेम अपनी अनोखी सुंदरता और अर्थ ले कर आता है।

प्रेम हमें अपनी आराम से भरी मानसिकता से बाहर निकालता है और हमें अपना अहंकार छोड़ने के लिए कहता है। यह हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ता है, हमें अपने भीतर की गहराई की थाह देता है। यह हमारी सीमाओं को तोड़कर हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है। यह रास्ता आसान नहीं होता। बल्कि प्रेम का मार्ग कांटों से भरा होता है। इसमें दर्द, निराशा, धोखा और अस्वीकृति खूब होती है। इसकी पीड़ा भी बेहद गहरी होती है। इसके बावजूद, प्रेम हमें जिंदगी से जोड़ता है, हमें अंदर की ताकत का अहसास कराता है। हम जो हैं, हमें उससे कहीं ज्यादा बेहतर बनाता है प्रेम।

प्रेम करो क्योंकि यह संसार प्रेम ही के आधार पर टिका है। अगर प्रेम न होता तो यह संसार न होता। बिना प्रेम के जीवन नीरस है। इस संसार में जो कुछ है वह प्रेम का ही जहूर है। आग प्रेम की जलन है। जल प्रेम की गति है। मिट्टी प्रेम का ठहराव है और वायु प्रेम की बेकली है। रात प्रेम की नींद है और दिन प्रेम का नींद से जागना। भलाई प्रेम से करीब होना है और पाप प्रेम से दूर होना है। स्वर्ग प्रेम की चाह है। प्रेम ईश्वर को पाने की की चाह में स्वयं को भुला देना है तो ईश्वर से फिर एक लगाव का अनुभव भी करना है।

प्रेम में एक अद्भुत विरोधाभास है। प्रेम हमें खुशी और दुख दोनों ही दे सकता है। प्रेम हमें संतोष और अशांति दोनों ही दे सकता है। प्रेम हमें जीवन से जोड़ सकता है तो उससे अलग भी कर सकता है। प्रेम में ही हम जीवन के सच्चे अर्थ को खोज सकते हैं, प्रेम में ही हम खुद को पा सकते हैं। प्रेम एक अथाह गहराई है, जिसमें हम खो सकते हैं, और खुद को पा भी सकते हैं। यह एक अनुभव है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलकर हमें नई नजर देता है, हमें नया इंसान बनाता है।

प्रेम एक शून्य है, जो हमें एक नए अस्तित्व में ले जाता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारे आप से तो जोड़ता ही है, उस अनंत शक्ति से भी जोड़ता है जो सृष्टि को जोड़ती है। प्रेम को समझना आसान नहीं है, लेकिन उसकी खोज एक अद्भुत यात्रा है। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा विकसित होती रहती है, हमेशा नई ऊंचाइयों पर पहुंचती रहती है।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः(022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अनमोल वचन

जिंदगी तो कुल एक पीढ़ी भर की होती है, पर नेक काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है।
-जापानी कहावत

राहुल की दोहरी भूमिका

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 18वीं लोक सभा में विपक्ष के नेता हो गए हैं। वह करीब दो दशक से सक्रिय राजनीति में हैं। पहली बार उन्हें संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिला है। राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। वह आजादी की विरासत वाली राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष जैसा महत्त्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं, लेकिन 2019 के लोक सभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद उन्होंने इस पद को त्याग दिया था। इसके बाद से उन्होंने पार्टी के किसी भी पद को संभालने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। कहा जा रहा है कि विपक्ष का नेता पद संभालने के लिए वह तैयार नहीं थे। लेकिन अंततः पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के दबाव में

उन्हें यह पद स्वीकारना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद राहुल के बारे में बनाई गई यह धारणा टूट गई कि वह बड़ी जिम्मेदारी को संभालने से डरते हैं। राहुल ने नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अपने पहले संबोधन में ही संकेत दे दिया कि भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को संसद से सड़क तक विपक्ष की कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। राहुल ने ओम बिरला को दूसरी बार लोक सभा अध्यक्ष चुने जाने पर कहा कि निस्संदेह सरकार के पास राजनीतिक सत्ता की शक्ति है लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। राजनीति में राहुल 'एंगरी यंगमैन' की भूमिका का निवर्हन करते दिखाई देते हैं। नेता प्रतिपक्ष सीबीआई निदेशक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आदि को चुनने वाली समितियों का हिस्सा होता है। राहुल के आक्रामक तेवरों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इन नियुक्तियों में प्रधानमंत्री मोदी को राहुल के साथ तालमेल बैठाने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राहुल ने हाल के दिनों में कुछ काम ऐसे किए हैं। देश में हजारों किलोमीटर की पदयात्राएं कीं और इस दौरान जनता के साथ सीधे संवाद कायम किया। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी को सदन में विपक्षी नेता के साथ-साथ विपक्षी दलों के गठबंधन को एकजुट रखने की जिम्मेदारी का निवर्हन भी करना है। अपेक्षा की जाती है कि वह इस दोहरी भूमिका का सही से निवर्हन करेंगे। सदन में सरकार के साथ सार्थक संवाद होगा और हर बात पर सदन का बहिष्कार करने के चलन पर रोक लगेगी।

सुधरते कानून

पहली जुलाई से नये आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 देशवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं। पिछले साल पारित ये नये कानून ब्रिटिशकाल के क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। इन नये कानूनों के तहत कोई भी नागरिक अब पुलिस थाने जाए बिना ही इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। जीरो प्राथमिकी से वह किसी भी थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। मामले और जांच को मजबूत करने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों का गंभीर अपराधों के लिए

घटना स्थल पर जाना और सबूत एकत्र करना अनिवार्य कर दिया गया है जिसकी वीडियोग्राफी भी करानी होगी। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता देनी होगी। यह जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी। नये कानूनों के तहत नब्बे दिन के भीतर मामले की प्रगति पर जानकारी पाने का अधिकार होगा। कानूनों को नागरिकों के हित में सख्त और सुविधाजनक बनाना सरकार की जिम्मेदारी का अहम हिस्सा है। कहा जा सकता है कि पुराने कानूनों को नया शीर्षक देने भर से सुधार संभव नहीं हो सकते। ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने और इलेक्ट्रॉनिक समन भेजने जैसे कदम वक्त की जरूरत और सुविधाजनक व्यवस्था हैं। इससे पुलिस द्वारा की जाने वाली हीला-हवाली रोकी जा सकेगी। साथ ही, विभिन्न गंभीर मसलों में समन लेने से मुकरने या फरार फिरने वालों का बच निकलना मुश्किल होगा। कहना वाजिब है कि पुलिस रिफॉर्म्स के बगैर यह सब संभव नहीं है। पुलिस बल को आवश्यक संख्या के अनुरूप बढ़ाना होगा। साथ ही, थानों और पुलिस चौकियों को पर्याप्त सुविधाएं भी मुहैया करानी होंगी। उनके पास कंप्यूटर हों, बिजली की निर्बाध सुविधा हो तथा हर वक्त नेट का कनेक्शन भी हो। अभी तो हालत यह है कि कई जगह थानों/चौकियों में कुर्सी, पानी और पंखा तक नहीं है। किसी भी व्यवस्था को लागू करते हुए उसे समग्रता में देखना होगा। राज्य सरकारों को भी इन्हें लागू करने के प्रति जिम्मेदाराना रवैया अपनाना होगा।

समाज/अखिलेश आर्येन्दु

परिवार बचाना बड़ी जिम्मेदारी

भारतीय हिन्दू संयुक्त परिवार का आदर्श उस मानवीय संवेदना से जुड़ता है, जो सारे संसार को अपना परिवार मानती है। पिछले पांच हजार वर्षों में भारतीय परिवार की पहचान उसके जरिए कमाए गए धन, पद, संपत्ति से नहीं रही है, बल्कि उनमें निहित मूल्यों, विश्वासों, नियमों और संकल्पनाओं से रही है। यहां तक कि राजतंत्र में भी परिवारों का महत्त्व उसी तरह बना रहा जैसे आज लोकतंत्र में। व्यक्ति परिवार की इकाई होता है। इसलिए व्यक्तियों का आपसी रिश्ता और व्यवहार बेहतर होना जरूरी है।

आजादी के बाद नये तरह के विकास के साथ तमाम तरह के बदलाव हुए और उनमें परिवार की बनावट, क्षमता और नियमों में ही बदलाव नहीं आया, बल्कि उनमें निहित मूल्य, विश्वासों और संकल्पनाओं में भी बदलाव हुआ। संयुक्त परिवार बिखरने लगे। इनके बिखरने की वजह गृह कलह, पति-पत्नी के झगड़े, गरीबी, बढ़ता उपभोक्तावाद, जिसने व्यक्ति को अति महत्त्वाकांक्षी बना दिया, रहे। संसाधनों की चाहत ने व्यक्ति में सहनशक्ति खत्म हुई और स्वार्थपरता लगातार बढ़ती गई। भारतीय हिन्दुओं के संयुक्त परिवारों में टूटन सबसे ज्यादा हुई। उसका असर बहुत गहरे तक हुआ। धर्म के प्रति आस्था कम हुई। सोच में अंतर लगातार बढ़ते जाना भी परिवारों में टूटने की वजह बन रहा है।

भारत में आज यदि सबसे ज्यादा किसी संस्था पर खतरा मडरा रहा है, तो संयुक्त परिवार नामक संस्था पर। संयुक्त परिवारों के लगातार टूटने से समाज के रिश्तों की अहमियत पर ही असर नहीं पड़ा है, बल्कि भारतीय समाज के मूल्य, नियम, आचार, व्यवहार ओर पहचान पर भी असर पड़ा है। बड़े-बूढ़ों की समाज में अहमियत और सम्मान की वजह संयुक्त परिवार की बनावट, मूल्य और आपसी विश्वास से जुड़ती थी। अब यह अटूट जुड़ाव ही ढीला होने लगा है। भारतीय समाज के परिवारों की स्थिति महज उनकी बनावट, बसावट और वित्तीय हालात पर ही निर्भर नहीं रही है, बल्कि परिवार में लोगों की आपसी समरता रही है। संयुक्त परिवार का मॉडल के कमजोर होने की वजह से कई तरह की समस्याएं गांवों में पैदा हुई हैं। इसलिए समाज सुधार के लिए काम करने वाली संस्थाओं को फिर से और नये सिरे अधिक सक्रिय होने की जरूरत है। इससे खेती ही नहीं बचेगी, बल्कि संयुक्त परिवार और गांव भी टूटने से बच सकेंगे।

चिंता से आगे की बात

जल संकट

प्रेम प्रकाश

ग्लोबल वार्मिंग के साथ जल संकट का मसला अब चिंता से ज्यादा हकीकत है। इस बारे में आज कोई एक देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया चिंतित है। बात करें भारत की तो एक ही समय में भयावह बाढ़ और बूंद-बूंद पानी के लिए हाहाकर देश के अलग-अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। पानी को लेकर भारत के लिए स्थिति इसलिए भी गंभीर है कि विश्व जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी 18 फीसद है, जबकि वैश्विक अनुपात की दृष्टि से पीने योग्य स्वच्छ जल के चार फीसद संसाधन ही यहां उपलब्ध हैं। हम अकेले इतना ज्यादा भूजल दोहन करते हैं, जितना अमेरिका और चीन मिल कर करते हैं।

बात कृषि की करें तो भूजल पर हमारी निर्भरता सर्वाधिक है। कृषि से लेकर बाकी तमाम क्षेत्रों में पानी के किफायती इस्तेमाल पर हमें गौर करना होगा। अच्छी बात यह है कि आज जो आलम है उसमें अब सरकारों के लिए पानी मसला नहीं, बल्कि मिशन है। समय के साथ बदले सरोकारों की यह नई हकीकत है। यही वजह है कि बीते कुछ दशकों में जल संरक्षण को लेकर विश्व मानचित्र पर कई मॉडल उभरे हैं। बदलाव के इस सफर के एक छोर पर सिंगापुर जैसा छोटा मुल्क है, तो दूसरे छोर पर भारत जैसी विशाल आबादी और भूगोल वाला देश। नई सरकार के गठन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुछ बातें स्पष्टता से देश के सामने रखी हैं। उन्होंने जहां विकसित भारत के निर्माण को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई, वहीं सरकार की पूर्व से चल रही योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात भी कही। इस बारे में कैबिनेट के सहयोगियों को उन्होंने खास तौर पर हिदायतें दी हैं। अलबत्ता, चढ़ते पारे के बीच पानी की समस्या को लेकर जो स्थिति देश की राजधानी और बाकी हिस्सों में है, उसमें जरूर सरकार की नीति और दृष्टि को लेकर कुछ बातें साफ होने की हैं। बहरहाल, बात पहले सिंगापुर की। दुनिया भर में सैर-सपाटे के लिए सबसे पसंदीदा ठिकाने और बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में सिंगापुर का नाम पूरी दुनिया में है। तीन दशक पहले जब डिजिटिलीकरण का जोर बढ़ा तो दुनिया भर की कंपनियों ने अपने उत्पाद को यहीं से तमाम देशों में भेजना और प्रचारित करना सबसे बेहतर माना। पर जैसा कि आज वहां के लोगों को लगता है कि सिंगापुर की एक दूसरी पहचान भी है, जो ज्यादा प्रेरक है, ज्यादा मौजूं है। आने वाले चार दशकों के लिए आज सिंगापुर के पास पानी के प्रबंधन को लेकर ऐसा ब्लूप्रिंट है, जिसमें जल संरक्षण से जल शोधन तक पानी की किफायत और उसके बचाव को लेकर तमाम उपाय शामिल हैं। सिंगापुर की खास बात यह भी है कि उसका जल प्रबंधन

शहरी क्षेत्रों के लिए खास तौर पर मुफीद है।

गौरतलब है कि सिंगापुर ऐसा शहर-राष्ट्र है, जिसके पास न तो कोई प्राकृतिक जल इकाई है, न ही पर्याप्त भूजल भंडार है, इतनी भूमि भी नहीं कि बरसात के पानी का भंडारण कर सके। ऐसे में गंदे पानी के शुद्धिकरण, समुद्री जल का खारापन कम करने और वर्षा जल के अधिकतम संग्रह के साथ सिंगापुर ने पानी से जुड़ी अपनी जरूरतों को पूरा करने का ऐसा मॉडल तैयार किया, जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ सामाजिक बदलाव की बड़ी मिसाल है। सिंगापुर से भारत सीख तो सकता है, पर हमारे देश की आबादी और भूगोल ज्यादा मिश्रित और व्यापक है। लिहाजा, पानी को लेकर भारतीय दरकार और सरोकार भी खासे भिन्न हैं। इसे भारतीय राजनीति में प्रकट हुए सकारात्मक बदलाव के साथ सरकारी स्तर पर आई नई योजनागत समझ भी कह सकते हैं कि अब स्वच्छता और घर-घर टोंटी से पानी की पहुंच जैसा मुद्दा साल के एक या दो दिन नारों-पोस्टरों से आगे सरकार की घोषित प्राथमिकता है। भारत पानी और स्वच्छता के सवाल को न सिर्फ योजनागत लक्ष्यों में, बल्कि उत्तरोत्तर विकसित होती जन-भागीदारी और जागरूकता के रूप में भी देख-समझ रहा है। दस साल पूर्व न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर पर भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था कि हम गंगा को साफ करने में सक्षम हो गए तो यह देश की 40 फीसद आबादी के लिए बड़ी मदद साबित होगी।

आज हम उस मुकाम पर हैं जब सफलता से ज्यादा पूर्व और पश्चात का अंतर देख सकें। यह अंतर तब और अहम मालूम पड़ेगा जब हम इस दृष्टि से विचार करें कि भारत जैसी भौगोलिक और वैचारिक भिन्नता वाले देश में कोई आम सहमति विकसित करना आसान नहीं है। यह भी कि भारत में पानी राज्य का विषय है। लिहाजा, खास तौर पर नदियों को लेकर किसी यूनिफाइड प्रोजेक्ट पर सहमति के साथ आगे बढ़ना चुनौतीपूर्ण है। पानी को लेकर भारत की स्थिति में बदलाव देखने का एक बड़ा आधार सरकार की समझ और नीति है। देश में सरकारों की योजनागत समझ और प्रतिबद्धता में दिखी कमजोरी ही रही कि आस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक के लिए महत्त्वपूर्ण नदियों को केंद्र में रख कर दशकों तक कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया। पानी को लेकर काम कर रहे तमाम विभागों को साथ लाकर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के गठन के बाद जल क्षेत्र में हम काफी आगे बढ़े हैं। यह बढ़त गंगा सहित कई नदियों के कायाकल्प से जुड़े प्रयासों से लेकर अमृत सरोवर मिशन तक कई स्तरों पर सफलता के आंकड़ों के रूप में सामने है।

नमामि गंगे दस साल की यात्रा पूरी कर रही है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से 2020-23 तक किए गए सर्वे में गंगा और उसकी सहायक 13 नदियों में 3936 डॉल्फिन मिली हैं। यह देश में नदी जल की शुद्धता की बेहतर हुई स्थिति का सबूत है। नमामि गंगे को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा चलाए गए एक ग्लोबल मूवमेंट के तहत टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की यह सराहना भारत की जल नीति और दृष्टि की बड़ी टेस्टिमोनी है। आज देश में 14.85 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक नल से शुद्ध जल पहुंच रहा है। नोबेल विजेता प्रो. माइकल क्रेमर के एक शोध के मुताबिक सभी ग्रामीण परिवारों तक कवरेज के साथ जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन से बाल मृत्यु दर में सालाना 1.36 करोड़ की कमी आएगी। साफ है कि पानी के साथ मनमानी के खतरे को समझते हुए देश आज जरूरी जवाबदेही और समझदारी के दौर में हैं। जल संरक्षण को लेकर समाज और सरकार का एक सीध में आगे बढ़ना न सिर्फ कारगर रहा है, बल्कि भविष्य के खतरों के लिहाज से भी जरूरी पहल है।

पानी को लेकर भारत की स्थिति में बदलाव देखने का एक बड़ा आधार सरकार की समझ और नीति है। देश में सरकारों की योजनागत समझ और प्रतिबद्धता में दिखी कमजोरी ही रही कि आस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक के लिए महत्त्वपूर्ण नदियों को केंद्र में रख कर दशकों तक कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया। लेकिन पानी को लेकर काम कर रहे तमाम विभागों को साथ लाकर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के गठन के बाद जल क्षेत्र में हम काफी आगे बढ़े हैं

...तो गुस्सा हो जाएगा काफूर

- प्राचीन रोम में वैराग्य दर्शन के विद्वान सेनेका का मानना था कि हमारी किसी गलती से उतना नुकसान नहीं होता जितना हमारे गुस्से से होता है
- हाल में जापान की नगोया यूनिवर्सिटी के अध्ययन में दावा किया गया कि किसी नकारात्मक घटना की अपने ऊपर जो प्रतिक्रिया होती है, उसे कागज के टुकड़े पर लिख लें और उसको गेंद बना कर कूड़ेदान में फेंद दें तो आपको गुस्से से छुटकारा मिल जाएगा
- साइंटिफिक रिपोर्ट्स ऑन नेचर में इस शोध का निष्कर्ष छपा है कि लिखित शब्द और क्रोध में कमी के बीच संबंध है

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

आज 18 साल का एक युवा उम्मीद करता है कि देश की संसद उसके भविष्य पर चर्चा करेगी, ना कि 5 दशक पुराने आपातकाल पर। आज पेपर लीक ही युवाओं का आपातकाल है! 21 साल का युवा उम्मीद करेगा कि उसकी बेरोजगारी पर चर्चा हो, जो उसके लिए बड़ी समस्या है!

प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद
@priyankac19

संसद में बेमतलब के नारे

मुद्दा | रजनीश कपूर

लोक सभा की सदस्यता की शपथ लेते समय हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा नारा लगाया जिस पर पूरा देश चौंक गया। उन्होंने 'जय भीम', 'जय मीम', 'जय तेलंगाना' और 'जय फिलिस्तीन' का नारा लगाया। जहां तक 'जय भीम' और 'जय तेलंगाना' जैसे नारों की बात है तो ये देश की सीमाओं के दायरे में आते हैं। पर एक दूसरे देश की जयकार बोलना, वो भी संसद के भीतर, किसी के गले नहीं उतरा। ओवैसी ने बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत की है। आने वाले वर्षों में कोई सांसद 'जय अमेरिका', 'जय पाकिस्तान' या 'जय चीन' का भी नारा लगा सकता है। इसलिए इस खतरनाक प्रवृत्ति पर लोक सभा और राज्य सभा के अध्यक्षों को फौरन रोक लगानी चाहिए।

सब जानते और मानते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब नास्तिक होना नहीं है, बल्कि इसका भाव है, सर्व धर्म समभाव, यानी हर धर्म के प्रति सम्मान का भाव। पर देखने में आया है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों और हिन्दुओं के कुछ नेता सांप्रदायिकता को भड़काने के उद्देश्य से धार्मिक उन्माद बढ़ाने वाले नारे लगवाते हैं ताकि उनके वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। जहां एक तरफ बरसों से मुसलमानों को अल्पसंख्यक बता कर उनके पक्ष में ऐसे काम किए गए जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध थे। जैसे रमजान में सरकारी स्तर पर इफ्तार की दावतें आयोजित करना। ऐसी दावतें अन्य धर्मों के उत्सवों पर भी की जातीं तो किसी को बुरा नहीं लगता। पर ऐसा नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि हिन्दुत्व की राजनीति करने वालों को अपने समर्थकों को उकसाने का आधार मिल गया। शायद इसी का परिणाम है कि पिछले दस वर्षों में भाजपा के सांसदों और विधायकों ने संसद और विधानसभाओं में जोर-जोर से और सामूहिक रूप से धार्मिक नारे लगाना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अब मुसलमानों के बीच भी उत्तेजना और आक्रामकता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है जबकि यह खतरनाक प्रवृत्ति है, जिसे सख्ती से रोका जाना चाहिए वरना समाज में गतिरोध और हिंसा बढ़ेगी।

वैसे इस तरह का वातावरण असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भी तैयार किया जाता है। इसलिए समझदार हिन्दू और मुसलमान अपने धर्म के प्रति आस्थावान होते हुए भी इस हवा में नहीं बहते। हिन्दुत्व का समर्थक कोई पाठक

मुझसे तर्क कर सकता है कि हिन्दुस्तान में भाजपा के सांसदों और विधायकों को हिन्दुवादी नारे लगाने से रोका जाएगा तो क्या हम फिलिस्तीन में जा कर ये नारे लगाएंगे? मेरा उत्तर है कि मैं सनातनधर्मी हूं और मेरा परिवार और पूर्वज शुरू से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं। लेकिन पिछले 30 वर्षों में हिन्दुत्व की राजनीति का जो चेहरा मैंने देखा है उससे मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं। जब देश की आबादी 141 करोड़ है, इनमें से 97 करोड़ वोटर हैं। उसमें से 36.6 प्रतिशत वोटरों ने ही इस चुनाव में भाजपा को वोट दिया है। मतलब यह कि कुल 111 करोड़ हिन्दुओं में से केवल 35 करोड़ हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। तो भाजपा सारे हिन्दू समाज के प्रतिनिधित्व का दावा कैसे कर सकती है? चूंकि देश की आबादी में 78.9 प्रतिशत हिन्दू हैं, और उनमें से एक छोटे से हिस्से ने बीजेपी को वोट दिया है। मतलब बहुसंख्यक हिन्दू भाजपा की नीतियों से सहमत नहीं हैं। हम सब मानते हैं कि हमारा धर्म सनातन धर्म है, जिसका आधार हैं वेद, पुराण, गीता, भागवत, रामायण आदि ग्रंथ। क्या भाजपा इनमें से किसी भी ग्रंथ के अनुसार आचरण करती है? अगर नहीं तो कैसे हिन्दू धर्म के पुरोधा होने का दावा करती है?

हमारे धर्म के चार स्तंभ हैं-चारों पीठों के शंकराचार्य जिन्हें आदि शंकराचार्य जी ने सदियों पहले भारत के चार कोनों में स्थापित किया था। क्या भाजपा चारों शंकराचार्यों को यथोचित सम्मान देती है और इनके ही मार्गनिर्देशन में अपनी धार्मिक नीति बनाती है? अगर नहीं तो फिर बीजेपी हिन्दू धर्म की पुरोधा कैसे हुई? सनातन धर्म में साकार और निराकार, दोनों ब्रह्म की उपासना स्वीकृत हैं। इस तरह उपासना के अनेक मार्ग और अधिकृत संप्रदाय हैं। इसलिए पूरे देश में व्याप्त सनातन धर्म का कोई एक झंडा या जयघोष नहीं होता। जैसे 'जय श्री राम' किसी अधिकृत संप्रदाय का जयघोष नहीं है। प्रभु श्री राम को लोग 'जय सिया राम', 'राम-राम' 'जय रामजी की' आदि अनेक संबोधनों से पुकारते हैं। 'जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी'। फिर केवल 'जय श्री राम' धार्मिक उदघोष कैसे हुआ? ऐसी तमाम अन्य बातों को भी देख-सुन कर स्पष्ट होता है कि भाजपा का हिन्दुत्व सनातन धर्म नहीं है। यह इनकी राजनीति के लिए अस्त्र मात्र है। इसका अर्थ हुआ कि संसद में चाहे 'जय श्री राम' का नारा लगे और चाहे 'अल्लाह हो अकबर' का, दोनों ही राजनैतिक उद्देश्य से लगाए जाने वाले नारे हैं, जिनका उद्घोष संसद में नहीं होना चाहिए। जय फिलिस्तीन का नारा तो और भी खतरनाक प्रवृत्ति है। संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष गंभीरता से विचार करके संविधान और संसद की गरिमा बचाने का काम करें।

बढ़ती इच्छाएं | श्रीराम शर्मा आचार्य

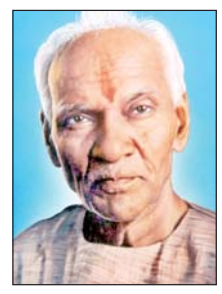

वस्तु एवं विषयों का बाहुल्य हो जाने के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं एवं इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं। और इसी के साथ समुपस्थित साधनों की अपेक्षा जनसंख्या की अपरिमित वृद्धि से मनुष्यों का स्वार्थ भी पराकाष्ठा पार कर गया है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण संसार की शक्तियों का सन्तुलन बिगड़ गया है, जिससे मनुष्यों के बीच पारस्परिक विश्वास समाप्त हो गया है। आधिक्य तथा अभाव की विषमता के कारण रोग, दोष, शोक, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लाभ आदि की प्रवृत्तियां बहुत बढ़ गई हैं। और इन प्रवृत्तियों की गिरफ्त में आज का इनसान आ चुका है। यही कारण है कि जीविका के लिए जीवन में अत्यधिक व्यस्तता बढ़ जाने के कारण मनुष्य एक निर्जीव यंत्र बन गया है, उसके जीवन की सारी प्रसन्नता, उल्लास, हर्ष एवं आशा आदि विशेषताएं आज समाप्त हो गई हैं। और इनकी जगह आज मनुष्य निष्ठुर, नीरस, अनास्थावान एवं नास्तिक बन गया है। मन में कोई उत्साह न रहने के कारण धर्म उसके लिए ढोंग और संयमशीलता, रूढ़िवादिता के रूप में बदल गई है। इसके साथ ही मनुष्य को परेशान करने वाली परिस्थितियों के विकटतम जाल चारों ओर फैल गए हैं। इन परेशानियों में फंसा-फंसा जब वह ऊब उठता है तो नवीनता तथा ताजगी लाने के लिए निकृष्ट मनोरंजनों तथा मद्यादिक व्यसनों की ओर भाग पड़ता है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, स्वार्थ एवं संघर्ष आज के समय का वास्तविक जीवन बन गया है। इतनी दुष्ट प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों के रहते हुए आखिर, मनुष्य परेशान न हो यह कैसे हो सकता है? क्या अनपढ़ और क्या पढ़ा लिखा, क्या धनवान और क्या निर्धन, क्या मालिक और क्या मजदूर, बच्चा-बूढ़ा, स्त्री-पुरुष सब समान रूप से अपनी-अपनी तरह परेशान देखे जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मनुष्य अपनी इन तमाम परेशानियों का इतना अभ्यस्त हो गया हो कि इनकी ओर से उदासीन रह रहा हो, बल्कि वह इन व्यग्रताओं से इतना दुःखी हो उठा है कि उसे जीवन में कोई विशेष दिलचस्पी बाकी नहीं रह गई है, जिसके फलस्वरूप समाज में अपराधों, विकृतियों एवं कुरूपताओं की एक तरह से बाढ़ सी आ गई है। मानव-जीवन के लक्ष्य 'सत्यम शिवम, सुन्दरम' का पूर्णरूपेण तिरोधान हो गया है।

रीडर्स मेल

बारिश की खुशी क्षणभंगुर

महोदय, मानसून लगभग सभी राज्यों में आहिस्ता-आहिस्ता प्रवेश कर रहा है। पहली बारिश से जनजीवन को बड़ा सुकून मिला है, मगर यह खुशी क्षणभंगुर है क्योंकि इसके बाद जब जोरों की बारिश होगी तो नाले उफान मारेंगे। गंदगी सड़कों पर और उसके बाद घरों तक में चली जाएगी क्योंकि अभी तक सफाई शुरू नहीं हुई है। सरकार और उसके अमले से आग्रह है कि सभी जगह के नालों और नालियों की अविलंब सफाई शुरू हो।

मयंक राज, भागलपुर

नशे के खिलाफ हो कार्रवाई

नशा समाज की सबसे बड़ी बुराई है। इसके खिलाफ आगे आकर युवा पीढ़ी को बचाने हेतु आम नागरिक और पुलिस प्रशासन की संयुक्त मनुहार जरूर रंग लाएगी। पूरे भारत पुलिस को नशे के खिलाफ मुहिम चलाना चाहिए। यह नेक काम है क्योंकि नशा समाज के लिए नासूर बन गया है जिसमें युवा नशे की लत का आदि बनता जा रहा है। नशा मुक्ति के लिए मिल कर प्रयास किए जाना शुभ संकेत है। अब सहयोगी बन कर पुलिस को गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, शहर-गांव में जाकर युवाओं को विभिन्न माध्यमों नुक्कड़ नाटक आदि कार्यक्रमों के माध्यम से समझाना चाहिए। नशे की बुराई के प्रति सरकार कठोर से कठोर कदम उठाए तभी इस बुराई का नकारात्मक प्रभाव खत्म होगा। युवा पीढ़ी को नशे के गुलाम होने से बचाने के लिए हम सभी आगे आएं।

हरिहर सिंह चौहान, इंदौर

सराहनीय सुधारात्मक कदम

जब लोग अपनी आमदनी पर स्वयं टैक्स देते हैं, तो मंत्रियों का आयकर सरकार द्वारा अलग से भरने के कांग्रेस जनित प्रावधान को समाप्त करके स्वयं द्वारा भरने का मध्य प्रदेश के मंत्रियों द्वारा सर्वसम्मत निर्णय स्वार्थरहित, लोक हितकारी संवेदनशील मुद्दा है, जो कांग्रेस जनित दुर्गुण के विरुद्ध सुधारात्मक और सकारात्मक कार्यवाही का एक और कदम है।

मनोज श्रीवास्तव, सुलतानपुर

महालानोविस का अतुलनीय योगदान

29 जून को (आज) भारत के ख्यातनाम वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालानोबिस की 131वीं जयंती देश में 'राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन' के रूप मे मनाई जा रही है। उन्हें भारत की द्वितीय पंच-वार्षिक योजना का मसौदा तैयार करने के लिए जाना जाता है। सांख्यिकी के क्षेत्र में वे अपनी खोज 'महालानोबीस दूरी' के लिए प्रसिद्ध हैं, जो एक सांख्यिकीय माप है। महालानोबिस का सर्वश्रेष्ठ योगदान उनकी सैम्पल सर्वे की संकल्पना है, जिसके आधार पर आज के युग में बड़ी-बड़ी नीतियां और योजनाएं बनाई जा रही हैं। 1931 में उन्होंने कलकत्ता में 'भारतीय सांख्यिकी संस्थान' की स्थापना की, जहां पर सांख्यिकी की पढ़ाई और संशोधन कार्य होता है। 1933 में संस्था ने 'संख्या' नामक शोध जर्नल की शुरुआत की। प्रशांत चंद्र महालानोबिस दूरद्रष्टा थे, जिन्होंने हमेशा आम आदमी की भलाई के लिए ही कार्य किया। देश की आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनको कोटि कोटि नमन!

विजय कोष्टी, सांगली, महाराष्ट्र

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 266
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अभिभाषण का भाव

अठारहवीं लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का अभिभाषण न केवल विश्वास जगाने की अच्छी कोशिश है, बल्कि सत्ता पक्ष की राजनीति का भी स्पष्ट संकेत है। राष्ट्रपति ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का विशेष रूप से उल्लेख किया। परीक्षाओं के साथ निरंतर हो रहे खिलवाड़ की वजह से किशोरों और युवा पीढ़ी में चिंता व्याप्त है। शिकायतों के प्रति सरकार को गंभीर होना चाहिए। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कथित गड़बड़ी का उल्लेख किया और वादा किया कि उनकी सरकार निष्पक्ष परीक्षाएं आयोजित करेगी। वास्तव में, युवा पीढ़ी और देश यही चाहता है कि परीक्षाओं को चाक-चौबंद बनाया जाए। उनसे खिलवाड़ करने वाले रसूखदारों के दुस्साहस को मुंहतोड़ जवाब मिलना ही चाहिए। राष्ट्रपति ने सही कहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पर विचार करने की जरूरत है।

राष्ट्रपति ने संसद के सभी सदस्यों को सलाह दी है कि सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए संसदीय कार्यवाही को बाधित नहीं किया जाए। यह बात छिपी हुई नहीं है कि संसद का समय बड़े पैमाने पर हंगामे की भेंट चढ़ता है। राष्ट्रपति की इस सदिच्छा का सम्मान सांसदों का कर्तव्य होना चाहिए। विरोध अपनी जगह है, जहां संसद सहमत नहीं होगी, वहां उन्हें नाराजगी जताने में हिचकना नहीं चाहिए, पर सदन में अनावश्यक शोर करना, मात्र विरोध के लिए विरोध करना बंद हो जाना चाहिए। देश की सर्वोच्च पंचायत फिजूल की टीका-टिप्पणियों के लिए कतई नहीं है। 18वीं लोकसभा में अगर कम से कम हंगामा और ज्यादा से ज्यादा काम हो, तो देश की तरक्की को बल मिलेगा। हंगामा या समय की बर्बादी सत्ता पक्ष की वजह से हो या विपक्ष की वजह से, नुकसान देश को होता है। राष्ट्रपति ने सांसदों को याद दिलाया है कि सदन के सभी सदस्यों के लिए लोकहित सर्वोपरि होना चाहिए। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह भी संकेत दिया है कि सरकार आगामी बजट के दौरान कई बड़ी घोषणाएं करेगी। पहले से ही यह उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी बजट देश की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को प्रभावित करने वाला हो सकता है। इससे देश में आर्थिक सुधार की गति बढ़ेगी। यहां लोग यही उम्मीद करेंगे कि आर्थिक सुधार आम लोगों के अनुरूप हों, कंपनियों की सुनवाई हो, पर लोगों की जरूरतों को देखते हुए सुधार के कदम उठाए जाएं। ऐसे कदम जरूरी हैं, जिनसे रोजगार में वृद्धि हो।

परीक्षाओं के साथ खिलवाड़ को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने सही कहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार की जरूरत है।

राष्ट्रपति का यह कहना भी प्रशंसनीय है कि निवेश के लिए हमारे राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा होनी चाहिए। निवेश आमंत्रित करने के लिए, बेहतर नीतियों को लागू करने के लिए प्रतिस्पर्द्धा का भाव आना जरूरी है। राज्य जब एक-दूसरे से सीखेंगे और एक-दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, तब देश की तरक्की तेज होगी। कुल मिलाकर, अभिभाषण स्वागतयोग्य है, पर हमेशा की तरह इस बार भी अभिभाषण की बातें विपक्ष को पसंद नहीं आई हैं। यहां यह समझना चाहिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को केंद्र सरकार तैयार करती है और जब इसमें आपातकाल को काला अध्याय के रूप में याद किया गया, तो विपक्ष की नाराजगी उभर आई। आपातकाल को हम भुला नहीं सकते, पर उसे बार-बार याद करके कटु यादों को ताजा करने से ज्यादा बेहतर है कि हम सबक लें और लोकतंत्र की ज्यादा मजबूती के लिए काम करें।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 28 जून, 1949

सहायक खाद्य

खाद्यान्नों की हमारे देश में कमी है और विदेशों से अन्न मंगाकर हम जो उसकी पूर्ति कर रहे हैं, उससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ रहा है, इस बारे में दो मत नहीं हो सकते। इसका हल दो ही तरह से संभव है। या तो हम अपनी उपज बढ़ायें और फिर भी कमी रहे, तो सहायक खाद्य-पदार्थों की उत्पत्ति-वृद्धि एवं उन्हें काम में लाने की कोशिश करें, या अन्न के आयात को अपने औद्योगिक अथवा कच्चे माल के निर्यात की वृद्धि द्वारा सन्तुलित करें। दोनों में से एक अथवा कम-बढ़ दोनों ही बातें करना आवश्यक है। अतः इनमें से जो भी बात की जाये, उसे सबका सहयोग मिलना चाहिए।सबसे पहला प्रयत्न इस दिशा में उपज-वृद्धि का ही होना चाहिए। 'अधिक खाद्यान्न पैदा करो' की सरकारी हलचल हम बरसों से देख भी रहे हैं, फिर भी यदि इस दिशा में कोई सन्तोषप्रद परिणाम सामने नहीं आया तो समझना चाहिए कि या तो इससे सम्बन्धी सरकारी हलचल सदोष रही है या फिर हमारे यहां उपज-वृद्धि की कोई गुंजाइश ही नहीं है। खासकर जब डा. राजेन्द्र प्रसाद जैसे जिम्मेदार व्यक्ति, जो कि खुद भी सरकार के खाद्य विभाग का संचालन कर चुके हैं, हमें बताते हैं कि हमारे यहां खाद्य की कमी केवल १० प्रतिशत है और यदि सौ मन उपज को हम सावधानी से खेती करके एक सौ दस मन कर सके, यानी हर दस मन उपज में केवल एक मन उपज ही बढ़ा सके तो भी यह पूरी हो सकती है। तो हमारी समझ में नहीं आता कि अन्नाभाव का इतना शोर क्यों है और अभी तक वह कमी पूरी क्यों नहीं हो पाई। यह भी आज कोई नहीं मानता कि हमारे यहां अन्नोत्पादन-वृद्धि की गुंजाइश नहीं है। फिर, ऐसा नहीं हो पाया, तो क्यों नहीं हो पाया इसका पता लगाना चाहिए और जो कारण इसमें बाधक रहे हों, उन्हें दूर कर यह काम करना चाहिए।

मालूम यह पड़ता है कि सम्बन्धी सरकारी विभाग इस दिशा में झंझट पाकर विदेशों से अन्न मंगाने के मार्ग को आसान पा रहा है, फिर उससे चाहे देश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़े। आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर की बात हम इसलिए कहते हैं, क्योंकि हमारे विदेशी व्यापार की असंतुलितता का कारण विदेशों से अन्न के भारी आयात को ही बताया जा रहा है।

शेयर बाजार की समृद्धि कैसे हो साझा

यहां स्कैन करें

अरुण कुमार | वरिष्ठ अर्थशास्त्री

शेयर बाजार से वास्तविक लाभ हासिल करने के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धनाढ्यों की नजर से देखने के बजाय मध्यवर्ग या गरीबों के नजरिये से देखना चाहिए।

शेयर बाजार के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने से निवेशक खुश हैं। गुरुवार को भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 79,000 के ऊपर चला गया था, जो इसके इतिहास में पहली बार हुआ है। निफ्टी भी कमोबेश इसी गति से आगे बढ़ रहा है और वह 24,000 के करीब पहुंचता दिखा। ये आंकड़े निवेशकों के लिए भले मुफीद हों, लेकिन आम भारतीय इसे कौतुक की नजर से ही देखते हैं। ऐसा क्यों?

दरअसल, शेयर बाजार में करीब 6,000 सूचीबद्ध कंपनियां हैं, जिनमें मूलतः तीन तरह के निवेशक निवेश करते हैं। पहला वे बड़े निवेशक हैं, जो अमूमन कंपनियों के मालिक होते हैं। आबादी के लिहाज से ये देश के 0.1 प्रतिशत लोग हैं और शेयर बाजार को कमोबेश यही नियंत्रित करते हैं। हालांकि, मध्य वर्ग के निवेशक भी लाख-दो लाख रुपये का निवेश करते हैं, लेकिन बड़े खिलाड़ी इन 0.1 प्रतिशत लोगों को ही माना जाता है। दूसरे वे निवेशक होते हैं, जो बड़े करदाता हैं और जिनकी हिस्सेदारी कुल जनसंख्या में 1.1 प्रतिशत है। जबकि, तीसरे निवेशक करीब आठ करोड़ वे लोग हैं, जो बहुत मामूली रकम निवेश करते हैं। चूंकि शेयर बाजार के गुणा-भाग खासतौर से इनसाइडर ट्रेडिंग (कंपनियों की आंतरिक सूचनाओं को हासिल करना) या मैन्युपुलेशन (तिकड़मबाजी) से ये अनजान रहते हैं, इसलिए बाजार के गिरने का नुकसान इनको ही अधिक होता है, जबकि ज्यादातर फायदा शुरुआती दो तरह के निवेशकों के हिस्से में जाता है।

शेयर बाजार को लेकर यह भी समझने की जरूरत है कि यह भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित होता है। अगर आज बाजार ऊपर है, तो निवेशकों को यही उम्मीद होती है कि आने वाले दिनों में यह अच्छा करने वाला है। यही कारण है कि जब उन्हें किसी संकट का एहसास होता है, तो निवेशक अपने शेयर बेचना शुरू कर देते हैं और शेयर बाजार गिरने लगता है। इसीलिए, इससे जुड़ी उम्मीदों व अपेक्षाओं को बरकरार रखने के लिए तमाम सरकारी वित्तीय संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता है।

शेयर बाजार में संगठित क्षेत्र की कंपनियां ही होती हैं। यही वजह है कि अपने देश में करीब छह लाख लघु व मध्यम कंपनियों और छह करोड़ सूक्ष्म कंपनियों का शेयर बाजार प्रतिनिधित्व नहीं करता, यानी इसमें इन कंपनियों के शेयर नहीं होते। जबकि, ज्यादातर रोजगार यही कंपनियां देती हैं। यह मान लिया जाता है कि बड़ी कंपनियां यदि अच्छा करेंगी, तो उसका फायदा छोटी-छोटी कंपनियों को भी होगा। मगर दिक्कत यह है कि बड़ी कंपनियां भी अब तमाम तरह के उत्पाद बनाने लगी हैं और हम भी ऑनलाइन सामान खरीदना पसंद करने लगे हैं, इसलिए छोटी कंपनियों की मांग बड़ी कंपनियों के खाते में जाने लगी है, जिससे प्रतिस्पर्द्धा में छोटी कंपनियां पिछड़ने लगी हैं। इसका असर देश के रोजगार परिदृश्य पर भी दिख रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू कृषि भी है और दुर्भाग्य से इसका भी शेयर बाजार प्रतिनिधित्व नहीं करता। हां, कृषि में यदि कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो उसका परोक्ष लाभ जरूर शेयर बाजार को मिलता है, लेकिन कृषि की बेहतरी के बारे में शेयर बाजार शायद ही सोचता है। कृषि में हिस्सेदारी निभाने वाले 85 फीसदी छोटे किसानों की आर्थिकी तो इससे पूरी तरह दूर है। इन्हीं सब वजहों से माना जाता है कि महज छह फीसदी आबादी की इसमें हिस्सेदारी है, जो संगठित क्षेत्र के हैं, जबकि एक बड़ी संख्या (94 फीसदी) असंगठित क्षेत्र में होने के कारण शेयर बाजार से दूर है।

जाहिर है, शेयर बाजार में नीतिगत बदलाव की जरूरत है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इसका ज्यादातर फायदा आमतौर पर 0.1 प्रतिशत और 1.1 प्रतिशत आबादी (शुरुआती दो तरह के निवेशकों) के खाते में चला जाता है, जिससे आर्थिक असमानता में इजाफा हो रहा है। सरकार को शेयर बाजार के लाभांश (कैपिटल गेन्स) पर कर के रूप में पैसे जरूर मिलते हैं, लेकिन चूंकि अपने देश में संपत्ति कर (वेल्थ टैक्स, यानी धनाढ्यों पर लगने वाला अतिरिक्त कर) खत्म कर दिया गया है, इसलिए शेयर बाजार में उछाल से सरकारी खजाने में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती। अच्छा होगा कि सरकार फिर से इस टैक्स को शुरू करे, जिससे उसके राजस्व में वृद्धि होगी। कुछ इसी तरह का टैक्स संपत्ति के पीढ़ीगत हस्तांतरण पर भी लगाया जाना चाहिए, जिसे 'इनहेरिटेंस टैक्स', यानी उत्तराधिकार कर कहा जाता है। हमारे यहां ये दोनों कर नहीं हैं, जबकि गैर-बराबरी कम करने में इनको काफी कारगर माना जाता है।

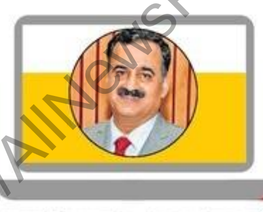

असल में, शेयर बाजार से वास्तविक लाभ हासिल करने के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धनाढ्यों की नजर से देखने के बजाय मध्यवर्ग या गरीबों के नजरिये से देखना चाहिए। उनकी तरक्की से अर्थव्यवस्था को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अमीर आदमी अपनी आमदनी का मामूली हिस्सा खर्च करता है, जबकि गरीब तुलनात्मक रूप से अधिक खर्च करता है। इससे बाजार में मांग पैदा होती है और निवेश बढ़ने की उम्मीद बंधती है। इसका किस तरह कंपनियों को भी फायदा होता है, इसका संकेत 1911 में फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मांग जब तक नहीं होगी, तब तब व्यापक उत्पादन का कोई अर्थ नहीं, जबकि 'मास प्रोडक्शन' अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी वारेन बफेट ने 2007-09 की मंदी के बाद कहा था कि पूंजीवाद को बचाने के लिए पूंजीपतियों पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, जिसका समर्थन जॉर्ज सोरोस जैसे अरब-खरबपतियों ने भी किया था।

भारत में अभी इसके लिए उचित समय भी है। अभी शेयर बाजार में सब कुछ ठीक चल रहा है, जिसका अर्थ है कि संगठित क्षेत्र अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसकी मांग बढ़ चली है। यह असंगठित क्षेत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है और चूंकि हम इसे शेयर बाजार का हिस्सा नहीं बना सकते, इसलिए संगठित क्षेत्र से टैक्स वसूलकर उसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। संपत्ति या उत्तराधिकार कर का उपयोग ग्रामीण विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मदों की बेहतरी में किया जा सकता है, जिनमें आज भी पर्याप्त खर्च नहीं किया जा रहा। इससे लोगों का जीवन बेहतर होगा। वैसे भी, अगर असंगठित क्षेत्र में मांग बढ़ेगी, तो उसका परोक्ष फायदा संगठित क्षेत्र को भी होगा, क्योंकि लोग उन उत्पादों को भी खरीदेंगे, जिनको बड़ी-बड़ी कंपनियां बनाती हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

साइबर संसार को कई संदेश दे गई असांजे की रिहाई

यहां स्कैन करें

पवन दुग्गल | साइबर कानून विशेषज्ञ

साइबर विशेषज्ञ, हैकर, संपादक जूलियन असांजे की रिहाई कोई सामान्य घटना नहीं है। यह रिहाई बदलते दौर का एक संकेत है। यह नई साइबर व्यवस्था का युग है, जिसमें तीन बातें साफ तौर पर हमारे सामने हैं। एक, सरकारें बहुत मजबूत होती जा रही हैं। दूसरी, साइबर सुरक्षा में सेंधमारी रोजमर्रा की समस्या बन गई है। तीसरी बात, साइबर अपराध हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। इन तीनों बातों से जोड़ते हुए ही जूलियन असांजे के मामले को देखना चाहिए।

जूलियन के खिलाफ मुकदमा इसलिए चलाया गया था, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी सरकार, अमेरिकी हितों और अमेरिकी सुरक्षा से संबंधित सूचनाएं हासिल कीं और विकीलीक्स पर प्रसारित कर दिया था। अमेरिका का कहना है कि विकीलीक्स में प्रकाशन से उसे बहुत नुकसान पहुंचा है। खुलासों के बाद अमेरिका उनके पीछे पड़ गया और वह गिरफ्तारी से बचते हुए भागते रहे। अनेक देशों में छिपते फिरते रहे और अंततः ब्रिटेन में गिरफ्तार कर लिए गए।

हमें यह समझना होगा कि जूलियन ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तब जो प्रधानमंत्री बने, उनके लिए जूलियन की रिहाई प्राथमिकता बन गई। कूटनीतिक स्तर पर रिहाई के लिए बहुत प्रयास हुए। अंततः एक समझौता या सौदा हुआ। सौदा हुआ, पर अमेरिका ने कहा कि मैं अपने आरोप खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि लगाए गए आरोप बेहद गंभीर किस्म के हैं, फिर भी यदि जूलियन असांजे माफी मांगते हैं और अपने आपको दोषी स्वीकार करते हैं, तो हम उनके द्वारा अब तक काटी गई सजा को पर्याप्त मानकर उन्हें रिहा कर देंगे। इसके बाद ही उनकी रिहाई के लिए रास्ता निकला। वह एक अमेरिकी अदालत में पेश हुए और खुद को दोषी स्वीकार किया, तब उन्हें छोड़ा गया। अब वह स्वदेश ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं।

जूलियन असांजे बहुत भाग्यशाली रहे कि उनकी रिहाई के लिए राजनीतिक संधि हुई है, पर हर इंसान इतना खुशकिस्मत नहीं है।

कुल मिलाकर, यह रिहाई एक अप्रत्याशित घटना है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उनकी रिहाई हो जाएगी। वास्तव में, यह दुनिया में मजबूत होती सरकारों के प्रयासों का नतीजा है। यहां ऑस्ट्रेलिया सरकार अगर मजबूती से रिहाई के प्रयास नहीं करती, तो वाकई अमेरिका जूलियन को इतनी जल्दी नहीं छोड़ता।

इस मामले को व्यापकता में देखना चाहिए। आज दुनिया में अलग-अलग सरकारों के पास अपने-अपने साइबर कानून हैं। साइबर अपराध को बहुत गंभीरता से लेने की शुरुआत हो चुकी है। पहला संदेश यही जाता है कि अगर आप किसी का डाटा उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप किसी सरकार का गोपनीय डाटा उजागर कर देते हैं, तो वह सरकार या राष्ट्र चुप नहीं बैठेगा, आप पर मुकदमे करेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, आपको गिरफ्त में ले लिया जाएगा।

दूसरा संदेश यह है कि कोई भी किसी सरकार के बारे में किसी गोपनीय जानकारी का पता न लगाए, तो साइबर कानूनों से बच सकता है। अगर दुनिया की कोई भी सरकार आप पर सुरक्षा संबंधी डाटा लीक करने का इल्जाम लगाती है, तो फिर दूसरी सरकारें आपका बचाव नहीं करेंगी।

जूलियन असांजे बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि उनकी रिहाई के लिए राजनीतिक-कूटनीतिक संधि हुई है, पर हर इंसान उनकी तरह खुशकिस्मत नहीं रहेगा। यह भी ध्यान रहे कि वह तभी छूट सके हैं, जब उन्होंने खुद को दोषी मान लिया है, अमेरिका भी इस बात से खुश है कि उसके लगाए गए आरोप साबित हुए हैं।

इस रिहाई के बाद बहुत सारी सरकारें सजग हो जाएंगी और अपने डाटा लीक के मामलों को गंभीरता से लेंगी। यह बात भी सामने आ गई है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सरकार से संबंधित गोपनीय सूचनाएं प्रकाशित नहीं कर सकते। पत्रकारिता का अर्थ यह नहीं कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा से खेलने लगें। अब अनेक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा, क्योंकि सरकारें पहले की तुलना में ज्यादा सजग हो जाएंगी। इसका एक असर यह भी होगा कि विकीलीक्स जैसे प्रयोग कम होंगे या नहीं हो पाएंगे। अब ज्यादा से ज्यादा डाटा डार्क नेट पर स्थानांतरित होते जाएंगे। डार्क नेट पर साइबर अपराधियों का पता लगाना अब भी मुश्किल है। डाटा चोरी के लिए एआई का इस्तेमाल भी बढ़ने वाला है, तो कुल मिलाकर, साइबर चुनौतियां बढ़ने वाली हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मनसा वाचा कर्मणा

मृत्यु से डरते थॉमस

मैं एक ऐसे शख्स (काल्पनिक नाम- थॉमस) को जानता हूं, जिन्होंने एक हजार डॉक्टरों से इलाज कराए हैं। उनकी उम्र 80 साल है। फिर भी, एक हजार बहुत बड़ी संख्या होती है। एक साल में उन्होंने औसतन 12 नए डॉक्टरों को दिखाया। कभी-कभी तो थॉमस एक दिन में तीन-तीन डॉक्टरों से सलाह लेते हैं।

थॉमस के कुछ दोस्त डॉक्टर हैं, तो कुछ डॉक्टर उनके दोस्त बन जाते हैं। उनके इन एक हजार डॉक्टरों में जूनियर से लेकर सीनियर, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर से लेकर निजी प्रैक्टिस करने वाले, सामान्य चिकित्सक से लेकर विशेषज्ञ तक शामिल हैं। पुरुष, महिलाएं, विदेशी, स्थानीय सभी तरह के डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया है। कभी महज रक्तचाप मापने के लिए, तो कभी सीने में अचानक उठे दर्द जैसे गंभीर मामले के लिए। अपने जीवनकाल में डॉक्टरों की फीस-जांच आदि पर वह लगभग 2,30,000 डॉलर खर्च कर चुके हैं। थॉमस को इसका कोई पछतावा नहीं है। लोग अपने शौक पूरे करने पर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन थॉमस के लिए यह डॉक्टर, डॉक्टर और डॉक्टर हैं। दुखद यह है कि थॉमस को हाल ही में फेफड़ों के कैंसर का पता चला और उन्हें मेरे पास भेजा गया था।

थॉमस मुझे एक सुलझे हुए सज्जन व्यक्ति लगे। उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, अपना मेडिकल इतिहास स्पष्ट रूप से बताया और मेरे अधिकांश प्रश्नों का उचित तरीके से उत्तर भी दिया। थॉमस मरने से डरते हैं। हममें से बहुत से लोग कैंसर पीड़ित हों या नहीं, पर मृत्यु के भय को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

अपनी मृत्यु के डर के अलावा थॉमस ने डॉक्टरों के प्रति अविश्वास का भी खुलासा किया। इलाज पर निर्णय लेने से पहले वह अधिक से अधिक राय ले रहे थे। उनके अपने संदेह थे। कुछ लोग थॉमस को 'थानाटोफोबिया' का शिकार कह सकते हैं। थानाटोफोबिया में व्यक्ति को अपनी या किसी प्रिय की मृत्यु का भय इस कदर सताता रहता है कि वह मनोवैज्ञानिक रूप से अपंग हो जाता है। मगर यह बहुत सुविधाजनक लेबल लगाना होगा, क्योंकि थॉमस सफल उद्यमी हैं व सामाजिक रूप से कुशल भी।

मैं थॉमस को कैंसर से लड़ने में मदद करूंगा। उनको जज नहीं करूंगा। मैं मौत के उनके डर का 'मेडिकलीकरण' नहीं करूंगा। यही इंसानियत है और इसकी कोई दवा नहीं होती।

हम हर छोटे से छोटे लक्षण या तकलीफ का इलाज करते हैं- शिशु के अत्यधिक रोने से लेकर किशोर के गुस्से, वेतनभोगी व्यक्ति की उदासी तक। थॉमस के पास कई डॉक्टरों को दिखाने का समय व पैसा है और ऐसा करना उन्हें अच्छा लगता है। यह उसके लिए उपचारात्मक है। मैं थॉमस को कैंसर से लड़ने में मदद करूंगा। उन्हें अनावश्यक रक्त परीक्षण और सिटी स्कैन कराने से रोकूंगा। मैं उन्हें जज नहीं करूंगा और सबसे बढ़कर, मैं मौत के उनके डर का 'मेडिकलीकरण' नहीं करूंगा। यही इंसानियत है और इसकी कोई दवा नहीं होती।

पाउलो कोएल्हो

जो बाइडन | अमेरिकी राष्ट्रपति

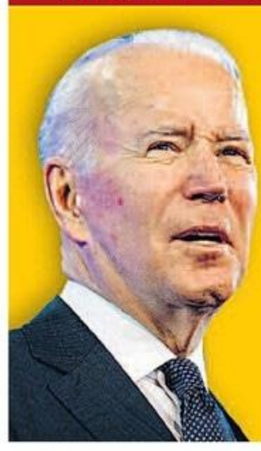

हमें मतपत्रों के जरिये अपने लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। लोकतंत्र पर डोनाल्ड ट्रंप का हमला सिर्फ उनके अतीत का हिस्सा नहीं है... बल्कि यह भविष्य के लिए उनके वादे की तरह भी है।

जय फलस्तीन बोलने में कैसा ऐतराज

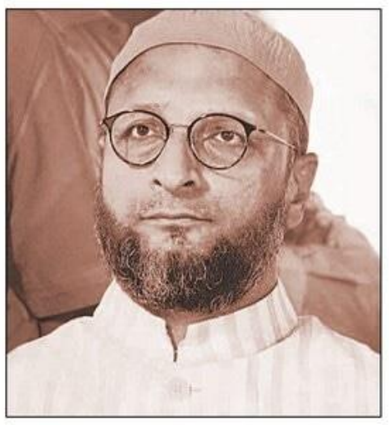

पिछली सदी के तीसरे दशक की बात है। तब तक फलस्तीनी इलाके में यहूदी राज्य की नींव पड़ चुकी थी। पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था और ब्रिटेन व फ्रांस ने मिलकर मध्य-पूर्व का बंटवारा कर लिया था। लीग ऑफ नेशंस (संयुक्त राष्ट्र से पहले की अंतरराष्ट्रीय संस्था) की निगरानी में सीरिया पर फ्रांस, तो इराक व फलस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हो चुका था। चूंकि ब्रिटेन की नीति यहूदियों को बसाने की थी, इसलिए पहले महायुद्ध के बाद लाखों यहूदी फलस्तीन में बसने के लिए आए। यहूदियों के इसी पलायन के खिलाफ सन् 1936 में अरब विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। जब फलस्तीन में यह सब हो रहा था, तब हिन्दुस्तान में भी अंग्रेजों का शासन था, लेकिन यहां ब्रिटिश हुकूमत के दमन के बावजूद पराधीन शासन का विरोध करने वाले देशभक्तों की कमी नहीं थी। इसी सूरते-हाल में इलाहाबाद में फलस्तीन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें राम मनोहर लोहिया, जेबी कृपलानी, मौलाना शौकत अली जैसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के भाग लेने की बात कही जाती है। साल 1936 के शुरुआती महीनों में कांग्रेस ने फलस्तीन का खुलकर समर्थन किया और 27 सितंबर, 1936 को भारत में पहला फलस्तीन दिवस मनाया गया। सोचिए जरा, 1936 का पराधीन भारत भी फलस्तीनियों के साथ खड़ा था, पर आज यदि संसद में फलस्तीन की जय बोली जाती है, तो सदस्यता छीनने की मांग आ जाती है।

देखा जाए, तो असदुद्दीन ओवैसी ने संसद सदस्य की शपथ लेने के बाद 'जय फलस्तीन' का नारा लगाकर पूरी दुनिया को एक खास पैगाम दिया है कि हम और हमारा देश भारत हमेशा की तरह आज भी फलस्तीन और वहां की जनता के साथ मजबूती से खड़ा है। यह एक संदेश है कि इजरायल की नीतियों व उसकी नाइंसाफी का भारत पुरजोर विरोध करता है। अच्छा तो यह होता कि फलस्तीन का नाम लेने के कारण ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा किया जाता। उनकी बातों को और मजबूती से दोहराया जाता, ताकि पूरी दुनिया को पता चलता कि भारत कितना इंसाफ पसंद है। मगर इन सबके बजाय ओवैसी साहब को लानत मलामत भेजी जा रही है। क्या विडंबना है कि 2024 के भारत में 'जय फलस्तीन' बोलने पर विवाद हो रहा है, जबकि फलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने वाले पहले देशों में भारत भी रहा है। ओवैसी की आलोचना करने वाले बेशक उनकी नीतियों की अलोचना करें, लेकिन फलस्तीन पर उन्हें जिस तरह घेरा जा रहा है, वह उचित नहीं।

अतहर इमाम, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

फलस्तीन

संसद में लगाया गया एक अनुचित नारा

लोकसभा सदस्यों के शपथ ग्रहण में माननीय सांसदों द्वारा अपने मन के उद्गार और नायकों के सम्मान में लगाए गए नारे 'अनेकता में एकता' को प्रतिबिंबित कर रहे थे। जय श्रीराम, जय भीम, जय संविधान, भारत माता की जय के नारों से स्पष्ट लग रहा था कि सांसद अपनी पार्टी लाइन को ध्यान में रखते हुए जयघोष कर रहे हैं। सांसदों द्वारा इन नारों के जरिये अपनी भावना को व्यक्त करना किसी हद तक उचित जान पड़ रहा था, पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी का 'जय फलस्तीन' व सांसद छत्रपाल गंगवार का 'जय हिंदू राष्ट्र' का उद्घोष अनुचित माना जाएगा। इनकी स्वाभाविक ही निंदा हो रही। किसी विवादित विषय का यूं उद्घोष करना गलत है। यह ठीक है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते समय इसकी मर्यादा का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। अमर्यादित आचरण, वह भी सांसदों द्वारा, कतई सही नहीं ठहराए जा सकते। हम सभी अपेक्षा करते हैं कि सदन में राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर राष्ट्र की प्रगति, सुरक्षा के लिए और जनता के सवालों पर सार्थक बहस होगी और विवाद की जगह सार्थक संवाद होगा। माननीयों द्वारा संसद में एक मजबूत राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने की सहभागिता दिखाई देगी। मगर शुरुआत प्रतिकूल स्थितियों के साथ हुई है। फिर भी, लोकसभा में इस बार सतरंगी झलक दिखाई दे रही है, जिसमें भारत के 140 करोड़ लोगों की आशा पूरी होने की अपार संभावनाएं हैं।

विरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

भारत के नारे क्यों नहीं लगाए

एआईएमआईएम के मुखिया व हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ के पश्चात जो नारा लगाया, वह नहीं लगाना चाहिए था। यह सही है कि अन्य सांसदों ने भी शपथ के बाद अपने-अपने विचार से नारे लगाए, लेकिन ओवैसी का नारा सांविधानिक नहीं था। यही कारण है कि संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत उनको अयोग्य ठहराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। विरोध सिर्फ सांसद ही नहीं कर रहे, आम जनता में भी उनके इस कृत्य की तीखी प्रतिक्रिया हुई है। आखिर क्यों उन्होंने सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए फलस्तीन की जय का नारा लगाया? उन्होंने 'भारत माता की जय' क्यों नहीं कहा? हालांकि, अब इस नारे को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, बावजूद इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह के विवादित नारों, बयानों आदि से हमारे जन-प्रतिनिधियों को बचना चाहिए। इससे उनकी गरिमा भी बनी रहेगी और सदन की भी।

महेश नेनावा, टिप्पणीकार

संपादकीय

संगठन खड़ा करना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती

राजनीति में पूर्ण विराम नहीं होता। जहां हैं वहां भी टिके रहने के लिए दौड़ना पड़ता है, क्योंकि आर्थिक-शैक्षिक-सामाजिक (और इन दिनों धार्मिक) कारणों से भी जनता की सोच निरंतर बदलती है। मुकाबला अगर भाजपा जैसी पार्टी से है जो मजबूत संगठन, वैचारिक प्रतिबद्धता और धार्मिक कर्मकांड से अपनी ऊर्जा सिंचित करती हो, ऐसे में कांग्रेस की चुनौती और बढ़ जाती है। लेकिन गठबंधन की प्रमुख पार्टी का स्वयं अपना जनाधार बढ़ाना किसी भी गठबंधन के न बिखरने की पूर्व-शर्त है। सच है कि भारत में जनता का मत मूलतः नेता को मिलता है न कि पार्टी को। यानी आइडियोलॉजी से ज्यादा जनता चेहरे को वोट करती है। लेकिन नेता और जनता के बीच संगठन और उसके प्रतिबद्ध कार्यकर्ता वह कड़ी हैं, जो बिना दिखाई दिए अपना काम करते हैं। आज कांग्रेस के पास ऐसे संगठन, प्रतिबद्ध कैडर, राज्यों में भरोसेमंद नेताओं की कमी है। फिर कमजोर संगठन हो तो चुनाव जीतने के बाद भी सांसद और विधायक पाला बदलते देखे गए हैं। यह संगठन, खासकर आरएसएस जैसे ताकतवर संगठन की ताकत ही है जो दक्षिण और उत्तर-पूर्व में भाजपा का मत-प्रतिशत लगातार बढ़ता गया है। कांग्रेस नेतृत्व के लिए यात्राओं के जरिए जनसंपर्क के साथ ही गुजरने वाले जिलों में संगठन खड़ा करना अब नई जरूरत होगी।

प्रेरणा

गुणवत्ता कोई काम नहीं है, यह तो एक आदत है।
-अरस्तू

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
ptvijayshankarmehta.com

एआई के दौर में बच्चों का जीवन संतुलित रखना जरूरी

आजकल के बच्चों में एक नई बात देखी जा रही है। या तो वो इस पार होते हैं या उस पार। या तो वो बहुत बिगड़ चुके होते हैं या बहुत ही आज्ञाकारी, सुधरे हुए होंगे। इन दिनों बच्चे इस तरह असंतुलित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि माता-पिता का संतुलन चला गया। असंतुलित बच्चे होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया भर में सिर्फ भारत के बच्चों को सबसे पहले और कम उम्र में ही स्मार्टफोन थमा दिए गए हैं। यह आंकड़ा डराने वाला है। और उनके न्यूरो सर्किट पर इसका सीधा प्रभाव पढ़ रहा है। एक और दुखदायी आंकड़ा सामने आता है कि भारत में 78% बच्चे खाना खाते हुए मोबाइल देख रहे हैं। उनका स्क्रीन टाइम कम करना और जितनी देर वो स्क्रीन पर रहें वो गुणवत्तापूर्ण और उपयोगिता से भरा हो, यह जिम्मेदारी माता-पिता की है। और यहीं संतुलन होना चाहिए। इसलिए इस काम को समस्या न मानें, चुनौती मानें और बच्चों पर लगातार ध्यान दें। आने वाला समय एआई का होगा। एआई जब छा जाएगा तब संतुलित बच्चे खो जाएंगे। हमारे परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे।

•Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

मुद्दा • जीडीपी का 3 प्रतिशत निवेश ही शिक्षा पर होता है...

शिक्षा में बदहाली का सीधा संबंध बेरोजगारी से है

अभय कुमार दुबे
अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर
abhaydubey@aud.ac.in

नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने प्रेरक संकल्पों की सूची में एक इजाफा और कर दिया है। उन्होंने भारत को ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने की शपथ ले ली है। लेकिन उनके वक्तव्य की पृष्ठभूमि दोहरी और एक-दूसरे को काटने वाली है। एक तरफ हमारे एक प्राचीन विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार की महत्वाकांक्षी योजना है। दूसरी तरफ डॉक्टरी की नीट परीक्षा और यूजीसी-नेट परीक्षा के बहुचर्चित और बहुविवादित घोटालों के कारण मचा हुआ हंगामा है। इसी समय 12वीं तक पढ़ाई कर चुकी केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक सदस्य द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे चार आसान शब्द भी ठीक से न लिख पाने का प्रकरण भारतीय शिक्षा के एक दुखद रूपक की तरह हमारे सामने आ गया है।

जाहिर है कि आज की तारीख में हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली के स्तर पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। इसलिए इस विरोधाभास की रोशनी में प्रधानमंत्री के संकल्प और जमीनी हकीकत के संबंधों पर गौर करना जरूरी है। मोटे तौर पर हम शिक्षा की व्यवस्था को तीन चरणों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला चरण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को मिलाकर बनता है। बुनियादी तालीम के लिए जरूरी इस दौर को पार करते-करते विद्यार्थी शिशु से किशोर वय के आखिर में पहुंच जाता है। फिर शुरू होता है विश्वविद्यालय प्रणाली के तहत उच्च शिक्षा का दौर। इसके तहत बीए, एमए और पीएचडी वगैरह की डिग्रियां मिलती हैं। दरअसल, माध्यमिक शिक्षा खत्म होते-होते हमारे युवा और युवतियां तय करने लगते हैं कि वे शिक्षक बनेंगे या व्यापारी, पुलिस में जाएंगे या फौज में, वकील या न्यायाधीश, क्लर्क या नौकरशाह। या फिर वे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, मैनेजर आदि बनना पसंद करेंगे। यहीं से तरह-तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के चरण की निर्णायक भूमिका शुरू होती है। ये तीनों चरण संसाधनों की कमी, बदइंतजामी और भ्रष्टाचार की बहुतायत और स्तरहीनता से बेहाल हैं।

प्रधानमंत्री जिस अर्थव्यवस्था का पिछले दस साल से संचालन कर रहे हैं, उसके तहत शिक्षा पर जीडीपी का 3% के आसपास ही निवेश हो रहा है। जबकि इसे दोगुना होना चाहिए था। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की हालत यह है कि छात्र उत्तीर्ण होकर आगे की कक्षाओं में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें नीचे की कक्षाओं के बराबर पढ़ने और गणित की क्षमता नहीं होती। डिग्रियां लेने के बावजूद अकादमिक क्षमताएं निचले स्तर की होती हैं। ज्यादातर स्नातक बाजार के मानकों के लिहाज से रोजगार पाने लायक नहीं होते। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी का मार्केट पूरी तरह से निजी क्षेत्र में है। पुलिस या फौज के सिपाही से लेकर आईएएस-डॉक्टर-इंजीनियर र-मैनेजर तक की कोचिंग निजी खर्चे पर उपलब्ध है। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग लेकर हमारा युवा वर्ग प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठता है, वह पिछले बीस साल से मुतवातिर चल रहे राष्ट्रीय घोटाले की भेंट चढ़ जाता है। इस स्कैंडल का नाम है पेपर-लीक।

80 के दशक से पहले पेपर लीक की घटना अपवाद स्वरूप ही होती थी। आज पेपर लीक न हो, यह अपवाद है। नई शिक्षा नीति लागू हुई है। मौजूदा शिक्षा मंत्री 2021 से इसके इंचार्ज हैं। फिर भी बरसों से शिक्षा का एक भूमिगत बाजार सक्रिय है। संगठित होकर नकल कराने वाले माफिया के बारे में सभी को पता है। पर इस तथ्य से लोग जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं कि पंजाब, बिहार और यूपी जैसे राज्यों में न जाने कितने ऐसे अध्यापक हैं, जिनकी जगह कोई और पढ़ाता है। नियुक्ति पाने वाला केवल तनख्वाह उठाता है, और अपनी जगह पढ़ाने वाले को उसका एक हिस्सा दे देता है। प्रधानाचार्य की भी इसमें मिलीभगत होती है।

शिक्षा का अधिकांश हिस्सा सरकारी क्षेत्र में है, उसका तेजी से निजीकरण किया जा रहा है। पर इससे क्या बदलेगा? शिक्षा की बदहाली का सीधा संबंध बेरोजगारी की समस्या से है। फिर भी शिक्षा हमारी प्राथमिकताओं में कहीं नीचे है।

मोटी रकम देकर किसी भी विषय में पीएचडी की थीसिस लिखवाने का एक पूरा कुचक्र मुद्दतों से चल रहा है। हजारों-लाखों में कोई-कोई थीसिस ही ढंग की होती है। बाकी सभी स्तरहीन, घिसे-पिटे शोध, कट-पेस्ट या खानापूर्ति वाले फील्ड वर्क पर आधारित होती हैं। हमारे विश्वविद्यालय ज्ञानार्जन के केंद्र नहीं रह गए हैं। वे ज्यादा से ज्यादा कोर्स पूरा कराने के लिए होने वाली टीचिंग की जिम्मेदारी ही पूरी कर पाते हैं। उन्हें मिलने वाली रेटिंग एक छलावा भर है, क्योंकि वह पीएचडी की डिग्रियां बांटने की संख्या पर आधारित होती है। मौलिकता और अकादमिक श्रेष्ठता से पूरी तरह से वंचित शोध-प्रबंधों के आकलन की इस रेटिंग में कोई भूमिका नहीं होती। कथित उच्च शिक्षा पाया छात्र जब मुंह खोलता है तो न ठीक से हिंदी बोल पाता है, न अंग्रेजी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस आलेख पर सुझाव एवं प्रतिक्रिया देने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें

दूरदृष्टि • रुझान बताते हैं ट्रम्प बाइडेन से आगे हैं...

अमेरिकी चुनाव नतीजों का दुनिया पर बहुत असर होगा

मनोज जोशी
'अंडरस्टैंडिंग द इंडिया चाइना बॉर्डर' के लेखक
manoj1951@gmail.com

जब आप मौजूदा वैश्विक परिदृश्य को देखते हैं तो आपको बहुत उथल-पुथल और अशांति दिखाई देती है। हमास-इजराइल युद्ध जारी है, रूस-यूक्रेन युद्ध चल रहा है, चीन और ताइवान-फिलीपींस के बीच तनाव है और उसके साथ हमारी अपनी समस्याएं भी हैं। लेकिन फिलहाल तो हम सभी को अमेरिका में चल रहे घटनाक्रम के बारे में चिंता करने की जरूरत है, जहां राजनीति इतनी विभाजित है कि हालात गृहयुद्ध के समान हैं। नवंबर में चुनाव होंगे, जिसके नतीजे ट्रम्प के हारने की स्थिति में रिपब्लिकन द्वारा स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है। बड़ी संख्या में अमेरिकियों ने 2020 के परिणामों को भी स्वीकार नहीं किया था और कुछ ने नतीजों को उलटने की भी कोशिश की थी। इस बार हालात और खराब हो सकते हैं।

अब ऐसा लगने लगा है कि ट्रम्प जीत सकते हैं, जो कि एक चिंताजनक मसला होगा। अमेरिका में अभूतपूर्व रूप से 34 बार उन्हें दोषी ठहराया गया है। सामान्य परिस्थितियों में वे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तक नहीं होते, लेकिन वे उम्मीदवार चुने गए हैं और चुनावों में बढ़त बनाए हुए हैं। दरअसल न्यूयॉर्क में हश-मनी (मुंह बंद रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा)- जिसके कारण उन पर दोष सिद्ध हुआ- उनके खिलाफ दर्ज मामलों में सबसे कम गंभीर है। जॉर्जिया में ट्रम्प के खिलाफ फर्जी मतदाताओं का उपयोग करके 2020 के चुनाव-परिणामों को पलटने की कोशिश करने का मामला दर्ज है। फ्लोरिडा में वर्गीकृत सरकारी दस्तावेजों को चुराने और फिर उनके बारे में झूठ बोलने का गंभीर मामला दर्ज है। वाशिंगटन डीसी में 6 जनवरी, 2021 को बलवे को बढ़ावा देने का मामला दर्ज है। इसमें संदेह नहीं कि अमेरिकी लोकतंत्र अभी संकट में है।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अजीबोगरीब होते हैं। उसमें मतदाता किसी उम्मीदवार के लिए नहीं, बल्कि अपने राज्य के निर्वाचकों (इलेक्टर्स) के समूह के लिए वोट करता है। ये निर्वाचक एक निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं जो चुनाव के तुरंत बाद मिलते हैं और अपने राज्य में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वोट देने के लिए बाध्य होते हैं। दो को छोड़कर सभी राज्य 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली का पालन करते हैं, जिसमें लोकप्रिय वोट जीतने वाली पार्टी सभी निर्वाचकों को अपने पाले में ले आती है। प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर एक निश्चित संख्या में निर्वाचक मिलते हैं। कैलिफोर्निया में 55 निर्वाचक हैं, टेक्सास में 38, जबकि उत्तरी और दक्षिणी डकोटा में केवल 3-3 निर्वाचक हैं। सभी राज्यों को मिलाकर कुल 538 निर्वाचक हैं। 270 इलेक्टोरल वोट जीतने वाला उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है, भले ही लोकप्रिय वोट कैसा भी रहा हो। इसलिए 2016 के चुनाव में हिलेरी क्लिंटन को 48.2 प्रतिशत वोट मिले और डोनाल्ड ट्रम्प को 46.1 प्रतिशत, फिर भी ट्रम्प चुनाव जीत गए क्योंकि उन्हें 304 इलेक्टोरल वोट मिले, जबकि हिलेरी को 227 ही वोट मिले।

चुनाव-विश्लेषकों का कहना है कि अधिकांश राज्यों में परिणाम पूर्वानुमानित होते हैं। लेकिन कोई सात ऐसे राज्य हैं, जहां के परिणाम अनिश्चित रहते हैं। ये राज्य ही चुनाव परिणामों को निर्धारित करते हैं। इनमें लोकप्रिय वोट का अंतर नगण्य होता है। कहा जाता है कि इन 7 राज्यों में फैले केवल 2 लाख मतदाताओं की मतदान-प्राथमिकता वास्तव में पूरे राष्ट्रपति चुनाव का फैसला करती है। ये हैं- पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, उत्तरी कैरोलिना, नेवादा, एरिजोना और जॉर्जिया। वाशिंगटन पोस्ट ने अपने गुरुवार के संस्करण में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मतदान डेटा के औसत के आधार पर एक सर्वेक्षण-विश्लेषण प्रकाशित किया है, जो दर्शाता है कि ट्रम्प इन 7 राज्यों में से 5 में आगे हैं। 2020 में बाइडेन ने इन 7 में से 6 राज्य जीते थे।

डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने पर सबसे बड़ा बदलाव यूक्रेन में हो सकता है, जहां ट्रम्प राष्ट्रपति जेलेंस्की के खास समर्थक नहीं हैं। संघर्ष-विराम की मांग होगी और इसमें यूक्रेन अपने क्षेत्र का 20% या उससे अधिक हिस्सा खो सकता है।

भारत के ट्रम्प और बाइडेन दोनों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, जिसके मद्देनजर नतीजों का सीधा असर भारत पर नहीं पड़ेगा। लेकिन वे अन्य जगहों पर स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। बाइडेन प्रशासन ने चीन पर ट्रम्प के सख्त रुख का पालन किया है, इसलिए वहां भी कम बदलाव होगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यूक्रेन में हो सकता है, जहां ट्रम्प राष्ट्रपति जेलेंस्की के खास समर्थक नहीं हैं। हाल ही में उनके दो पूर्व सलाहकारों ने ऐसी योजना का खुलासा किया था, जिसके तहत संघर्ष-विराम की मांग होगी और इसमें यूक्रेन अपने क्षेत्र का 20% या उससे अधिक हिस्सा खो सकता है। दक्षिण कोरिया और जापान के प्रति भी ट्रम्प के मन में तिरस्कार की भावना है और इन दोनों का संघर्ष चीन से रहता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

https://t.me/AllNewspaperPdf

भास्कर खास

ब्रांड सक्सेस स्टोरी

जॉनसन एंड जॉनसन | फार्मा कंपनी, कब बनी- 1886, मार्केट कैप- 29 लाख करोड़ रु.

जॉनसन एंड जॉनसन : सबसे मूल्यवान फार्मा कंपनी, 61 हजार मुकदमे भी

अमेरिका की 138 साल पुरानी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन... छह सालों से बेबी पाउडर को लेकर विवादों में फंसी है, दूसरी ओर कमाई भी बढ़ रही है। इस विवाद में 61 हजार से ज्यादा मुकदमे झेल रही कंपनी ने इसी महीने 5,849 करोड़ रुपए में सेटलमेंट किया है, दूसरी ओर ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के मुताबिक यह दुनिया की सबसे मूल्यवान फार्मा कंपनी (मोस्ट वैल्युएबल) बनी हुई है। सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के कारण भारत को 'दुनिया की फार्मेसी' कहा जाता है, लेकिन कमाई के मामले में अमेरिका की फार्मेसी कंपनियों का एकाधिकार है। मार्केट कैप के लिहाज से टॉप-20 फार्मा कंपनियों में 12 अमेरिका की हैं। इसमें तीसरे नंबर पर जॉनसन एंड जॉनसन है। क्या है इसका इतिहास, ब्रांड स्टोरी में पढ़ते हैं।

1947 से भारत में कारोबार, 6 हजार से ज्यादा कर्मचारी

अमेरिका के न्यूजर्सी स्थित कंपनी का मुख्यालय।

साल 1947 में जॉनसन एंड जॉनसन ने बेबी पाउडर की ब्रांडिंग के साथ भारत में व्यापार शुरू किया था। दस साल बाद कंपनी ने भारत में अलग इकाई स्थापित की। वहीं 1959 में मुंबई में पहली उत्पादन इकाई शुरू की। कंपनी की भारत में पिछले साल 500 करोड़ रुपए की कमाई रही। जॉनसन एंड जॉनसन की दुनिया के 60 देशों में में 270 से ज्यादा ऑपरेटिंग कंपनियां हैं , वहीं कंपनी 175 से ज्यादा देशों में अपनी दवाएं और हेल्थकेयर उत्पाद बेचती है।

शुरुआत: जब सर्जिकल उत्पाद बनाकर कंपनी की नींव रखी

अमेरिका में साल 1861 से शुरू हुए गृहयुद्ध में 7 लाख से ज्यादा लोगों की जानें गईं। संक्रमण और बीमारियां चरम पर थीं। ऐसे हालात देखकर 16 साल के रॉबर्ट वुड जॉनसन के मन में हेल्थकेयर के प्रति रुचि जागी। वुड ने परिवार की दवा की दुकान में काम शुरू कर दिया। एंटीसेप्टिक सर्जरी को बढ़ावा दे रहे डॉ. जोसेफ लिस्टर को सुनने के लिए साल 1885 में जॉनसन एक कॉन्फ्रेंस में गए। डॉ. लिस्टर के एंटीसेप्टिक तरीकों से प्रेरित होकर रॉबर्ट वुड जॉनसन ने अपने दो छोटे भाइयों और एक बिजनेस पार्टनर सीबुरी के साथ मिलकर साल 1886 में जॉनसन एंड जॉनसन की नींव रखी और सर्जिकल उत्पादों का बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू किया।

▪ *अमेरिका में रेल लाइंस बिछाने के दौरान दुर्घटनाओं को देखकर जॉनसन भाइयों को फर्स्ट एड किट बनाने का आइडिया आया था।*

मार्केट : बैंड-एड ईजाद की, विज्ञापनों ने घर-घर पहुंचाया

18वीं सदी में अधिकांश प्रसव घर पर ही होते थे। इस दौरान संक्रमण से मां- बच्चे दोनों की जान को खतरा होता था। इसे देखते हुए जॉनसन ब्रदर्स ने साल 1894 में पहली मेटरनिटी किट पेश की। इसी साल जॉनसन का बेबी पाउडर भी बिक्री के लिए मार्केट में आया। यह भी बेहद सफल रहा। बैंड-एड का आइडिया भी जरूरत के चलते आया। अर्ले डिक्सन इसी कंपनी में काम करते थे। उनकी पत्नी जोसेफिन को अक्सर किचन में चोट लग जाती थी। इसी से डिक्सन को एक आइडिया आया। उन्होंने दवाओं की ढेर सारी रेशमी पट्टियों को काटकर उसको टेप के ऊपर चिपका दिया। और 1920 के बाद से 'बैंड-एड' बनाने शुरू कर दिए।

▪ *विज्ञापनों पर खर्च करने में भी कंपनी आगे है। इसने साल 2022 में 2.1 अरब डॉलर (17 हजार करोड़ रु) विज्ञापनों पर खर्च किए।*

चुनौती : सर्वाधिक कमाई वाली दवा का पेटेंट खत्म हुआ

जॉनसन एंड जॉनसन की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा Stelara का पेटेंट पिछले साल खत्म हो गया है। सोरायसिस का उपचार करने वाली इस दवा से कंपनी को पिछले साल 10.9 अरब डॉलर की कमाई हुई थी। यह दुनिया में सर्वाधिक बिकने वाली टॉप-10 दवाओं में भी शामिल है। अब पेटेंट खत्म होने से कंपनी की कमाई पर भी असर पड़ने की आशंका है। हालांकि कंपनी 2025 तक इसे अमेरिका में बेच सकेगी। लेकिन दुनिया के बाकी प्रांतों में अन्य कंपनियां इस दवा को बेच सकेंगी। वहीं इसकी दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा Darzalex का पेटेंट 2027 में खत्म होने वाला है। इससे कंपनी को पिछले साल 9.7 अरब डॉलर की कमाई हुई थी।

▪ *कंपनी की दवाओं से 50% कमाई होती है, वहीं 30% कमाई चिकित्सा उपकरणों और 20% कमाई उपभोक्ता उत्पादों से होती है।*

विवादों से नाता : समझौते के तहत 5849.45 रुपए चुकाएगी, दस साल पहले भी चुकाए थे 18 हजार करोड़

फार्मा कंपनियों के लिए मुकदमेबाजी नई बात नहीं है। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर और अन्य टेल्कम उत्पादों में कैंसर कारकों की उपस्थिति के आरोप के बाद कंपनी की साख को काफी क्षति पहुंची। साल 2022 (साल की समाप्ति पर 38 लाख करोड़ रु. मार्केट कैप थी) से कंपनी की मार्केट कैप घट रही है। हालांकि कमाई बढ़ रही है। बेबी पाउडर मामले को लेकर कंपनी पर 61 हजार से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। केस करने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं। इसी महीने कंपनी ने 42 अमेरिकी राज्यों और वाशिंगटन, डीसी द्वारा एक जांच के बाद मामले को रफा-दफा करने के लिए 700 मिलियन डॉलर (5849.45 करोड़ रुपए) के समझौते पर सहमति व्यक्त की है। इससे पहले साल 2013 में कंपनी को एक दवा Risperdal की मार्केटिंग में अनियमितताओं का भी दोषी पाया गया था। इसके लिए कंपनी ने 2.2 अरब डॉलर (लगभग 18 हजार करोड़ रु.) का सेटलमेंट किया था।

पीपुल भास्कर

चर्चा में | राशिद खान , अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान

रिफ्यूजी कैंप में रहे, यूट्यूब से गेंदबाजी सीखी, राशिद अब टी20 के सुपर स्टार

जन्म: 20 सितंबर 1998, नांगरहार प्रांत, अफगानिस्तान
परिवार: पिता और 10 भाई-बहन
शिक्षा: पाकिस्तान के इस्लामिया कॉलेज से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई
संपत्ति- लगभग 30 करोड़ रुपए
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार

उनकी कप्तानी में पहली बार अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम किसी आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंची है।

अफगानिस्तान की टीम भले ही टी-20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में हार गई हो, लेकिन उनके यहां तक के सफर को पूरे क्रिकेट जगत में सराहा जा रहा है। खासकर टीम के कप्तान राशिद खान का नाम इस समय हर क्रिकेट प्रेमी की जुबान पर है। उनकी कप्तानी में टीम ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों को टूर्नामेंट में हराकर पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई।

कप्तान राशिद खान का यहां तक का सफर आसान नहीं रहा है। उनका बचपन बेहद कठिनाई में बीता। 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिका और तालिबान के बीच छिड़े युद्ध ने उनके परिवार को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवार अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान बॉर्डर के पास रिफ्यूजी कैंप में रहने लगा उस समय राशिद की उम्र केवल 3 साल थी। हालात सुधरने के बाद परिवार लौटा, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही स्थिति बनी तो पूरा परिवार पाकिस्तान लौट गया। यहीं पेशावर की गलियों में खेलते हुए उनका जीवन आगे बढ़ा। एक बार राशिद को अचानक अंग्रेजी बोलने का जुनून सवार हो गया। मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद उन्होंने 6 महीने तक अंग्रेजी की स्पेशल ट्यूशन ली । इसके बाद खुद इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाने लगे।

क्रिकेट के अलावा वे फुटबॉल के जबर्दस्त फैन हैं। एक साक्षात्कार में राशिद ने बताया था कि अगर वे क्रिकेटर नहीं होते तो फुटबॉल में करियर बनाते। उन्हें बॉलीवुड फिल्मों का बेहद शौक है। सलमान उनके फेवरेट एक्टर हैं।

राशिद कह चुके हैं कि अगर वे क्रिकेटर नहीं होते तो फुटबॉलर बनते

शुरुआती जीवन : राशिद को डॉक्टर बनाना चाहती थी मां

राशिद खान का जन्म अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में हुआ था। पिता खोदादाद खान टायर व्यवसायी थे। राशिद पढ़ाई में बेहद होशियार थे। उनकी मां का सपना था कि राशिद बड़े होकर डॉक्टर बनें, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिका के बीच बार-बार होने वाले युद्ध के कारण उन्हें कभी अफगानिस्तान तो कभी पाकिस्तान में रहना पड़ा। इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई। जब राशिद बड़े हो रहे थे उस समय पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी का खुमार लोगों पर छाया हुआ था। उनको देखकर राशिद ने भी वैसी ही बैटिंग और स्पिन सीखी। क्रिकेट के अभ्यास के लिए वे भाइयों के साथ घंटों खेलते। और इस तरह उनका क्रिकेटर बनने का सफर शुरू हुआ। राशिद के 6 भाई और 4 बहनें हैं।

करियर : 21 साल की उम्र में बने अफगानिस्तान टीम के कप्तान

मात्र 17 साल की उम्र में 2015 में राशिद खान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वन-डे और टी 20 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। इसके बाद 2018 में उन्होंने भारत के खिलाफ पहला टेस्ट खेला। 2019 में मात्र 21 साल की उम्र में उन्हें टीम के तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) का कप्तान बना दिया गया। हालांकि इसी साल उन्हें हटाकर असगर अफगान को कप्तानी दे दी गई। राशिद ने अब तक कुल 201 मैचों (टेस्ट, वनडे और टी20) में 269 विकेट लिए हैं। उनके नाम मात्र 53 मैचों में 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने का रिकॉर्ड है। अंतरराष्ट्रीय मैचों के अलावा राशिद आईपीएल और बीबीएल सहित दुनियाभर की लगभग सभी बड़ी क्रिकेट लीग में खेलते हैं। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें एक बार फिर से टीम का कप्तान बनाया गया था।

रोचक : धाराप्रवाह पांच भाषाएं बोल लेते हैं राशिद

- उन्होंने बॉलिंग से जुड़े कई गुर यूट्यूब से सीखे हैं। अच्छी कोचिंग की व्यवस्था न होने पर वे पसंदीदा स्पिनर्स की तकनीक वीडियो देखकर सीखते थे।
- कई पाकिस्तानी और अफगान प्रशंसक उन्हें 'अफगान अफरीदी' भी कहते हैं। पाकिस्तान के हरफनमौला खिलाड़ी शाहिद अफरीदी उनके आदर्श रहे हैं।
- राशिद पाकिस्तान की घरेलू टीम की ओर से भी खेल चुके हैं। 2013 में पाकिस्तान-अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच हुए टूर्नामेंट में पाकिस्तान की 'सिबी' टीम की ओर से खेले थे।
- उनके 6 भाई हैं और सभी अच्छे गेंदबाज हैं।
- 2020 में आईसीसी ने राशिद खान को दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया था।
- राशिद खान पश्तो , दारी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी फर्राटेदार बोल लेते हैं।

कल्पमेधा

सुधार के बिना पश्चाताप कुछ इस तरह है जैसे सुराख बंद किए बिना जहाज में से पानी निकलना।

– पामर

जांच की आंच

राजधानी दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले की जांच अब बहुकोणीय हो गई है। पहले प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले में गिरफ्तार किया था, अब केंद्रीय जांच एजंसी यानी सीबीआइ ने भी उन्हें हिरासत में ले लिया है। सीबीआइ का कहना है कि दिल्ली की आबकारी नीति बनाने में दक्षिण भारत का एक समूह शामिल था और उससे केजरीवाल जुड़े हुए थे। इस मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए केजरीवाल का सबूतों से आमना-सामना कराना और उनसे पूछताछ जरूरी है। अदालत ने सीबीआइ की इस दलील को उचित मानते हुए केजरीवाल की तीन दिन की हिरासत मंजूर कर दी। माना जाता है कि सीबीआइ को कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगे होंगे, तभी उसने हिरासत की मांग की। मगर हमेशा की तरह आम आदमी पार्टी इस मामले को सियासी हथकंडा करार दे रही है। कुछ दिनों पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। उसने प्रवर्तन निदेशालय के पास केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पुख्ता सबूत न होने को लेकर नाराजगी भी जताई थी। मगर प्रवर्तन निदेशालय ने उस जमानत आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में गुहार लगाई और जमानत पर स्थगन आदेश मिल गया। इसे लेकर अभी चर्चाएं चल ही रही थीं कि सीबीआइ ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।

दिल्ली शराब घोटाले की सच्चाई अभी रहस्य के पर्दे में है। आम आदमी पार्टी के कई नेता इसकी जांच की जद में आ चुके हैं। उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में हैं। संजय सिंह जेल जाकर आ चुके हैं। कयास लगाए जाते हैं कि और भी कुछ नेताओं तक इस जांच की आंच पहुंच सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध ठहराने की कानूनी लड़ाई चल रही है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने आम चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए मोहलत दी थी, पर फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। अब सीबीआइ ने एक नया सिरा पकड़ लिया है, तो केजरीवाल की रिहाई आसान नहीं लगती। केजरीवाल ने अभी तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। चूंकि ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति को किसी आरोप में गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा देना अनिवार्य है, इसलिए उन्होंने अपने पद पर बने रहने का फैसला किया। मगर सार्वजनिक जीवन में सब कुछ कानून से नहीं चलता, जनभावनाएं भी महत्त्वपूर्ण होती हैं। आम लोगों की यही अपेक्षा रहती है कि अगर किसी बड़े पद का निर्वाह कर रहे व्यक्ति पर कोई गंभीर आरोप लगे, तो वह नैतिक आधार पर खुद को उस पद से अलग कर ले।

चूंकि कथित शराब घोटाला मामले को राजनीतिक रंग दे दिया गया है और इसे लेकर अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आ सका है, इसलिए लोगों में भ्रम बना हुआ है। आम आदमी पार्टी और भाजपा एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। ताजा मामले में भी आम आदमी पार्टी का तर्क है कि केंद्र सरकार केजरीवाल को इस मामले में उलझाए रख कर सीखचों के पीछे रखने का प्रयास कर रही है। मगर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को जब इस तरह सियासी रंग दे दिया और लंबे समय तक उलझाए रखा जाता है तो उससे आम लोगों का भरोसा कमजोर होता है। अगर सचमुच दिल्ली की आबकारी नीति गलत थी और उसके चलते कुछ लोगों को नाजायज लाभ पहुंचाया गया, तो इसकी सच्चाई जल्दी सामने आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी से भी अपेक्षा की जाती है कि वह इस जांच में सहयोग करेगी।

सुस्ती का रोग

जब किसी व्यक्ति को सुस्त देखा जाता है, तो इसका सीधा अर्थ यही लगाया जाता है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर वह आलसी है। मगर यह इसलिए भी संभव है कि उसकी सक्रियता में कई वजहों से कमी आ रही हो और उसका कारण कोई शारीरिक बीमारी नहीं हो। हालांकि बीमारी की वजह से अगर सक्रियता में कमी आती है तो यह भी सही है कि सक्रियता में कमी से शरीर में बीमारी घर बनाती है। विडंबना यह है कि वक्त के साथ विस्तृत होते दायरे के बीच ज्यादातर लोगों की व्यस्तता तो बढ़ी है, मगर उनकी शारीरिक सक्रियता में तेजी से कमी आई है। 'द लांसेट ग्लोबल हेल्थ' जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में यह उजागर हुआ है कि सन 2022 में भारत की सत्तावन फीसद महिलाएं शारीरिक रूप से पर्याप्त सक्रिय नहीं थीं, जबकि पुरुषों में यह दर बयालीस फीसद थी। अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि अगर मौजूदा परिपाटी जारी रही तो 2030 तक भारत में अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता वाले वयस्कों की संख्या बढ़ कर साठ फीसद तक पहुंच जाएगी।

अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी देश की साठ फीसद आबादी अगर शारीरिक रूप से पर्याप्त सक्रिय नहीं रहे तो आने वाले वक्त में वहां आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कैसी तस्वीर बनेगी। आमतौर पर अधिक आबादी वाले देशों में रोजी-रोटी का मसला इस तरह जटिल होता है कि ज्यादातर लोगों को जीवन चलाने के लिए शारीरिक रूप से जरूरत से ज्यादा सक्रिय रहना पड़ता है। सवाल है कि आखिर भारत में ऐसे हालात कैसे पैदा हो रहे हैं कि यहां इतनी बड़ी तादाद में लोग सुस्त होते जा रहे हैं! विचित्र यह भी है कि लोगों की व्यस्तता में एक अजीब किस्म की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे तमाम लोग हैं, जिनका आधे घंटे का कोई काम टलता रहता है, मगर रोजाना वे पांच या सात घंटे या इससे ज्यादा समय अपने स्मार्टफोन या अन्य तकनीकी संसाधनों पर, सोशल मीडिया या अन्य आभासी मंचों पर बर्बाद करते हैं। महामारी के दौरान घर से काम करने की व्यवस्था जब चलन में आई थी, उसने भी लोगों के ज्यादा शिथिल होने में भूमिका निभाई। शारीरिक सक्रियता में कमी की वजहों और नतीजों पर अगर गौर नहीं किया गया तो इन सबका समुच्चय आखिर व्यक्ति को विचार से कमजोर करेगा, शरीर को बीमार बनाएगा।

भुखमरी के आगोश में पलता बचपन

दुनिया का हर चार में से एक बच्चा युद्ध, वैश्विक अशांति, असमानता, गरीबी और जलवायु संकट की वजह से गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा है।

सोनम लववंशी

कहने को तो दुनिया आधुनिक हो चुकी है, लेकिन सामाजिक मूल्यों का पतन साफ देखा जा सकता है। दुनिया में एक तरफ जहां अन्न की बर्बादी अपने चरम पर पहुंच गई है, तो दूसरी तरफ भूख और कुपोषण गंभीर समस्या बनती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की ताजा रपट के मुताबिक दुनिया में पांच वर्ष से कम आयु के 27 फीसद यानी करीब 18 करोड़ बच्चे गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। पर्याप्त भोजन की कमी से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। दुनिया का हर चार में से एक बच्चा युद्ध, वैश्विक अशांति, असमानता, गरीबी और जलवायु संकट की वजह से गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिल्बर्ट हुंगबो ने कहा कि भूख मिटाने के लिए दुनिया भर में करोड़ों बच्चों को स्कूल के बजाय मजदूरी के लिए भेजा जा रहा है। यहां तक कि उन्हें गलत कामों के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। दुनिया के लगभग सोलह करोड़ बच्चे ऐसे हालात में संघर्ष कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की 'खाद्य बर्बादी सूचकांक-2024' रपट के अनुसार पिछले एक वर्ष में 1.05 अरब टन भोजन बर्बाद हो गया, जिसमें से करीब बीस फीसद खाद्य कूड़े में फेंक दिया गया। बाजार में उपलब्ध खाद्य उत्पादों का लगभग पांचवां हिस्सा बर्बाद कर दिया जा रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की एक रपट के मुताबिक प्रति वर्ष सबसे ज्यादा 63.1 करोड़ टन यानी लगभग 60 फीसद भोजन घरों में बर्बाद चला जा रहा है। एक तरफ जहां लाखों लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, वहीं दुनिया के संपन्न परिवारों में हर व्यक्ति दो कुंतल भोजन हर वर्ष बर्बाद कर रहा है। अन्न की यह बर्बादी अब वैश्विक त्रासदी बनती जा रही है। यहां तक कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान का भी सबब बन रही है। भोजन की यह बर्बादी संपन्न ही नहीं, पिछड़े देशों में भी समान रूप से देखी जा सकती है। उच्च, उच्च मध्यम और निम्न मध्यम आय वाले देशों के बीच प्रति व्यक्ति वार्षिक खाद्य अपशिष्ट दर में केवल सात किलोग्राम का फर्क देखा गया है, लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच इस बर्बादी की मात्रा बहुत अलग है। मध्यम आय वाले देशों में ग्रामीण आबादी अपेक्षाकृत कम भोजन बर्बाद करती है। संयुक्त राष्ट्र की कोशिश है कि भोजन की बर्बादी 2030 तक पचास फीसद कम की जाए।

अकेले भारत में 68 लाख बच्चे भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। यह संख्या सूडान, माली जैसे देशों से भी ज्यादा है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2023 के मुताबिक, इस त्रासदी की जद में काम पर जाने वाले बच्चे और किशोर ही नहीं, बल्कि उनमें 6 से 11 माह के 30 फीसद, 12 से 17 माह के 13 फीसद और 18 से 23 माह के 18 फीसद शिशु भी शुमार हैं। इस बीच हमारे देश में अल्प-पोषण व्यापकता 14.6 फीसद से बढ़ कर 16.3 फीसद हो चुकी है। ऐसे में

कुपोषित बच्चों की निगरानी और उन्हें इस जटिल हालात से उबारने के लिए कोई व्यापक नीति बनाना भी सरकारों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुका है। आंकड़ों के मुताबिक, हमारे देश में लगभग 60 फीसद बच्चे दुग्ध आदि पोषक आहार से वंचित रह जाते हैं।

भुखमरी और कुपोषण की सबसे बड़ी वजह आर्थिक असमानता, निर्धनता और महंगाई है। आज आबादी का एक बड़ा हिस्सा खाद्य पदार्थ और स्वच्छ पेयजल से वंचित होता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह सरकारी योजनाओं और नीतियों का समुचित क्रियान्वयन न हो पाना है। विश्व में युद्ध और सूखा, बाढ़, भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने भी इसे जटिल बना दिया है। कृषि गतिविधियां छिन्न-भिन्न हो रही हैं। खाद्य उत्पादन का असमान वितरण हो रहा है। भारत में गरीबी और बालश्रम के खतरनाक नतीजे बच्चों के शोषण के रूप में सामने आ रहे हैं।

संविधान का अनुच्छेद 21 सभी को निर्बाध जीवन जीने की आजादी देता है। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। इसके लिए संविधान बच्चों को कई अधिकार भी देता है। पर बच्चे वोटबैंक की राजनीति का हिस्सा नहीं होते हैं, शायद इसीलिए बच्चे सरकार की प्राथमिकता में नहीं आते हैं और न ही उनके लिए बनाई गई नीतियों का उचित तरीके से क्रियान्वयन किया जाता है।

भुखमरी और कुपोषण की सबसे बड़ी वजह आर्थिक असमानता, निर्धनता और महंगाई है। आज आबादी का एक बड़ा हिस्सा खाद्य पदार्थ और स्वच्छ पेयजल से वंचित होता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह सरकारी योजनाओं और नीतियों का समुचित क्रियान्वयन न हो पाना है। विश्व में युद्ध और सूखा, बाढ़, भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने भी इसे जटिल बना दिया है। कृषि गतिविधियां छिन्न-भिन्न हो रही हैं। खाद्य उत्पादन का असमान वितरण हो रहा है। भारत में गरीबी और बालश्रम के खतरनाक नतीजे बच्चों के शोषण के रूप में सामने आ रहे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया में गेहूं का सरकारी भंडारण कम हो रहा है। भारत में ही पिछले एक साल में गेहूं का दाम आठ फीसद तक बढ़ गया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अनाज की पर्याप्त खरीदी नहीं हो पा रही है, जबकि सरकार मुफ्त अनाज योजना, बीपीएल धारकों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने की योजना चला रही है। ऐसे में यह भूख देश और समाज के लिए काफी महंगी पड़ने वाली है।

एक रपट के मुताबिक 2022 के मुकाबले 2023 में दो करोड़ चालीस लाख लोगों ने भुखमरी का सामना किया। इसके पीछे बड़ी वजह सूडान और गाजा जैसे क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा में आई भारी गिरावट है। जो देश युद्ध और संघर्ष की मार झेल रहे हैं वहां भुखमरी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दक्षिण सूडान में करीब उन्यासी हजार लोग ऐसे हैं, जो भुखमरी के पांचवे चरण में पहुंच गए हैं। जलवायु परिवर्तन भी भुखमरी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। अल-नीनो 2024 में अपने चरम पर है, जिसका सीधा प्रभाव खाद्य सुरक्षा पर पड़ा है। इसके कारण पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में कम बारिश और बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। अल-नीनो दक्षिण अफ्रीका में आए भयंकर सूखे की एक बड़ी वजह रहा है। अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन आक्सफैम की एक रपट के अनुसार इस सूखे के कारण इस इलाके में दो करोड़ चालीस लाख लोगों को भुखमरी, पानी की कमी और कुपोषण का सामना करना पड़ा।

सीधी-सी बात है कि भूख की कोई सीमा, कोई सरहद नहीं होती है। यह बच्चों पर भी कोई रहम नहीं करती। दुनिया में हर पांच में से एक बच्चा कुपोषण का शिकार है। इसका अर्थ है कि बच्चों को उचित आहार नहीं मिल पा रहा। यह सिर्फ स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि संकेत है कि हम अपने समाज और मानवता के प्रति कर्तव्यों को निभाने में विफल हो रहे हैं। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, तो यह माता-पिता नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता है। बच्चों को भूख से बचाना है तो सभी देशों को साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। बच्चे स्वस्थ समाज की नींव हैं। जब नींव ही कमजोर हो जाएगी तो फिर समाज कैसे आगे बढ़ेगा। एक तरफ तो दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के चमकते आंकड़े विकास और तरक्की के बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ 78.3 करोड़ लोगों को तो यह तक खबर नहीं कि उनको अगला भोजन मिलेगा भी या नहीं। यह कैसा विकास है!

आबोहवा की फिक्र

अमित चमड़िया

आमतौर पर हम अपने आसपास समाज और अर्थ की सुविधा-असुविधा और जटिलताओं में गुम होते हैं और राजनीतिक मुद्दों पर हमारा ध्यान सिर्फ चुनावों के वक्त ही जाता है। जबकि सच यह है कि राजनीति हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है। सामाजिक जीवन के दायरे में ही अब देश-दुनिया की आबोहवा की मुश्किलें और उससे जुड़े मुद्दों को भी देखा जा सकता है, जिसे देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में लिए गए राजनीतिक फैसले प्रभावित करते हैं, मगर किसी चुनाव में पर्यावरण और इससे संबंधित बिंदु शायद कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाते।

हमने पर्यावरण को अपनी दिनचर्या से जोड़ने का प्रयास कभी नहीं किया, जबकि पर्यावरण के नुकसान का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे दिनचर्या पर ही पड़ता हैं। हम लोग बड़े होते ही अपनी जाति और धर्म के बारे पहले सोचने लगते हैं, उसके बाद भूख और रोजगार जैसे मुद्दों में अपनी जिंदगी को उलझा पाते हैं और उन्हीं पर बात करते हैं, भले ही उसका हासिल शून्य हो। इसी तरह, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुडी चीजें भी शायद ही कभी चुनाव में मुद्दा बन पाती हैं। व्यापक प्रभाव के लिहाज से देखें तो इन सबमें पर्यावरण का मुद्दा इन सब मुद्दों से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।

दुनिया मेरे आगे

पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हम अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं करते हैं, मगर पर्यावरण में आ रहे बदलावों की मार झेलते रहते हैं। हमारे कई तौर-तरीके वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। हमें अब 'बैक टू नेचर' यानी प्रकृति के पास जैसे अभियान को चलाने के बारे में गंभीरता से सोचना होगा।

पर्यावरण को होने वाले नुकसान का प्रभाव केवल स्थानीय नहीं होता, धरती का एक बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित होता है। पर्यावरण से जुड़े छोटे-छोटे मानवीय प्रयास पर्यावरण को ठीक रखने में कहीं न कहीं अपना योगदान देते हैं, जिसका आभास हमें नहीं होता है। इसी तरह का प्रयास देश के एक बड़े अनुसंधान संस्थान में प्रयोग के तौर पर किया गया, जिसमें वहां हर सोमवार को कर्मचारियों के बीच 'रिंकल अच्छे हैं' अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत उस संस्थान के सभी कर्मचारियों को बिना इस्त्री किए कपड़े पहनने पर जोर दिया गया है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि एक जोड़े कपड़े की इस्त्री करने से जो बिजली खपत होती है, उस बिजली के खर्च से लगभग दो सौ ग्राम कार्बन डाइआक्साइड गैस वातावरण मे फैलती है।

आजकल यह माना जाता है कि इस गैस का वायुमंडल में ज्यादा होना जीवन के लिए खतरनाक है। वास्तव में यह अभियान जलवायु में हो रहे बदलाव से पैदा होने वाले संकट के विरुद्ध एक सांकेतिक लड़ाई हैं। इस समय जबकि जलवायु में बड़ा परिवर्तन होता दिख रहा है, दिनोंदिन औसत तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे में भी जलवायु परिवर्तन से जुड़े मसले देश में चुनाव के मुद्दे नहीं बन पाते हैं। मसलन, इस बार के चुनाव में भी जलवायु परिवर्तन पर कहीं भी चर्चा नहीं हुई। जब 'रिंकल अच्छे हैं' अभियान के जरिए सप्ताह में एक दिन कपड़ों पर इस्त्री न करके कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों के बारे में खबर आई तो एक परिचित विद्यार्थी की याद आई, जो अपने घर सासाराम से दूर पटना के एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। उस समय वह अपने कपड़े को धोने और सुखाने के बाद अच्छे से समेटकर बिस्तर के नीचे रख देता था। अगले दिन जब कपड़े पहनने के लिए निकलता तो कपड़े इस तरह से मिलते जैसे किसी ने कपड़े पर इस्त्री की हो। तब यह बात शायद किसी के दिमाग में नहीं आई कि उस परिचित का यह काम कैसे पर्यावरण का नुकसान होने से बचा रहा है। सिक्किम में रहने वाला एक अन्य व्यक्ति अपने घर से कम से कम कूड़ा निकालता है। वह अपनी दिनचर्या में इस बात का खयाल रखता है कि कम से कम चीजें ही कूड़े के रूप में बाहर फेंकी जाएं। रसोई घर से निकलने वाले बेकार हो चुके सामान को वह अपने घर में बनाए गए जुगाड़ से खाद में बदल देता है और इस खाद का प्रयोग वह अपने घर में रखे गमले में कर लेता है।

यों तो भारत के उत्तर-पूर्व के इलाकों में हरियाली की कमी नहीं हैं, इसके बावजूद इन इलाकों, जैसे सिक्किम, असम, मेघालय में यह देखा जा सकता है कि लोग अपने-अपने घरों में, चाहे वे घर एक कमरे का क्यों न हों, गमले में कई तरह के पौधे उगाते हैं। यह पर्यावरण के प्रति उनकी चिंता को जाहिर करता है। देश के कई हिस्सों में गर्मी के मौसम में घर की खुली छत पर सोने का प्रचलन अब बहुत कम हो गया है। खुली छत पर सोना भी कार्बन उत्सर्जन को कम करता है।

हकीकत यह है कि वातावरण से जुड़े मुद्दे हम अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं करते हैं, मगर पर्यावरण में आ रहे बदलावों की मार झेलते रहते हैं। दूसरी ओर, हमारे कई तौर-तरीके वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। हमें अब 'बैक टू नेचर' यानी प्रकृति के पास जैसे अभियान को चलाने के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। छोटे-छोटे कदम जो पर्यावरण का नुकसान होने से बचा सकते हैं, उनको अपने जीवन में उतारना होगा। हम लोग पर्यावरण के बारे में सोचते तो बहुत हैं, लेकिन अपनी ओर से कुछ ठोस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वर्ष 2022 में लगभग पांच हजार भारतीयों के बीच किए गए एक सर्वे के अनुसार यह पाया गया कि इक्यासी फीसद लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं, लेकिन इनमें केवल 'चिंता' ही ज्यादा दिखाई देती है। अगर इतने लोग अपने दिनचर्या में पर्यावरण को नुकसान से बचाने वाले कार्यों को शामिल कर लें तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण को बहुत हद तक बचा लेंगे और औसत तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी को रोक पाएंगे।

युद्ध के पक्ष

रूस के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि वाशिंगटन और कीव 'शांति से रहने वाले निवासियों पर जानबूझ कर किए गए मिसाइल हमले के लिए जिम्मेदार हैं... इसमें अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया।' रूस ने कहा कि उसके कब्जे वाले क्रीमिया पर यूक्रेन द्वारा किए गए मिसाइल हमले की जिम्मेदारी अमेरिका की है, जिसमें तीन बच्चों सहित पांच लोगों की मौत हो गई और करीब सवा सौ लोग घायल हो गए। रूस को साथ में यह भी बताना चाहिए था कि यूक्रेन पर लगभग रोज स्कूल, अस्पताल, बाजार, रिहाइशी घरों, आधारभूत संरचनाओं, बिजली उत्पादन केंद्रों आदि पर जो हमले किए गए हैं, वह कौन, क्यों और किस हक से कर रहा है। पिछले माह ही जर्मनी और अमेरिका ने यूक्रेन को यह छूट दे दी है कि वह उनके द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों के साथ आत्मरक्षा के साथ-साथ रूस के भीतर तक आक्रमण कर सकता है। जिस तरह रूस को इस आक्रमण के लिए चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों से मदद मिल रहा है, उसी तरह यूक्रेन को अमेरिका आदि देशों से। अब वक्त आ गया है जब रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त कराया जाए।

– जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

घाटे की खेती

अगर फसल के दाम खुले बाजार में कम हों और सरकारी तौर पर फसल की खरीदी भी न की जाती हो तो फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाना नाकाफी है। सरकार ने आगामी खरीफ फसल के समर्थन मूल्यों बढ़ोतरी तो कर दी, लेकिन कई फसलें ऐसी हैं, जिन्हें खरीदने की व्यवस्था सरकार नहीं करती है। इस कारण फसल तैयार हो तो मंडियों में पहुंचते ही न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी नीचे बिकने लगती है। लागत से कम में बिकने से कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। आखिर घाटे की खेती कब तक चल सकती है? बढ़ता लागत बोझ खेती किसानी को थका देता है। यही कारण है कि आने वाली पीढ़ी खेती से विमुख होती जा रही है। किसान और खेती को जिंदा रखना है तो फसल के लाभकारी दाम मिलने के लिए कानूनी गारंटी जैसे कदम उठाने होंगे। अगर खेती थक गई तो सारे अन्य उपक्रम भी थक जाएंगे।

– हुकुम सिंह पंवार, इंदौर

खतरे की आहट

गर्मी की मार से पूरा विश्व परेशान है। ब्रिटेन में 26 डिग्री सेल्सियस पर ही 'हीट वेब' यानी लू की लहरों का दौर घोषित कर दिया गया। वहीं भारत में भी तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता दिखा। भीषण गर्मी से जहां सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में माल-मवेशियों की भी गर्मी से मौत हुई है। मानव अपना विनाश तो सुनिश्चित कर ही रहा है, पर पशु-पक्षियों के अस्तित्व को भी खतरे में डाल रहा है। खबरों के मुताबिक, गंगा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जून के महीने में अपने रिकार्ड स्तर से भी नीचे चली गई। यह जलवायु परिवर्तन संकेत है। एक ऐसे भविष्य का, जोकि अंधकारमयी प्रतीत होता है। हम सभी को पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को केंद्र में लाना होगा। इसके समाधान के लिए अति शीघ्र प्रयास नहीं किया गया तो हमारी पृथ्वी का बंटाधार होते देर नहीं लगेगा।

– करुणा नयन चतुर्वेदी, दिल्ली विवि

परीक्षा का स्वरूप

मौजूदा परीक्षा प्रणाली विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमताओं का सही आकलन नहीं करती और इसमें सुधार की आवश्यकता है, ताकि विद्यार्थियों की तर्कसंगत सोच और समग्र विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। यह चिंता का विषय है कि एक ही परीक्षा विद्यार्थियों के भविष्य का निर्धारण करे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली को विद्यार्थियों के समग्र विकास पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्नपत्रों में तर्कसंगत और व्यावहारिक प्रश्नों का समावेश जरूरी है, ताकि विद्यार्थियों की समस्या सुलझाने की क्षमता का परीक्षण हो सके। साथ ही निरंतर मूल्यांकन और परियोजना आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा देना चाहिए। इससे न केवल विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव कम होगा, बल्कि उनकी विभिन्न योग्यताओं का भी समुचित आकलन हो सकेगा। आखिरकार, परीक्षाओं का उद्देश्य ज्ञान का मापदंड होना चाहिए, न कि तनाव का स्रोत।

– अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़, उप्र

www.readwhere.com

भारतीय अर्थव्यवस्था

प्रगति के पथ पर

भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रही है। अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को 'पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था' बनाने का आह्वान किया था। हालांकि, अभी यह सपना पूरा होने में समय लगेगा, पर उन्होंने भारत के उद्यमियों तथा अन्य हितधारकों को दिशा और उम्मीद दे दी है। हर लक्ष्य प्राप्त करने का एक मार्ग होता है जिस पर चलना जरूरी होता है। वास्तव में, दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था भारत लगातार वैश्विक निवेशकों और अर्थशास्त्रियों को समान रूप से आकर्षित कर रहा है। भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक प्रमुख पक्ष है। लेकिन यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनेक बाधायें दूर करनी होंगी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक-आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत वर्तमान वित्त वर्ष में 7.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर प्राप्त करेगा। नीतिगत दृष्टिकोण तथा विभिन्न आयामों पर नजर डालने से यह दावा महत्वपूर्ण और आशावादी दृष्टिकोण का परिचायक है। निसंदेह भारत की अर्थव्यवस्था ने विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए मजबूती प्रदर्शित की है जिनमें कोविड-19 वैश्विक महामारी तथा वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव शामिल हैं। अनेक आर्थिक संकेतक एक मिश्रित, लेकिन आशावादी तस्वीर पेश करते हैं। हालिया वर्षों में दुनिया की सबसे तेज प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की प्रशंसा हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने हालिया वर्षों में शानदार वृद्धि प्रदर्शित करते हुए महामारी से पैदा स्थिति से निपटने में सफलता पाई है। 2023-24 की पहली तिमाही में उसकी जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत थी जो मजबूत आर्थिक गतिशीलता प्रदर्शित करती है।

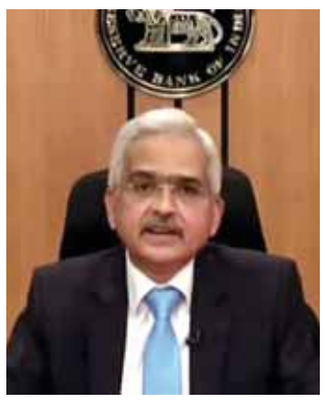

लेकिन मूल्यवृद्धि व मुद्रास्फीति चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-सीपीआई मई, 2024 में 4.6 प्रतिशत पर था जो आरबीआई द्वारा निर्धारित 4 प्रतिशत में 2 प्रतिशत अधिक या कम की सहनशील सीमा में था। इसे प्रगति का सकारात्मक संकेत कहा जा सकता है। अर्थव्यवस्था का एक और चिन्ताजनक क्षेत्र बेरोजगारी है। जून, 2024 में शहरी बेरोजगारी 7.8 प्रतिशत तथा ग्रामीण बेरोजगारी 7.4 प्रतिशत थी जो चिन्ताजनक है। सुधारों के बावजूद महत्वपूर्ण विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन अधिक नहीं हो रहा है। टिकाऊ वृद्धि के लिए रोजगार जरूरी है और यह आर्थिक वृद्धि के लिए 'लाल संकेत' है। इस विभीषिका से निपटने के प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि इससे सभी सकारात्मक संकेतक प्रभवित हो सकते हैं। सकारात्मक रूप से भारत भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई आकर्षित कर रहा है जो 2024 के पहली छमाही में कुल 55.3 बिलियन डालर था। इसके साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था की प्रगति ने बिजनेस सुगमता पर अच्छा असर डाला है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और 2025 में इसके 1 ट्रिलियन डालर पहुंचने की आशा है। इसमें भारत की युवा जनसंख्या का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो हमारा 'जनसंख्या लाभांश' है। भारत की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम है। इससे भारत बड़े व जीवन्त कार्यबल वाला देश है जो उपभोग और खोज को बढ़ावा देता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा इस साल 7.2 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करने का विश्वास भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और संभावनायें प्रकट करता है। लेकिन यह वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए हमें मुद्रास्फीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितताओं तथा जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा समस्याओं का मुकाबला करना होगा। इससे ही टिकाऊ व समावेशी वृद्धि सुनिश्चित होगी।

मोदी सरकार : अवसर व चुनौतियां

सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में व्यवधान न आए और उसकी ब्लैक मार्केटिंग कतई न हो तभी हम महंगाई दर को एक सीमा के अंदर रखने में कामयाब होंगे।

विवेक सिंह
(लेखक, अर्थशास्त्री हैं)

18 वीं लोकसभा का प्रथम सत्र 24 जून से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार बनी तीसरी सरकार की चुनौतियों की भी शुरुआत हुई है। चुनौतियों को ठीक से साधा गया तो ये अवसर भी बन सकती हैं। इस बार विपक्ष मजबूत स्थिति में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष जहां 91 सीटों पर सीमित था वहीं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन 234 सीटों के साथ मजबूत स्थिति में है। एनडीए ने अपना अध्यक्ष बनाने में सफलता प्राप्त की है। ज्यादा संभावना यह है कि डिप्टी स्पीकर पद एनडीए के घटक दलों में से किसी एक को मिल सकता है। मोदी की तीसरी सरकार के लिए आर्थिक विकास, कल्याणकारी योजनाएं और सब्सिडी में लाखों करोड़ रुपए के व्यय को एक साथ साधना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है।

प्रश्न वरीयता का है। समावेशी एवं समग्र विकास के लिए सरकार को गरीबों के प्रति अत्यंत संवेदनशील रहना होगा, साथ ही साथ आर्थिक विकास की गति को भी तेज करने का उत्तरदायित्व होगा। इसकी झलक आगामी जुलाई महीने के पूर्ण बजट में परिलक्षित होगा। आने वाले 23 वर्षों, 2047 तक भारत को एक विकसित देश के रूप में देखने की प्रतिबद्धता सरकार ने जाहिर की है जो सच होती दिख रही है। चुनौतियों के बावजूद देश इसी प्रकार प्रगति पथ पर बढ़ता रहा तो 2047 के पहले ही भारत विकसित देशों की कतार में शामिल हो सकता है। पिछले तीन सालों से लगातार जीडीपी ग्रोथ रेट 7 से 8.5 प्रतिशत के बीच में है जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2 प्रतिशत थी। भारत सरकार का वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट का लक्ष्य है। कुछ वर्षों में भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अनुमानत: वर्ष 2026 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो सकता है। समान नागरिक संहिता का मुद्दा 1950 से ही भाजपा के एजेंडे में शामिल रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी समान नागरिक संहिता भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल थी। कई प्रदेशों सरकारों ने इस पर कार्य आरंभ कर दिया है। यह संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब एनडीए के आंतरिक घटकों में सामंजस्य स्थापित होने के साथ ही साथ विपक्षी दलों में भी इसको लेकर आपसी सहमति बने। समान नागरिक संहिता देश में लागू हो जाती है तो यह सरकार, बीजेपी और एनडीए के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

एक राष्ट्र एक चुनाव अवधारणा के अंतर्गत लोकसभा और सभी विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने का प्रस्ताव है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार चुनावी भाषणों में एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को दोहराते हुए स्पष्ट किया था कि सरकार बनने पर एक राष्ट्र एक चुनाव पर सरकार काम करेगी। संविधान संशोधन के जरिए ही एक राष्ट्र एक चुनाव को सुनिश्चित किया जा सकता है जिसके लिए सभी पार्टियों में आम सहमति का होना आवश्यक है। एक राष्ट्र एक चुनाव के अनेकों फायदे हैं। एक अनुमान के मुताबिक यदि लोकसभा के साथ सभी विधानसभा चुनाव भी हो जाएं तो देश के लगभग 5 लाख करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। इससे चुनावी मशीनरी के समय और पैसे की बर्बादी रुकेगी। आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। देश के विकास के लिए समावेशी, संतुलित, विकासोन्मुख बजट आवश्यक है। 140 करोड़ लोगों के विकास के साथ देश का विकास जुड़ा है। इस समय समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुख बजट देश की अनिवार्यता है। एक तरफ जहां देश की आय में वृद्धि जरूरी है वहीं दूसरी तरफ खर्चों पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। मोदी सरकार 2.0 में निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री के रूप में कार्य बेहतर और सराहनीय था। उम्मीद यही है कि मोदी सरकार 3.0 में भी निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री के रूप में कार्य बेहतरीन होगा। अगले महीने जुलाई में पूर्ण बजट आएगा जो 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। बजट गरीबों के आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरने के साथ ही आर्थिक विकास को गति को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। किसानों की आय में वृद्धि मोदी सरकार के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

निश्चित रूप से पिछले 10 वर्षों में किसानों के आय में वृद्धि हुई है परंतु यह आशा के अनुरूप नहीं है। किसानों को उनकी फसल का वास्तविक मूल्य मिलना चाहिए, इसके लिए बिचौलियों पर नकेल रखना बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय में अनेक प्रयासों के बावजूद जो पैसा किसानों को पहुंचना चाहिए वह बिचौलियों को पहुंच रहा है। बिचौलिए मालामाल हैं और किसान बेहाल हैं। किसान सम्मान निधि सरकार की एक बेहतरीन योजना है जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है और किसानों के जीवन स्तर में अनुकूल सुधार आया है। कृषि कानूनों में आवश्यक सुधार कर जल्द से जल्द लागू करना चाहिए ताकि किसानों की आय में आशा के अनुरूप वृद्धि हो।

महंगाई एवम बेरोजगारी पर लगाम जरूरी है। 2024 के आम चुनाव में महंगाई एक प्रमुख मुद्दा था जिसे विपक्ष द्वारा लगातार उठाया गया। पिछले 10 वर्षों के महंगाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि कुछ वर्षों को छोड़कर ज्यादातर महंगाई दर नियंत्रण में ही रही है। 3 से 5 प्रतिशत तक महंगाई दर किसी भी अर्थव्यवस्था में होना लाभकारी है। मई 2024 मे महंगाई दर 4.75 प्रतिशत थी जो कि पूर्णरूपेण नियंत्रित है।

सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में व्यवधान न आए और उसकी ब्लैक मार्केटिंग कतई न हो तभी हम महंगाई दर को एक सीमा के अंदर रखने में कामयाब होंगे। भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है इसका मुख्य कारण सरकारी नौकरी की चाहत और जरूरी स्किल का न होना है। नई शिक्षा नीति लागू होने के उपरांत हमें बेरोजगारी दर में काफी कमी देखने को मिलेगी। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान निर्यात में आशा के अनुरूप वृद्धि दर्ज हुई है। इस वर्ष कुल निर्यात 778 बिलियन डॉलर है जो की अगले वर्ष 900 बिलियन डालर होने की पूरी संभावना है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है जो बिलकुल संभव दिखता है। पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्यात में लगभग 2300 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सरकार पिछले 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर में 540न की वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 45 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं परिणाम स्वरूप आज इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है। इस सुधार को आगे और ले जाने की आवश्यकता है ताकि देश की इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था विश्वस्तरीय हो सके।

भारत में आज सबसे बड़ी समस्या सांस्कृतिक मूल्य सहित रोजगार उन्मुख शिक्षा व्यवस्था की है। ज्यादातर भारतीय विद्यार्थी डिग्री के बावजूद ज्ञान और कौशलहीन हैं। शिक्षा भारतीय शिक्षा प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए जिसमें भारतीय भाषाओं खासकर हिंदी और संस्कृत पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग हो या मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी हो या विज्ञान इनका पाठ्यक्रम और मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी के बजाय हिंदी होने से विद्यार्थी व्यापकता में सीखेंगे। भारतीय परंपरा मैं धर्मांतरण जैसी विषय वस्तु है ही नहीं। भारतीय संस्कृति कन्वर्जन नहीं अपितु कन्वर्सेशन और करेक्शन पर आधारित है। देश में लगातार धर्मांतरण की खबरें आती रहती हैं जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में उचित नहीं है। केंद्र सरकार को सख्त धर्मांतरण विरोधी कनून लाना चाहिए ताकि देश और देशवासियों को सांस्कृतिक सुरक्षा मिल सके। मोदी सरकार को अपनी विदेश नीति मजबूत करने पर और अधिक ध्यान देना होगा विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक रिश्ता है।

दूसरे देशों के साथ देश के रिश्ते अच्छे होंगे या खराब यह विदेश नीति पर निर्भर करती है। पिछले 10 वर्षों में भारत की विदेश नीति सार्थक रही है। भारत के सामरिक एवं व्यापारिक रिश्ते दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ अच्छे हैं। परिणाम स्वरूप विदेशी व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने का एक प्रमुख कारण सफल विदेश नीति को जाता है।

ईश्वर शरणागति से लाभ

ईश्वर की शरण में जाने से हम आसानी से जटिलताओं से निपट सकते हैं।

अजीत कुमार विश्नोई
(लेखक, आध्यात्मिक शिक्षक हैं)

हम सब आनन्ददायक जीवन चाहते हैं, पर उसका तरीका नहीं जानते हैं। हम अनेक प्रयास करते हैं, पर कुछ न कुछ गलत हो जाता है। यह सपना असंभव लगता है, पर ऐसा नहीं है। परम दयालु ईश्वर ने इसका रास्ता बताया है। भगवान कृष्ण ने कहा था, 'मेरी माया ईश्वरीय है जिससे पार पाना बहुत कठिन है। केवल मेरी शरण में आने वाले ही इस माया से मुक्ति पा सकते हैं।' हम बार-बार स्वाभाविक रूप से हानिकारक विषयों के संपर्क में आते हैं। लाभदायक संवेदनायें उचित हैं, पर इनका पता लगाना कठिन है। ईश्वर हमें यह बुद्धि प्रदान करता है। जैसे माता अपने छोटे बच्चे को स्वयं को नुकसान पहुंचाने से रोकती है, उसी तरह ईश्वर अपने शरणागत की रक्षा करता है। ईश्वर हम सबके लिए माता के समान है। भगवान कृष्ण ने कहा, 'अनेक जन्मों के प्रयास के बाद अंतत: योगी विवेकवान बन कर मेरी शरण में आता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव को सब कुछ मानने वाली महान आत्मा विरल होती है।'

हम इस यात्रा की शुरुआत अभी कर सकते हैं जिसमें ईश्वर हमारी रक्षा करता है। हमें भगवान कृष्ण की यह सलाह मानने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए, 'योग में दृढ़ रहने वाले लोग मुझे गौरवान्वित करते हैं। वे दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ मेरी भक्ति करते हैं तथा उनको मुक्ति मिलती है।'

ईश्वर ने वादा किया है कि 'जो लोग एकात्म भाव से मेरी उपासना करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, ऐसे योग अनुरागियों की मैं सहायता करता हूं। उसे प्राप्त चीजों की सुरक्षा करता हूं तथा उसे अप्राप्त चीजें देता हूं।' हमें भगवान के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, 'अपना मन केवल मुझ पर केन्द्रित करो, अपनी बुद्धि मुझ में एकाग्र करो और इस प्रकार निसंदेह केवल मुझमें ही स्थित रहो।' इस प्रकार हमें ईश्वर में ही एकाग्र रहना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? ईश्वर हमारी माता की तरह हमारा ध्यान रखता है। वह हमारे जीवन का लघु-प्रबंधन करता है। इससे कोई भी व्यक्ति इतना लाभान्वित होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस प्रकार ईश्वर हमारे जैसे असहाय लोगों की माता की तरह सहायता करता है। हालांकि, कभी-कभी हमारी अंतश्चेतना बदल सकती है जिसका संकेत भगवान कृष्ण ने दिया है। उन्होंने कहा है, 'सचेतन रूप से अपनी सभी गतिविधियां मुझ में अर्पित करो, बुद्धि-योग का व्यवहार करो। मेरी शरण में आने पर तुम सचेतन रूप से हमेशा मुझ में ही वास करोगे।' इस प्रकार हमेशा भौतिक वस्तुओं में रत हमारी चेतना ईश्वर के प्रति चेतना में बदल जाती है और इस मार्ग पर चल कर वह आध्यात्मिक हो जाती है। ऐसा होने पर हमारे जीवन में व्यापक परिवर्तन आता है, जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है, 'मेरी चेतना में समाहित होकर तुम मेरी कृपा या आर्शीवाद प्राप्त करने की सभी बाधाओं से मुक्त हो जाओगे।' इसी श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि 'यदि तुम स्वयं कर्ता के भाव से मुक्त हो जाओ तो संपूर्ण मुक्ति प्राप्त कर लोगे।' आमतौर से ऐसा सभी मनुष्यों के साथ होता है। हमें अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए क्योंकि ईश्वर और इच्छायें एकसाथ नहीं रह सकते हैं।

क्या आप अपनी उस विशिष्ठ स्थिति की कल्पना कर सकते हैं, जब ईश्वर के दिशानिर्देशों पर चल कर हम सब कुछ प्राप्त कर लें? इसके बाद जीवन सहज हो जाएगा। हमें पूरे मन से ईश्वर के निर्देशानुसार उसकी शरण में जाना चाहिए। सभी प्रकार से हमें केवल ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। ईश्वर की शरण में जाने से इनकार करने पर अपनी अनन्त यात्रा में हमें कभी शांति या मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। इसे सोचते हुए हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। हम ऐसा कब करेंगे? हम ईश्वर के निर्देशों का पालन कब करेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा है, 'मेरी चेतना प्राप्त करे, मेरे भक्त बनो, मुझे अपने बलिदान अर्पित करो और मेरी शरणागति प्राप्त करे। ऐसा करके ही तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। मैं तुमसे इसका सच्चा वादा करता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं।'

भगवान कृष्ण के वचन सबके लिए अत्यन्त लाभकारी हैं। भगवान ने वादा किया है, 'केवल मेरी शरण में आओ, चिन्ता न करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा।' सवाल है कि हम बार-बार मुसीबतों में क्यों फंसते हैं? हम हमेशा चिन्तित क्यों रहते हैं? इसका कारण हमारे बुरे कर्मों के फल हैं। ईश्वर की शरणागति से ईश्वर हमें क्षमा कर देगा तथा हमें और मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

यह उस मुक्ति के समान है जब हम अपने भौतिक- सांसारिक शरीरों से मुक्ति पाते हैं। यह अविश्वसनीय लगता है, लेनि इस पर विचार करना चाहिए। हमें सुविधाजनक रूप से यथासंभव अधिकाधिक समय तक ईश्वर की शरण में रहना चाहिए।

आप की बात

स्वागत योग्य निर्णय

मध्य प्रदेश में अब मंत्रियों को अपना आयकर खुद भरना पड़ेगा। प्रदेश सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है। हमारे देश के सभी राज्यों में इसे लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सरकारी खजाने पर बोझ बनने वाली मंत्रियों की अन्य सुविधाओं पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए। मंत्रियों के भारी-भरकम टेलीफोन व बिजली बिलों का भुगतान बंद किया जाना चाहिए। मंत्रियों को रहने के लिए बंगले, सरकारी वाहन तथा सिक्योरिटी के साथ-साथ लाखों रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। इसके साथ ही उनको आजीवन भारी भरकम पेंशन मिलती है। इन सब में कटौती की जाए तो पहले से ही करोड़पति हमारे मंत्री-विधायकों को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मगर इससे प्रदेश का बहुत सारा धन अन्य अच्छे कार्यों में लग सकेगा। अब मंत्री व विधायकों के वेतन भत्ते स्वयं बढ़ाने के नियम को भी खत्म करके देशभर के लिए एक जैसी राशि निर्धारित की जानी चाहिए। अभी हालत यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की पगार प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। विधायकों व मंत्रियों के वेतन और भत्तों की तुलना सरकारी अधिकारियों से की जानी चाहिए और इनके बीच एक संतुलन बनाया जाना चाहिए। यह विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

-सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

कर्नाटक में नाटक

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में नया नाटक उभर रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से अनेक मंत्री मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में तीन और उप-मुख्यमंत्री बनाये जाएं। फ्लिहाल एक उप-मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार हैं। शायद स्वयं सिद्धारमैया शिवकुमार का प्रभाव घटाने के लिए ऐसा करना चाहते हैं। कतिपय मंत्री वीरशैव, लिंगायत, एससी, एसटी व अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को उप-मुख्यमंत्री बनाने की वकालत कर रहे हैं। कर्नाटक में विभिन्न समुदायों के उप-मुख्यमंत्री बनाने की यह मांग कांग्रेस की छवि के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। जनता स्वाभाविक रूप से सोच रही है कि अच्छा हुआ केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व की महागठबन्धन सरकार नहीं बनी वरना वहां तो प्रधानमंत्री के बाद उप-प्रधानमंत्री बनाये जाने की मांग काबू से बाहर हो जाती। वैसे भी कांग्रेस की खैरात बांटने की योजनाओं के कारण राज्य सरकार का खजाना खाली हो रहा है और वह लोकसभा चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। गरीबों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले बड़े कांग्रेसी नेता राज्य की जनता पर पड़ने वाले इस आर्थिक बोझ पर चुप्पी बनाए हुए हैं।

- शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

मोदी की शैली

18वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की भूमिका में हैं। उनके तेवर व शैली में कोई अंतर नहीं आया है। मोदी ने अपना मनचाहा स्पीकर बनाकर दिखा दिया है। इसी मनचाहे स्पीकर ओम बिड़ला ने इंदिरा सरकार द्वारा थोपी इमरजेंसी को जब लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया तो सारे कांग्रेसी हाय-हाय करने लगे। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने ओम बिड़ला ने इमरजेंसी के खिलाफ अपना पूरा बयान पढ़ा तथा पूरे सदन ने दो मिनट का मौन भी धारण किया। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पर पहले तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर दबाव डालने का प्रयास किया, पर बात न बनने पर अपना उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए खड़ा कर दिया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस द्वारा कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन न करने से कांग्रेस को मत-विभाजन की मांग करने की भी हिम्मत नहीं हुई। इस प्रकार लगातारी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी ने अपनी आक्रामक शैली से स्पष्ट कर दिया है कि विपक्ष किसी मुगालते में न रहे। हालांकि, नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सभी दलों में सहमति बनाने का प्रयास करेंगे, पर वे विपक्ष अथवा कांग्रेस के किसी प्रकार से दबाव में आने वाले नहीं हैं। यह भारतीय राजनीति के लिए शुभ संकेत है।

.- मनमोहन राजावत, शाजापुर

असांजे की रिहाई

विकीलीक्स के संस्थापक संपादक जूलियन असांजे की रिहाई के साथ राजकाज में पारदर्शिता की मांग से जुड़ी एक लंबी लड़ाई का पटाक्षेप हो गया। अमेरिका सहित कई देशों के बहुत सारे सरकारी रहस्यों के पर्दाफाश में अहम भूमिका निभाने वाले इस ऑस्ट्रेलियाई हैकर को बारह साल दुनिया से अलग-थलग रहकर बिताने पड़े। असांजे की विकीलीक्स ने दुनिया के कई देशों के राजनेताओं के कच्चे चिट्ठे खोले हैं। जनतंत्र और जनता के लिए काम करने वाले और बड़े राष्ट्रों की निरंकुशता को उजागर करने वाले जूलियन असांजे को 12 वर्ष की सजा भुगतनी पड़ी। दशकों से विश्व के सभी बड़े छोटे राष्ट्रों में शासकों के कच्चे चिट्ठे खोलने वालों को उनके कोप का भाजक होना पड़ा है। कई खोजी पत्रकारों को जेल के भीतर लंबे समय तक रखा गया और कई की हत्या भी करवा दी गई। असांजे को अमेरिका में मृत्यु दंड का खतरा था। लेकिन दुनिया भर की लोकतांत्रिक शक्तियों तथा आम जनता की हमदर्दी के कारण आज वे जीवित हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि अपनी रिहाई के बाद वे फिर सक्रिय होंगे तथा अनेक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे।

- विभूति बुपक्या, खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/epaperpdf

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 114

बजट से जुड़े संकेत

लोक सभा के नए सत्र के पहले संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया भर नहीं होता है क्योंकि इसमें आमतौर पर अगले पांच वर्ष के लिए सरकार की नीतियों और योजनाओं को रेखांकित किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोक सभा की शुरुआत के बाद संसद के पहले संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए जो कुछ कहा वह कई लिहाज से महत्त्वपूर्ण था। यह संबोधन तब आया जब नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ लेकिन यह वह कार्यकाल है जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साझेदारों की भूमिका बहुत अहम है क्योंकि पिछले दो अवसरों की तरह इस बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल हो सका। व्यापक सामाजिक-राजनीतिक बहस के मुताबिक देखें तो यह ऐसे समय हुआ है जब रोजगार, खासकर युवा बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है और घरेलू तथा विदेशी कारोबारियों का निवेश कमजोर पड़ा है। ऐसे में इस भाषण से उम्मीद की जा रही थी कि इसमें नीतिगत दिशा को लेकर अहम बातें कही जाएंगी। इस भाषण में सरकार की पिछली उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बात की गई। इसने मोटे तौर पर इस बात पर जोर दिया कि कैसे भारत 10 वर्ष पहले की दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से उठकर अब पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और इस समय हमारा देश दुनिया की सबसे तेज विकसित होती अर्थव्यवस्था वाला देश है। इन परिस्थितियों का श्रेय 'रिफॉर्म, परफॉर्म ऐंड ट्रांसफॉर्म' को दिया गया। आर्थिक वृद्धि के मोर्चे पर कोविड के बाद 2021 से 2024 के बीच वृद्धि का दायरा सालाना 8 फीसदी रहने की बात को रेखांकित किया गया।

कुल मिलाकर अभिभाषण में राजनीतिक दृष्टि से सभी जरूरी विषयों को छुआ गया। सरकार के गरीबी निवारण पर ध्यान केंद्रित करने, पर्यावरण के अनुकूल अर्थव्यवस्था, किसानों और महिलाओं के सशक्तीकरण आदि विषयों को रेखांकित किया गया। उन विषयों का भी उल्लेख किया गया जिनका अतीत में काफी विरोध हुआ है। उदाहरण के लिए भाषण में इस बात का उल्लेख किया गया कि सरकार ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता प्रदान करना शुरू किया, कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ने पिछले चुनाव में एक बार फिर खरा उतर कर दिखाया और कैसे अनुच्छेद 370 को समाप्त करने से जम्मू-कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे में परिवर्तन आया। यह दिलचस्प बात है कि भाषण में परीक्षा संबंधी संस्थाओं में व्यापक बदलाव के वादे से भी पीछे नहीं हटा गया। यह हाल ही में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के पेपर लीक से जुड़ी हुई बात है। ध्यान रहे कि यह परीक्षा केंद्र सरकार की एक संस्था के नेतृत्व में कराई जाती है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात के तगड़े संकेत थे कि सरकार आगामी आम बजट के लिए अपनी क्षमताएं बचाकर रख रही है। मुर्मू के अभिभाषण में साफ बताया गया कि कैसे आगामी बजट सरकारी दूरगामी और भविष्यदर्शी नीतियों और दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। मुर्मू ने वादा किया कि 'बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ बजट में कई ऐतिहासिक कदम' भी देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बजट सुधारों की गति को तेज करेगा और ऐसा 'देश के लोगों की तेज विकास की आकांक्षा' के अनुरूप ही होगा। इसमें अहम बात थी दुनिया भर से निवेश जुटाने के लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की। उन्होंने कहा कि ऐसा करना प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की वास्तविक भावना के अनुरूप होगा। लोक सभा के मौजूदा स्वरूप में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जोरदार बहस की उम्मीद है लेकिन विपक्ष के लिए बेहतर होगा कि वह बजट तक प्रतीक्षा करे।

नीतिगत खामियों से बच कर रहे बजट

आम बजट में देश के कारोबारी जगत की इच्छाओं को पूरा करने से अधिक जरूरी है कि नीतिगत खामियों से बचा जाए। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य

खबरों के मुताबिक वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बजट पूर्व बैठक में उद्योग जगत की ओर से यह मांग की गई है कि उन कंपनियों को प्रत्यक्ष कर दरों में राहत प्रदान की जाए जिनकी कर योग्य आय 20 लाख रुपये तक है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल कीमतों में उत्पाद शुल्क कम करने, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत न्यूनतम मजदूरी में इजाफा करने तथा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अथवा पीएम किसान के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाने की बातें भी शामिल हैं। एक औद्योगिक संगठन ने तो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को तीन दरों वाली प्रणाली में बदलने तथा पूंजीगत लाभ कर के जटिल ढांचे को सरल करने की भी मांग की।

अब सवाल उठता है कि सरकार की इन अनुशंसाओं को स्वीकार करने और जुलाई में पेश होने वाले बजट में इनकी घोषणा करने की क्या संभावना है? इन अनुशंसाओं से परे उन अहम मुद्दों का आकलन करना भी जरूरी है जो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में नजर आ सकते हैं।

विभिन्न जीएसटी दरों को तीन दरों में समाहित करने की मांग उपयुक्त है। ऐसा करके राजस्व निरपेक्ष दर को बढ़ाया जा सकता है और कर संग्रह में सुधार किया जा सकता है। परंतु आम बजट में ऐसी घोषणाओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधित्व वाली एक समिति इस मसले का परीक्षण कर रही है और इस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर जीएसटी परिषद इस पर निर्णय ले सकती है। क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में जीएसटी दरें कम करने के सवाल पर केंद्र का रुख स्पष्ट करेंगी? लगता तो नहीं।

वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एक समान सरल पूंजीगत लाभ कर ढांचे की मांग भी उचित ही है। यह अनुशंसा विशेष रुचि का विषय होगी जिसमें उद्योग संगठन की मांग है कि वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगाने के लिए धारण अवधि को 12 महीने के समान स्तर पर लाया जाना चाहिए तथा दरों को 10 फीसदी करना चाहिए। इसी प्रकार अल्पावधि के पूंजीगत लाभ कर की दर की बात करें तो वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए इसे 15 फीसदी होना चाहिए। पूंजीगत लाभ के ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाने का सुझाव उचित है। इसमें सुधार का मूल विचार कुछ वर्ष पुराना है। अब सरकार को इस पर अंतिम निर्णय लेना चाहिए।

परंतु क्या सरकार नए ढांचे को बजट के माध्यम से पेश करेगी? बीते कई वर्षों के दौरान आम बजट के भाषणों में ऐसी घोषणाएं नहीं की गई हैं जो शेयर बाजार पर असर डाल सकती हों। सरकार नहीं चाहेगी कि शेयर बाजार के किसी भी हिस्से को नकारात्मक ढंग से प्रभावित कर सकने वाली किसी भी अलोकप्रिय खबर को बजट के सकारात्मक प्रभावों या उसके कर राहत संबंधी प्रस्तावों के प्रभावों को नष्ट करने दिया जाए। ऐसे में बजट में शायद उन्हीं बातों को शामिल किया जाए जो शेयर बाजार पर सकारात्मक असर डालें। पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था के पुनर्गठन जैसी बातें, जो कुछ लोगों को खुश तो कुछ अन्य को नाखुश कर सकती हैं, उनसे शायद बचा जाए। वर्ष2024-25 के बजट में अलग-अलग तरह की संपत्तियों पर पूंजीगत लाभ कर की जरूरतों को सरल किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक कार्य इस वर्ष बाद में करने के लिए एक अधिकारप्राप्त समिति पर छोड़े जा सकते हैं।

मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने और पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि बढ़ाने की बात मोदी सरकार के लिए मौजूदा राजनीतिक माहौल में अनुकूल साबित हो सकती है।

चुनाव के बाद हुए हालिया सर्वेक्षण बताते हैं कि ग्रामीण भारत में सत्ताधारी दल को लेकर रुचि कम हुई है। ऐसे में 2024-25 का बजट मनरेगा और पीएम किसान की राशि के प्रति झुकाव वाला हो सकता है। मनरेगा के मेहनताने में हाल के वर्षों में बढ़ी महंगाई नजर आनी चाहिए। इसी तरह पीएम किसान योजना के तहत 2019 में 6,000 रुपये की जो वार्षिक राशि तय की गई थी उसमें भी मुद्रास्फीति के हिसाब से उचित इजाफा किया जाना चाहिए। यह सरकार की राजकोषीय मजबूती की कोशिश के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए क्योंकि बेहतर कर राजस्व और रिजर्व बैंक से हासिल होने वाले अधिशेष से इसकी आसानी से भरपाई हो जानी चाहिए।

बड़ी बहस इस बात पर होगी कि मध्य वर्ग को आय कर में राहत देने की बात केंद्र सरकार स्वीकार करेगी या नहीं। वर्ष 2021-22 में लगभग 6.8 करोड़ भारतीयों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया। इनमें से 5.8 करोड़ लोगों की सकल वार्षिक आय 2.5 लाख से 20 लाख रुपये के बीच थी। तब से अब तक इस आय वर्ग के लोगों की संख्या में इजाफा हुआ होगा। अगर करदाताओं की इस श्रेणी को कर राहत दी जाती है तो इससे बड़ी तादाद में लोग लाभान्वित होंगे। परंतु अगर बजट में ऐसी राहत की घोषणा की गई तो इससे राजस्व में भी कमी आएगी। उद्योग जगत की दलील है कि कर राहत और मनरेगा तथा पीएम किसान के तहत बढ़ी हुई राशि से खपत मांग बढ़ेगी।

मोदी सरकार ने अब तक मांग बढ़ाने के लिए ऐसी कर राहत पर कम ही यकीन किया है। उसने अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए निवेश बढ़ाने को प्राथमिकता दी। चुनाव के पहले कर राहत देने से कुछ राजनीतिक लाभ मिल भी सकता था। परंतु अब चुनाव हो चुके हैं और मोदी सरकार को प्रत्यक्ष कर पुनर्गठन के वादे को पूरा करना ही होगा। कुछ वर्ष पहले शुरू हुए इन सुधारों को पूरा करना समझदारी भरा होगा। मध्य वर्ग के लिए कर दरों में कटौती के आधार पर बजट का आकलन करना सही नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में अनिश्चितता को देखते हुए पेट्रोल और डीजल पर कर को कम करना जोखिम भर हो सकता है।

बजट का ऐसी मांगों के पूरा होने के आधार पर आकलन करने के बजाय उसका आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि यह कम से कम चार नीतिगत कमियों से बच पाता है या नहीं। पहली, इसे राजकोषीय मजबूती की उस राह से परे नहीं हटना चाहिए जो कोविड के बाद के वर्षों में बजट में रेखांकित की गई। हां, अगर इसके लिए लक्ष्य को एक वर्ष आगे बढ़ाया जाए तो बेहतर होगा। दूसरा, बजट को कुछ वर्ष पहले शुरू की गई आयात शुल्क बढ़ाने की प्रक्रिया को पलट देना चाहिए। अगर देश की निर्यात वृद्धि को तेज करना है तो आयात शुल्क कम करने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू करनी चाहिए। तीसरा, सरकार को अधोसंरचना तैयार करने में निवेश कम करना चाहिए। बीते कुछ वर्षों में सरकार के पूंजीगत व्यय ने अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की है। अभी तक निजी निवेश में सुधार के कोई संकेत नहीं नजर आए हैं। आखिर में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना के तहत क्षेत्रों की तादाद बढ़ाने की चाह पर अंकुश लगना चाहिए। पीएलआई योजना की कई लागत ऐसी हैं जो केंद्र के साथ विनिर्माण क्षेत्र को भी चुकानी पड़ रही हैं। ऐसे में प्रतिस्पर्धा सुधार की चिंता किए बिना सब्सिडी पर उसकी निर्भरता बढ़ रही है।

2024-25 के बजट में शायद उद्योग जगत की कर राहत, पेट्रोल-डीजल में शुल्क कटौती, पूंजीगत लाभ कर पुनर्गठन और मनरेगा तथा पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाने जैसी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकें। परंतु यह दलील उचित है कि अगर चार नीतिगत कमियों से बचा जाए तो देश के उद्योग जगत को ही लाभ होगा।

शहरों में बढ़ती गर्मी और इसका समाधान

भारत भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। विशेषकर, मई ने कहर बरपाया और तापमान इतना बढ़ गया कि पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड टूट गए और पिछले रिकॉर्ड की तुलना में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। अल नीनो प्रभाव से बेकाबू हो रहे जलवायु संकट के कारण पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है और भीषण गर्मी से मानव से लेकर जीव-जंतु तक परेशान हैं। तापमान लगातार बढ़ने से भारत समेत पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है जिससे जलवायु अनुरूप एवं वैकल्पिक समाधानों की तत्काल जरूरत महसूस की जा रही है ताकि मानव, जीव-जंतु सहित पर्यावरण को और नुकसान से बचाया जा सके।

विश्व में शहरी आबादी बढ़ने के साथ अधिक लोगों को मौसम में आए प्रतिकूल बदलावों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम का सख्त मिजाज कमजोर एवं वंचित लोगों को अधिक प्रभावित कर रहा है। सी40 (शहरों का जलवायु नेतृत्व समूह) के एक सर्वेक्षण के अनुसार इस समय दुनिया के 350 से अधिक शहर अत्यधिक गर्मी की जद में आ गए हैं। इस अध्ययन के अनुसार 2050 तक ऐसे शहरों की संख्या बढ़कर 970 तक पहुंच सकती है। सिटी40 वैश्विक स्तर पर 96 शहरों का संगठन है, जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिम एवं शहरी समाधान लागू करने के लिए संकल्पित है। इसी अध्ययन में कहा गया है कि शहरों में रहने वाले 2.6 करोड़ से अधिक गरीब लोग अत्यधिक गर्मी से जूझ रहे हैं। वर्ष 2050 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 21.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ का कहना है कि लगभग 56 करोड़ बच्चे बार-बार लू का सामना कर रहे हैं और आशंका जताई जा रही है कि यह संख्या 2050 तक बढ़कर 2 अरब तक पहुंच सकती है। ऐसी चरम स्थितियां इस बात का संकेत हैं कि वर्तमान समय में अत्यधिक तापमान का सामना करने वाले लोगों को निकट भविष्य में और भीषण गर्मी झेलने के लिए तैयार रहना होगा। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग भी अधिक गर्मी का अनुभव करेंगे जिसके वे आदी नहीं रहे हैं। ऐसी आशंका के बीच योजनाकारों को प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारी दुरुस्त रखनी होगी।

शहरी नियोजन प्रक्रिया में भीषण गर्मी से निपटने के लिए एक समग्र नजरिया अपनाया जाना चाहिए जिसमें बदलती परिस्थितियों में अनुकूल व्यवहार और आधुनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में बेहतर तालमेल बैठाना आसान हो जाए। इस बदलाव के केंद्र में एक टिकाऊ शहरी ढांचा होना चाहिए। शहरों को ऐसे भविष्य की नींव रखनी चाहिए जिसमें सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से इतर प्रत्येक व्यक्ति की उन आवश्यक सेवाओं तक पहुंच हो, जो रोजमर्रा का जीवन आसान बनाने के साथ ही चरम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने में मददगार हों। यह न केवल समाधान है बल्कि रोकथाम एवं मदद का जरिया भी है जिससे उन लोगों के लिए एक सुरक्षा चक्र तैयार हो जाएगा जो भीषण गर्मी के दौरान उपेक्षा का शिकार हो सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक विश्वसनीय एवं सक्षम परिवहन तंत्र निजी वाहनों पर निर्भरता कम करता है और उत्सर्जन एवं नगरीय उष्मा द्वीप प्रभाव भी कम करता है।

अमित कपूर और विवेक देवरॉय

मौजूदा संकट हमें चरम तापमान से निपटने में हरित अवसंरचना पर विचार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हरित अवसंरचना में प्रकृति के अनुकूल उपायों का समागम होता है जिनका मकसद शहरी एवं जलवायु-संबंधी चुनौतियों से निपटना है। इन उपायों में वर्षा जल प्रबंधन, जलवायु अनुकूलन, गर्मी का प्रभाव नियंत्रित करना रखना, जैव-विविधता बढ़ाना और मानव केंद्रित उपायों (जैसे छाया एवं आश्रय) के साथ टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन बढ़ावा शामिल हैं।

हरित अवसंरचना एक पारिस्थितिकी-तंत्र आधारित ढांचा तैयार करता है। यह ढांचा समुदायों के सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण से जुड़े हितों की रक्षा करता है। इसे देखते हुए यह लाजिमी हो गया है कि शहरी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन एवं बढ़ते तापमान पर अंकुश लगाने के उपाय शहरीकरण की प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएं। पर्यावरण अभियांत्रिकी के माध्यम से शहरी नियोजन पेचीदा शहरी चुनौतियों से निपटने की दिशा में टिकाऊ विकल्पों का मार्ग प्रशस्त करता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी समिति ने छठी समीक्षा रिपोर्ट में पारिस्थितिकी-तंत्र आधारित दृष्टिकोण जैसे शहरी नियोजन, शहरी वन एवं आर्द्रभूमि दोबारा बहाल करने और शुरुआती चेतावनी प्रणाली पर जोर दिया है।

वैश्विक स्तर पर हो रहे नवाचार हमें रहने लायक अधिक से अधिक शहर तैयार करने की महत्त्वपूर्ण सीख देते हैं। सिंगापुर हरित छत और ऊर्ध्वाधर उद्यान (वर्टिकल गार्डन) के जरिये गर्मी की समस्या से निपट रहा है। न्यूयॉर्क सिटी में 'कूल रूफ' कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें धूप का असर कम करने के लिए घरों की छतों को सफेद रंग दिया गया है। इसी तरह, मेलबर्न में साल 2012 में 20 वर्षों की एक रणनीति अपनाई गई जिसमें शहरी वन क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया गया और 2040 तक कैनोपी कवर (बढ़ते पौधों से छायांकित क्षेत्र) बढ़ाकर 60 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है।

शहरी क्षेत्रों में तापमान कम करने की प्रभावी रणनीति में हरित अवसंरचना तैयार करना शामिल है। पार्क, उद्यान और हरित छतों की संख्या बढ़ाकर शहरों में तापमान काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी तरह, शहरों में सड़कों एवं गलियों के किनारों और सार्वजनिक स्थानों पर हरियाली बढ़ाकर न केवल तापमान कम किया जा सकेगा बल्कि इससे वायु की गुणवत्ता भी सुधरेगी। इससे शहर अधिक सुंदर भी दिखेंगे।

एक दूसरा जरूरी माध्यम छतों एवं सतह को गर्म होने से बचाना है। ठंडी छतें सामान्य छतों की तुलना में सूर्य की रोशनी पीछे धकेल देती है और कम गर्मी अवशोषित करती हैं। इन छतों में विशेष सामग्री या परत का इस्तेमाल होता है जो तापमान रोधी होते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल कर पार्किंग, फुटपाथ एवं गलियों में भी सतह ठंडी रखी जा सकती है।

अत्यधिक गर्मी की समस्या दूर करने में प्रभावी जल प्रबंधन भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शहरी जल इकाइयां वाष्पशील शीतलन (इवैपरेटिव कूलिंग) के जरिये आस-पास की जगहों को ठंडा रख सकती हैं। इसके अलावा, तूफानी बारिश से आए जल का प्रबंधन एवं इसका बहाव रोकने के लिए वर्षा उद्यान एवं बायोस्वाल जैसे ढांचे भी शहरों में जल एवं पेड़-पौधों के साथ तापमान कम रखने में मदद करते हैं।

अगर शहरों का आकार थोड़ा छोटा रखा जाए तो यह नगरीय ऊष्मा प्रभाव कम करने में मदद कर सकता है। इसका एक फायदा यह होगा कि लंबे-चौड़े परिवहन तंत्र की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। घरों एवं इमारतों को अधिक हवादार बनाया जाए तो वातुकूलित मशीनों (एसी) का इस्तेमाल कम होगा जिससे उष्मा उत्सर्जन भी घटेगा।

इन विविध रणनीतियों की मदद से शहरी क्षेत्र भीषण गर्मी एवं लू के असर को कम कर सकते हैं और शहरी जीवन को अधिक सुगम बना सकते हैं। इन रणनीतियों का एक और फायदा यह होगा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी तैयारी मजबूत होगी और भविष्य के लिए अधिक सुदृढ़ शहरी तंत्र तैयार हो पाएगा।

(कपूर इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटटिवनेस इंडिया के अध्यक्ष और देवरॉय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। लेख में जेसिका दुग्गल का भी योगदान)

आपका पक्ष

अर्थव्यवस्था सर्वोपरि

लेख 'भारत में फिर राजनीतिक अर्थव्यवस्था हावी' सही निष्कर्षों के साथ बहुत चित्ताकर्षक एवं हृदयग्राही चर्चा करता है। यह समझना आवश्यक है कि 18वीं लोक सभा जनादेश से गठित हुई है और इसके गठबंधन सरकार के स्वरूप पर कोई प्रश्न, शंका और संभ्रम निरर्थक हैं। मोदी सरकार पहले कार्यकाल से ही गठबंधन सरकार है। भाजपा नीत पिछली दो गठबंधन सरकारों की सफलता का ही परिणाम है कि भाजपा गठबंधन के विरुद्ध कोई विरोधी लहर नहीं थी। राजनीतिक पटल पर तीसरी बार मोदी सरकार के गठबंधन स्वरूप को लेकर आलोचना जनमानस के लिए तब तक कोई अर्थ नहीं रखती जब तक कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने के साथ जनमानस की आकांक्षाओं को पूरा करने और उसके जनकल्याण पर ध्यान देती रहे। जनकल्याणकारी योजनाओं को वोट-बैंक के लिए नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन और स्थायित्व का कारक स्वीकार करने की आवश्यकता है। यह सही है कि राशन व्यवस्था अति निर्धन वर्ग तक सीमित हो और शिक्षा और कौशल पर अधिकाधिक खर्च हो। 'हिंदुत्व और सनातन से दो वक्त की रोटी नहीं मिलती' की धारणा रखने वाले वर्ग को यह समझने की आवश्यकता है कि सनातन की मंदिरों की अर्थव्यवस्था 3.02 लाख करोड़ रुपये की हो चुकी है और धार्मिक पर्यटन भी 1.34 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। मंदिरों, धार्मिक पर्यटन, होटल, भोजनालय, छोटे-बड़े उद्योग व्यापार में देश में करोड़ों लोग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े हैं और अयोध्या, वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मदुरै, तिरुपति बालाजी, शिरडी, मथुरा, उज्जैन, नासिक, कोणार्क, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, जम्मू, कटरा, द्वारकाधीश, सोमनाथ और पूरे उत्तराखंड में सनातन और धार्मिक पर्यटन से ही अर्थव्यवस्था चल रही है। हजारों अनाथालय, वृद्धाश्रम, गोशालाएं, विद्यालय, भोजनालय, धर्मशालाएं सनातन व्यवस्था में ही चल रहे हैं। यह सत्य है कि रोजगार सृजन निजी क्षेत्र में ही है तो आरक्षण को लेकर इतनी राजनीति क्यों? यह प्रश्न राजनीतिक पटल के सामने मुंह फाड़े खड़े है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

मंदिर, धार्मिक पर्यटन, होटल, भोजनालय, छोटे-बड़े उद्योग व्यापार में देश के करोड़ों लोग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े हैं

भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही बुनियादी ढांचे पर भी भरपूर जोर दिया जा रहा है। पिछले दिनों संसद में 18वीं लोक सभा का पहला सत्र शुरू हुआ है। इस बार संसद में केवल दो ही दल नजर आ रहे हैं। पहला राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) और दूसरा इंडिया (भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन)। भले ही राजग और इंडिया कई दलों के गठबंधन से बना है लेकिन संसद में एक ही दल के रूप में नजर आते हैं। विकसित देश अमेरिका में दो ही दल हैं पहला डेमोक्रेटिक तथा दूसरा रिपब्लिक। भारत में एक देश एक चुनाव की परिकल्पना की गई है। शायद एक दिन देश में दो बड़े दल हों और एक देश एक चुनाव भी देखने को मिल जाए।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

भारत और इजिप्ट के राफेल लड़ाकू विमानों ने गुरुवार को मिस्र के प्रसिद्ध पिरामिड के ऊपर तालमेल के साथ उड़ान भरी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

विदेश से आती कमाई

विभिन्न देशों में कार्यरत भारतीयों ने 2023 में 120 अरब डॉलर की कमाई देश में भेजी थी. विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, विप्रेषण (रेमिटेंस) के मामले में भारत अग्रणी देश बना हुआ है. उसके बाद मेक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान हैं, जिन्हें क्रमशः 66, 50, 39 और 27 अरब डॉलर मिले हैं. उल्लेखनीय है कि कुशल भारतीय कामगारों का सबसे बड़ा गंतव्य अमेरिका है. अनेक विकसित देशों के अलावा खाड़ी देशों में भी बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी काम कर रहे हैं. दुनिया में सबसे अधिक प्रवासी भारतीय हैं तथा वे विभिन्न देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसका एक संकेत हमें 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ती विप्रेषण राशि से मिलता है. अमेरिका के बाद सबसे अधिक कमाई संयुक्त अरब अमीरात से आयी है, जो कुल विप्रेषण का 18 प्रतिशत है. इसके बाद सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और कतर का स्थान है. विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत में आने वाले विप्रेषण में 2024 में 3.7 प्रतिशत और 2025 में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच अपनी मुद्राओं में लेन-देन की व्यवस्था होने से औपचारिक माध्यमों से अब अधिक विप्रेषण भेजा जा रहा है. अमीरात और सिंगापुर में यूपीआइ भुगतान प्रणाली के चालू होने से कमाई भेजने का खर्च भी कम होगा और समय भी कम लगेगा. विप्रेषण के मामले में एक आशंका यह लगी रहती है कि बाहरी घटनाओं से इसमें कमी आ सकती है. भारत के अधिकतर कुशल कामगार अमेरिका और अन्य विकसित देशों में कार्यरत हैं तथा कम कुशल प्रवासी खाड़ी देशों में हैं. इस वितरण से बाहरी घटनाओं का असर कम होगा, इसलिए वैसी स्थिति में भी विप्रेषण में स्थिरता बनी रहेगी. प्रवासन और विप्रेषण आर्थिक और मानवीय विकास के महत्वपूर्ण कारक हैं. प्रवासी कामगार एक ओर अपनी प्रतिभा एवं अपने परिश्रम से दूसरे देशों के विकास को गति देते हैं, वहीं दूसरी ओर वे अपने देश के विदेशी मुद्रा भंडार को समृद्ध बनाते हैं तथा अपने परिवार की उन्नति का आधार बनते हैं. वैश्विक स्तर पर जहां कई देशों में श्रम की उपलब्धता का अभाव है, वहीं कई देशों में बेरोजगारी है और कौशल की कमी है. ऐसे बहुत से देश प्रबंधित प्रवासन को बढ़ावा दे रहे हैं. इसका लाभ भारत जैसे देशों को मिल रहा है. विप्रेषण बढ़ना निश्चित ही उत्साहजनक है, पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कामगारों को जोखिम, शोषण, भेदभाव आदि का भी सामना करना पड़ता है. हाल में कुवैत में एक इमारत में आग लगने से कई भारतीय कामगारों की मौत हो गयी. इटली में एक भारतीय श्रमिक को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया. इस संबंध में हमारे दूतावास और उच्चायोगों के सक्रिय हस्तक्षेप की आवश्यकता है.

भारत में आने वाले विप्रेषण में 2024 में 3.7 प्रतिशत और 2025 में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी.

अर्थव्यवस्था पर जल संकट का साया

अभिजीत मुखोपाध्याय
अर्थशास्त्री
abhijitmukhopadhyay@gmail.com

जलवायु परिवर्तन से जो देश सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, उनमें भारत भी है. एक ओर गर्मी के मौसम की अवधि बढ़ती जा रही है तथा औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, वहीं अनियमित बारिश की समस्या गंभीर हो रही है. देश के बड़े हिस्से में पानी की घटती उपलब्धता इस संकट को बढ़ाती जा रही है. यह परेशानी भी जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है. वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज द्वारा जारी पर्यावरण जोखिम की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि भारत में पानी की कमी तथा जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की संख्या में बढ़ोतरी से भारत की साख पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. जल संकट से खेती और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं तथा खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं आमदनी में कमी सामाजिक अस्थिरता का कारण भी बन सकती हैं. उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने भी यह रेखांकित किया है कि खाद्य मुद्रास्फीति चिंता की वजह बनी हुई है और ऐसे में ब्याज दरों में कटौती करना संभव नहीं है. मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया गया था. अधिक दर होने से उद्योगों के लिए कर्ज ले पाना एक चुनौती बन गया है. ऐसा नहीं होता, तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर और अधिक हो सकती थी.

विकास के साथ-साथ ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है. हालांकि स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में उत्साहजनक तेजी आयी है, पर अभी भी हम बिजली के लिए कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों पर निर्भर हैं. इन संयंत्रों में पानी की बड़ी खपत होती है. जाहिर है कि पानी की समस्या ऐसे संयंत्रों को मुश्किल में डाल सकती है. ऐसा ही इस्पात उद्योग के साथ है. अन्य उद्योगों को भी पानी की दरकार होती है. मूडीज ने कहा है कि तेज आर्थिक विकास, औद्योगीकरण और शहरीकरण से पानी की उपलब्धता और घटती जायेगी. हमारे देश में 2021 में पानी की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक उपलब्धता 1,486 घन मीटर थी, जो 2031 में घटकर 1,367 घन मीटर रह जायेगी. यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह औसत उपलब्धता है. कई हिस्सों में यह आंकड़ा बहुत कम है. अभी हमने देखा कि दिल्ली और बेंगलुरु में पीने का पानी मिलना मुहाल हो गया था. यह संकट अभी टला नहीं है. हाल में आयी डीसीएम श्रीराम-सत्व नॉलेज रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 तक देश के 50 प्रतिशत जिलों में पानी की गंभीर कमी हो जायेगी. कुछ समय पहले एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में बताया गया था कि सैकड़ों जिलों में पानी में आर्सेनिक तत्व हैं.

एक ओर बढ़ती गर्मी पानी की कमी की समस्या को गंभीर बना रही है, तो दूसरी ओर देश के अनेक इलाके बाढ़ से ग्रस्त होते हैं. जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बहुत अधिक बारिश से जल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान होता है. अगर बारिश की कुल मात्रा को देखा जाए, तो उसमें कमी आ रही है. साल 2023 में 1971 से 2020 तक के औसत से छह प्रतिशत कम बारिश हुई थी. हमारे देश में साल की 70 प्रतिशत से अधिक बारिश जून से सितंबर की अवधि में होती है. यदि इसमें कमी आती है, तो खेती पर भी असर पड़ता है और तापमान भी अधिक रहता है. हाल के समय में गेहूं, धान आदि कुछ फसलों की पैदावार पर असर पड़ा है. इन कृषि उत्पादों के निर्यात पर रोक लगानी पड़ी है ताकि खाद्य मुद्रास्फीति अनियंत्रित न हो जाए. हमें ऐसी तकनीकों और फसलों को अपनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे पानी की खपत घटायी जा सके. पानी की कमी, दूषित पानी और अधिक तापमान मौतों एवं बीमारियों की वजह बन रहे हैं. इससे कामगारों की क्षमता भी घटती है और आर्थिक नुकसान होता है. हमारे देश में अधिकतर रोजगार ऐसे हैं, जिनमें बाहर काम करना पड़ता है.

जैसा कि मूडीज ने कहा है, देश में औद्योगीकरण और शहरीकरण के विस्तार की बड़ी संभावना है. इस विस्तार के साथ-साथ पानी के लिए उद्योगों एवं लोगों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी. इसका एक मतलब यह भी है कि पानी महंगा होता जायेगा. यदि जल प्रबंधन पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया, तो हमारे देश की बड़ी आबादी के लिए वह त्रासद स्थिति हो सकती है. जब जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, जल संकट, भूमि क्षरण आदि के बारे में कुछ दशक पूर्व अनुमान लगाये जाते थे, ऐसा लगता था कि इन संकटों के आने में अभी समय है. पर ऐसा नहीं हुआ. ये सभी मुश्किलें ठीक हमारे सामने हैं. भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें पानी के प्रबंधन पर ध्यान दे रही हैं. पेयजल उपलब्ध कराने के भी प्रयास हो रहे हैं. दिल्ली में कृत्रिम झीलें बनी हैं, जिनमें रिसाइकल पानी डाला जाता है. ऐसे प्रयासों से भूजल स्तर बढ़ा है. इस तरह के उपाय समूचे देश में होने चाहिए. तालाबों, जलाशयों और झीलों को बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए. शहरीकरण से सबसे अधिक नुकसान जलाशयों का ही हुआ है. इस संबंध में ठोस नियमन नहीं होने से रियल एस्टेट कारोबारी झीलों-तालाबों को पाटकर इमारतें बना देते हैं. इसे रोका जाना चाहिए.

जल प्रबंधन में निवेश बढ़ाना समझदारी की बात होगी क्योंकि ऐसा कभी न कभी करना ही होगा, इसलिए अभी से हमें अपने प्रयासों को तेज करना चाहिए ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके और हम भारी नुकसान से बच सकें. खेती, भवन निर्माण, उद्योग आदि में भूजल का बेतहाशा दोहन हो रहा है. देश के कई जिलों में भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया है. जितना दोहन हो रहा है, उस मात्रा में रिचार्ज नहीं हो रहा है. ऐसे में बारिश के पानी को सहेजना बहुत जरूरी हो जाता है. यदि समुचित वर्षा जल संरक्षण हो तथा गंदे पानी को रिसाइकल किया जाए, तो संकट से बचाव संभव हो सकता है. जो बातें मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कही है, वे कई रिपोर्टों और अध्ययनों में कही जा चुकी हैं. असली मामला सुझावों पर अमल का है. हालांकि जल समस्या के समाधान के लिए सरकारी स्तर पर कोशिशें हो रही हैं, पर वे पर्याप्त नहीं हैं. बारिश के पानी को बचाने के लिए इमारतों में व्यवस्था करने के प्रावधान हैं, पर इस संबंध में निगरानी की कमी है. यह संरक्षण केवल बड़ी इमारतों के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि इसके लिए हर घर में उपाय होने चाहिए. अर्थव्यवस्था तो दूर की बात, पानी नहीं होने से हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश में औद्योगीकरण और शहरीकरण के विस्तार की बड़ी संभावना है. इस विस्तार के साथ-साथ पानी के लिए उद्योगों एवं लोगों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी. इसका एक मतलब यह भी है कि पानी महंगा होता जायेगा. यदि जल प्रबंधन पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया, तो हमारे देश की बड़ी आबादी के लिए वह त्रासद स्थिति हो सकती है.

ज्ञान-विज्ञान और भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि

प्रो सतीश कुमार
राजनीति विज्ञान संकाय, इग्नू, नयी दिल्ली
singhsatis@gmail.com

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले नालंदा विश्वविद्यालय के नये परिसर का उद्घाटन करते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था. शिक्षा को लेकर यही भारत की सोच रही है. जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में इंडियन साइंस कांग्रेस के उद्घाटन में कहा था कि भारत की गरीबी को दूर करने का माध्यम शिक्षा ही है. बहरहाल, बरसों तक भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि पश्चिम आयातित ज्ञान-विज्ञान पर टिकी रही. इसीलिए अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया गया. विदेशी पुस्तकों में विदेशी ज्ञान भारत के ज्ञान-विज्ञान की पहचान बन गयी. सामाजिक विज्ञान भी इसी में समाहित हो गया. राष्ट्र की परिभाषा से लेकर राजनीतिक विचार-विमर्श का आधार भी पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान बना. प्रधानमंत्री मोदी ने दस वर्ष पूर्व कार्यभार संभालने के साथ इस गिरह को खोलने की सोच को बढ़ावा दिया. इस प्रक्रिया में समय लगा और उनके दूसरे कार्यकाल में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया. पठन-पाठन में क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी पर बल दिया गया. मृतप्राय संस्कृत को जीवित किया जाने लगा. यह समझ विकसित होने लगी कि दुनिया के सामने उपस्थित समस्याओं का हल भारतीय दृष्टिकोण में है. भारत की सोच में एक शांतिपूर्ण जगत की विहंगम दृष्टि है.

लेकिन समस्या दुनिया के सामने भारत की ज्ञान व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से स्थापित और संचालित करने की थी. वह कैसे हो, यह सबसे बड़ी चुनौती थी. अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी इस दिशा में ठोस पहल करने जा रहे थे, पर कुछ राजनीतिक समीकरण ने उथल-पुथल मचाया और कुछ शिक्षा जगत में सक्रिय अपराधियों ने भारत की बेहतरीन सोच पर प्रश्न-चिह्न खड़ा कर दिया. अहम सवाल यह है कि भारत की अंतरराष्ट्रीय पहचान का मजबूत आधार कैसे तैयार होगा और उसका सूत्रधार कौन होगा. क्या प्रधानमंत्री की सोच का भारत केवल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तक ही थम जायेगा? ये सारे प्रश्न हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं. अगर भारत के पुरातन इतिहास की चर्चा की जाए, तो हड़प्पा सभ्यता के दौर में भारत के व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से लेकर अफ्रीकी देशों तक थे. हड़प्पा संस्कृति के केंद्र बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और गुजरात में थे. पूरा मध्य एशिया भारत के साथ जुड़ा हुआ था. ईरान में भारतीय संस्कृति के अवशेष मिले हैं. दक्षिण भारत के जरिये समूचा पूर्वी एशिया भारत के संपर्क में था. यह व्यापार केवल वस्तुओं का नहीं होता था, बल्कि विचारों का भी होता था. इसी तरह भारत से नेपाल और पुनः चीन व पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म और हिंदू संस्कृति का विस्तार हुआ. चीन के दो महत्वपूर्ण यात्री फाहियान और ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आये और अध्ययन-अध्यापन किया तथा भारत को गुरु भूमि के रूप में स्वीकार किया.

बीसवीं सदी में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर विचार संस्थानों (थिंक टैंक) की शुरुआत की. इसका उद्देश्य दुनिया को अपने अनुसार समझने और उसी के अनुरूप नीतियों को बनाना था. अमूमन ये संस्थाएं गैर-सरकारी थीं, लेकिन उनको आर्थिक मदद के साथ-साथ संसाधनों को सरकार द्वारा ही मुहैया कराया जाता था. इन संस्थाओं के माध्यम से अमेरिका ने ज्ञान शक्ति का एक ऐसा मजबूत तंत्र बना लिया कि दुनिया में किसी भी समस्या का हल उसी के विशेषज्ञों से पूछा जाने लगा. यहां तक कि जब भारत में संसद पर आतंकी हमला हुआ, तो उसके बारे में समझ बनाने के लिए भी अमेरिकी संस्थाओं से राय ली गयी. इस तरह महाशक्ति की परिभाषा में ज्ञान की शक्ति भी एक आधार बन गया. आर्थिक और सैनिक शक्ति के साथ-साथ ज्ञान की पहचान भी जरूरी है, जिसे अमेरिकी विद्वान जोसफ नाई ने 'सॉफ्ट पावर' की संज्ञा दी. चीन 21वीं सदी में 'सॉफ्ट पावर' पर खूब काम कर रहा है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं- एक, साम्यवादी शासन और दूसरा, मंदारिन भाषा, जो दुनिया में सभी जगह नहीं बोली नहीं जाती. भारत के पास एक स्थापित लोकतंत्र भी है और दुनिया में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं.

लेकिन समस्या का हल इतने भर से नहीं हो सकता. बात भारतीय चिंतन और संस्कृति की है, उसके रूपांतरण की है. यही बार प्रधानमंत्री की सोच के केंद्र में भी है. उच्च शिक्षा में भारत का कुल नामांकन 26 प्रतिशत है, जिसे हम 2035 तक 50 प्रतिशत पर ले जाना चाहते हैं. क्या गुणवत्ता के साथ भारत को विश्व में प्रतिष्ठित करने का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था से संभव होगा. राष्ट्र निर्माण में भूमिका महज राजनीतिक नेतृत्व की नहीं होती. हर सक्षम व्यक्ति को इसमें योगदान देना होता है. अगर नयी सरकार के दौर में कोई उथल-पुथल हुई, तो देश का शिक्षा तंत्र पिछड़ जायेगा और भारत की पहचान अधर में लटक जायेगी. इसलिए नयी शिक्षा नीति के जरिये भारत केंद्रित अंतरराष्ट्रीय पहचान की आवश्यकता है. प्रधानमंत्री मोदी ने जो नालंदा में कहा, उसे कैसे पूरे देश में लागू किया जाए, यह गंभीर चुनौती होगी. उन्होंने कहा है, 'नालंदा केवल एक नाम नहीं है. नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है. नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है.' **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

राष्ट्र निर्माण में भूमिका महज राजनीतिक नेतृत्व की नहीं होती. हर सक्षम व्यक्ति को इसमें योगदान देना होता है. अगर नयी सरकार के दौर में कोई उथल-पुथल हुई, तो देश का शिक्षा तंत्र पिछड़ जायेगा और भारत की पहचान अधर में लटक जायेगी. इसलिए नयी शिक्षा नीति के जरिये भारत केंद्रित अंतरराष्ट्रीय पहचान की आवश्यकता है.

देश दुनिया

पोलियो उन्मूलन के प्रयासों में विफलता चिंता की बात

छह महीने में छह मामले. पिछले पूरे वर्ष की संख्या आधे समय में ही पूरी हो गयी. पोलियो वायरस को समाप्त करने या उस पर काबू पाने में पाकिस्तान के प्रयास विफल होते दिख रहे हैं. विदित हो कि बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा देश से पोलियो उन्मूलन के लिए भारी धनराशि खर्च की गयी है. फिर भी एक अवधि के बाद, जब हम 'पोलियो मुक्त' का गौरव हासिल करने के लिए तैयार थे, तब देश उल्टी दिशा में चलने लग गया है. दुनिया की पोलियो समस्या का आधा बोझ पाकिस्तान पर है, युद्धग्रस्त अफगानिस्तान को छोड़कर यह एकमात्र ऐसा देश है, जहां पोलियो वायरस का प्रसार जारी है. इस रोग को समाप्त करने में पाकिस्तान की लगातार विफलता के पीछे के कारण सर्वविदित हैं. फिर भी सरकार और अधिकारी वैसे क्षेत्रों में टीकाकरण का अनुपालन कराने में असमर्थ रहे हैं, जहां की जनसंख्या टीकाकरण को लेकर अस्वीकृति जताती रही है. कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह, अधिकारियों को अपनी बात मजबूती से रखनी होगी. यह अस्वीकार्य है कि एक ऐसी बीमारी, जिसका पूरी तरह रोकथाम संभव है, उससे विकलांग होने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि जारी है. जबकि सरकार फर्जी अफवाहें फैलाने और टीकाकरण को लेकर अस्वीकृति को प्रोत्साहित करने वाले तत्वों पर लगाम लगाने या दंडित करने में विफल रही है. बेशक, एक नैतिक कारण है कि किसी को भी दवा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. परंतु इसके साथ ही, पोलियो रोधी टीका लेने या अपने बच्चों को इसे पिलाने से इनकार करने वाले किसी भी व्यक्ति को औपचारिक रूप से दंडित करना शुरू करने के अच्छे नैतिक कारण भी हैं. सरकार को पोलियो कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने पर तत्काल रोक लगाना चाहिए, जो पहले से ही अत्यधिक जोखिम उठाते हैं. सरकार को पोलियो उन्मूलन के लिए हाल की तुलना में कहीं अधिक संकल्पित होने की आवश्यकता है.

DAWN

बोधि वृक्ष

भीतर छुपी शांति

हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोग बौद्धिक रूप से पहले से कहीं अधिक विकसित हैं. किंतु इतनी प्रगति के बावजूद भी अभी तक शांति के लिए हमारी भूख पहले से कई गुणा अधिक होती जा रही है. भला ऐसा क्यों? क्यों हमारे भौतिक और बौद्धिक संवर्धन के बावजूद हमें शांति नहीं मिल पायी है? इसके उत्तर के लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है. वास्तव में जिस शांति की खोज में हम दर-दर भटकते हैं, वह हमारी मूल प्रकृति है. जिसे हम अज्ञानतावश भूल गये हैं. जब हम हमारी मूल सकारात्मक ऊर्जा खो देते हैं, तब नकारात्मकता धीरे से हमारे मन के अंदर प्रवेश कर लेती है और फिर हमारे कर्मों में उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है, परिणामस्वरूप, हमें अत्यंत दुख की अनुभूति होने लगती है. ज्योंही हमें दुख की प्राप्ति होनी शुरू होती है, हम उससे निजात पाने के प्रयासों मे लग जाते हैं. शांति प्राप्त करने की हमारी इस जद्दोजहद में हम और आक्रामक बन जाते हैं. किंतु हम भूल जाते हैं कि शांति प्राप्त करने के हमारे प्रयास कुछ मानवीय बाधाओं द्वारा सीमित हैं, जिसमें पहली बाधा मानव शरीर की है. हम न तो अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ जानते हैं, न ही भविष्य के बारे में. यदि हम कुछ जानते हैं तो वह है हमारा वर्तमान जन्म. इसलिए वर्तमान में स्वयं को अनुशासित करने के लिए बनाये गये कर्म के वैश्विक कानूनों के निहितार्थ को हम समझ नहीं पाते और अयथार्थ कर्म करते तथा स्वयं व अन्य को दुख देते जाते हैं. इसके अतिरिक्त, हम भौगोलिक, पर्यावरण, सांस्कृतिक और धार्मिक बाधाओं से विवश होकर एक सार्वभौमिक सहानुभूति को विकसित करने में भी असफल हो जाते हैं. परिणामस्वरूप, विश्व स्तर पर कार्य करने के बजाय अपनी बनायी छोटी सी दुनिया में सिमटकर रह जाते हैं. हमें समझना होगा की शांति एक सामूहिक भावना है. इसलिए, जब तक हम स्वयं के साथ-साथ समाज एवं पर्यावरण में शांति स्थापित करने के कदम नहीं उठायेंगे, तब तक सार्वभौमिक शांति बनाये रखने के हमारे सारे मंसूबे असफल सिद्ध होंगे.

-ब्रह्माकुमार निकुंज जी

स्मृति शेष

सरल और संवेदनशील अधिकारी थे मुचकुंद दुबे

वीएस दुबे
बिहार एवं झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव
delhi@prabhatkhabar.in

भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और देश के पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे एक बेहद सरल, सहज एवं संवेदनशील अधिकारी थे. वे हमेशा समाज की बेहतरी की चिंता करने वाले अधिकारी रहे. हालांकि वे मेरी सेवा के अधिकारी नहीं थे, परंतु पटना स्थित एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टिट्यूट (आद्री) में उनसे मुलाकात होती रहती थी. वे सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे थे. इसी क्रम में वे आद्री के भी अध्यक्ष रहे. विदेश नीति के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक विषयों पर उनकी पकड़ जबरदस्त थी. अध्ययन-अध्यापन के प्रति उनकी ललक ही थी कि विदेश सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने और वहां करीब आठ वर्ष तक पढ़ाया. उनकी योग्यता के कारण ही उन्हें यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारतीय सदस्य, बिहार में कॉमन स्कूल सिस्टम कमीशन का अध्यक्ष और सिक्किम के योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था.

बिहार में जब नवंबर, 2005 में नयी सरकार बनी, तो उन्हें समान स्कूल सिस्टम कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था. उन्होंने अपनी सारगर्भित रिपोर्ट में कई सुझाव दिये थे. इस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार में योगदान दिया. कमीशन का मानना था कि अमीर और गरीब को एक समान शिक्षा मिले. इससे सामाजिक खाई पाटने में मदद मिलेगी. उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध, भारत का सामाजिक और आर्थिक विकास, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और निरस्त्रीकरण, अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग और विश्व व्यवस्था के मुद्दे रहे हैं. उन्होंने दो पुस्तकें लिखी हैं- 'असमान संधिः गैट के बाद विश्व व्यापार व्यवस्था' और 'भारत की विदेश नीतिः बदलती दुनिया से मुकाबला'. उन्होंने तीन पुस्तकों का संपादन किया है, जिनमें शामिल हैं, आज का भारतीय समाजः समानता, एकीकरण और सशक्तिकरण की चुनौतियां. उन्होंने छह पुस्तकों का सह-संपादन भी किया है.

मुचकुंद दुबे

मुचकुंद दुबे का जन्म अविभाजित बिहार में हुआ था, परंतु झारखंड के अलग हो जाने के बाद भी उनका संबंध और संपर्क बिहार से बना रहा. आद्री की बैठकों में वे नियमित रूप से शामिल होते रहते थे. इस दौरान उनकी बिहार को लेकर चिंता, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्पष्ट रूप से दिखी तथा विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने कई सुझाव भी दिये. बाद के दिनों में भी उनका बिहार से लगाव बना रहा. वे विदेश नीति के अच्छे जानकार थे. उनके नहीं रहने से एक खालीपन का अहसास हो रहा है, जिसे पाटना कठिन होगा. शिक्षा के क्षेत्र में, विदेश नीति के क्षेत्र में और सामाजिक व कला के क्षेत्र में मुचकुंद दुबे की समान रुचि रही थी, जो उनकी प्रतिभा और मेहनत का परिचायक है. **(बातचीत पर आधारित)**

आपके पत्र

पुल निर्माण में हो रही भारी गड़बड़ी

बिहार में पिछले आठ दिनों में एक-एक कर चार निर्माणाधीन पुल के पाये धंस गये. इससे साफ होता है कि पुल का निर्माण करनेवाले ठेकेदार व कंपनी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रख रही है.इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है. लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि पुल के निर्माण के लिए ठोस नीति बनाने के साथ उनके मेंटेनेंस के लिए कानून बनाये. साथ ही पुल गिरने की उच्चस्तरीय जांच कराने के साथ दोषी ठेकेदार और अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये.

आनंद पांडेय, समस्तीपुर

पेपर लीक होने से छात्रों में मायूसी

प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से योग्य लोगों को चुना जाता है. लेकिन, पेपर लीक होने से प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को निराशा हाथ लगती है. उनकी जगह अयोग्य लोग चुन लिये जाते हैं. लगभग सभी राज्यों में प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और अनियमितता की शिकायत मिली है. हर बार सरकार जांच का आदेश देती है व खामियों को दूर करने का भरोसा दिलाती है, लेकिन समस्याएं बदस्तूर जारी हैं. इसका ताजा उदाहरण नीट परीक्षा में पेपर लीक का मामला है. हालांकि, इसकी जांच चल रही है.

हिमांशु शेखर, गया

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

ब्रांड वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए मानवीय मूल्य

भेदभाव से मुक्त समाज की रचना का लक्ष्य पाने के लिए जितनी शिद्दत से कोशिश होनी चाहिए वह हो नहीं रही है। कई मौकों पर भेदभाव जानबूझकर किया जाता है तो कहीं अनजाने में ऐसा होता रहता है। भेदभाव का ताजा उदाहरण दुनिया की नामचीन मोबाइल फोन निर्माता कंपनी के लिए भारत में उत्पाद को तैयार करने वाली कंपनी के प्लांट का है। यहां विवाहित महिलाओं को सिर्फ इसलिए नौकरी पर रखने से मना किया जा रहा है कि ऐसा करने में 'रिस्क फैक्टर' है। कंपनी का मानना है कि विवाहित महिलाओं को नौकरी देने पर उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों और संभावित गर्भधारण की वजह से काम प्रभावित होने का जोखिम है।

हैरत की बात यह है कि कंपनी के पूर्व अधिकारी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन वर्तमान अधिकारी नहीं। इस भेदभाव की शिकार महिलाओं के सामने आने और शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। भारत में स्थित प्लांट में नामचीन कंपनी के सबसे जरूरतें उत्पादन को प्रभावित करती प्रतीत होती हैं। मशीन के इस्तेमाल में नैतिक और सामाजिक मूल्यों की बाधा नहीं आती। न तो वर्किंग ऑवर की चिंता रहती है और न ही कर्मचारियों के अनुपस्थित होने की। आर्टिफिशियल इंजेलिजेंस (एआइ) की ओर बढ़ता रुझान मशीन पर पूरी निर्भरता की ओर ले जा रहा है। इसका असर आने वाले समय में जीडीपी में बढ़ोतरी के रूप में दिख सकता है और देश विकास के नए सोपान भी गढ़ सकता है। लेकिन समझना होगा कि विकास के सोपान मूल्यहीन धारणाओं पर आधारित होने चाहिए या उच्च मूल्यों वाले। प्रोडक्ट का मूल्यवान होना ही काफी होगा या उसे बनाने वाले और इस्तेमाल करने वाले हाथों का भी कोई मूल्य बचेगा?

प्रकृति भेदभाव नहीं करती, लेकिन हमारे भेदभाव का शिकार वह जरूर होती है। मनुष्य को यह भी समझना होगा कि धरती सिर्फ उसी के लिए नहीं है। इस समझ की शुरुआत स्त्री-पुरुष में भेदभावपूर्ण व्यवस्थाओं को मिटाकर ही हो सकती है। धरती पर टिकाऊ जीवन के लिए यह जरूरी शर्त है।

ब्रिटेन में चुनाव : बाहरी लोगों के कारण सामाजिक ताना-बाना प्रभावित होने की आशंका है ब्रिटेन के लोगों को

राजनीतिक फुटबॉल बना प्रवासन का मुद्दा

क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के प्रति दीवानगी रखने वाला ब्रिटेन इन दिनों बड़ा व्यस्त है। इन दोनों ही खेलों की बड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। एक ओर क्रिकेट विश्व कप तो दूसरी ओर फुटबॉल यूरो कप। इन दोनों खेलों के बीच चुनाव का आकर्षण भी कम नहीं है। इस बार चुनाव में प्रवासन का मुद्दा भी केंद्र में है। यह मुद्दा ब्रिटेन के सभी राजनीतिक दलों की 'राजनीतिक फुटबॉल' बना हुआ है जिसे वे जब चाहें दूसरे को 'पास' कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। चुनाव की अंतिम डिबेट में ऋषि सुनक और कीर स्टार्मर आमने-सामने थे। इस दौरान अन्य मुद्दों के साथ प्रवासन व शरणार्थियों के मुद्दे पर भी तीखी बहस हुई।

ब्रिटेन के चुनाव में अब कुछ दिन ही शेष हैं। आम धारणा यह बन चुकी है कि कंजर्वेटिव पार्टी के 14 वर्ष के शासन के बाद इस बार लेबर पार्टी सत्ता में आने में कामयाब रहेगी। प्रवासन का मुद्दा दशकों से ब्रिटेन की राजनीति के लिए एक यक्षप्रश्न रहा है। यहां के नागरिक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वैध-अवैध रूप से ब्रिटेन में निरंतर बड़ी संख्या में आ रहे लोगों से सामाजिक ताना-बाना गड़बड़ा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, आवास व शिक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। 2016 में यूरोपियन यूनियन छोड़ने (ब्रेग्जिट) के लिए हुए जनमत संग्रह में भी प्रवासन प्रमुख मुद्दा था। अन्य यूरोपीय देशों से ब्रिटेन आने वाले लोगों की मुक्त आवाजाही रोकने की मांग ने ब्रेग्जिट रेफरेंडम में अहम भूमिका निभाई। 52 फीसदी प्रतिभागियों ने ईयू से अलग होने का समर्थन किया। ब्रेग्जिट समर्थकों का दावा था कि इससे ब्रिटेन को अपनी सीमाओं को पूरी तरह नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

लंदन से 'पत्रिका' के पाठकों के लिए

मानवाधिकार कानून की शिक्षक **डॉ. हीथर एलेंसडोटिर** व 'अमरीका बनाम अमरीका' पुस्तक के लेखक **द्रोण यादव** का ब्रिटेन के राजनीतिक परिदृश्य पर एक विश्लेषण

@patrika.com

प्रवासन को रोकने की नीतियां अपनी जगह हैं, पर विभिन्न जगह से आने वाले शरणार्थियों को व्यवस्थित तरीके से बसाने की नीतियां भी आवश्यक हैं।

ब्रेग्जिट समर्थकों का यह दावा था कि यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद अन्य यूरोपीय देशों से ब्रिटेन में लोगों की मुक्त आवाजाही समाप्त हो सकेगी, हालांकि प्रवासन जारी रहा। पिछले माह जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2022 में 7,64,000 और 2023 में 68,500 लोगों का आव्रजन हुआ। सरकारी आंकड़े यह भी बताते हैं कि 2024 के प्रथम चार महीनों में विद्यार्थियों के आश्रितों के आवेदन में 79 प्रतिशत की कमी के साथ 30,000 विद्यार्थी वीजा में कमी आई है, जबकि स्वास्थ्य व देखभाल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के आश्रितों के आवेदन में 58 प्रतिशत तक की कमी आई है। इस गिरावट का एक मुख्य कारण यूक्रेन युद्ध में मानवीय आधार पर वीजा हासिल करने वाले लोगों की संख्या में कमी आना भी थी। कुछ विशेषज्ञों की मानें तो ब्रिटेन में प्रवासियों का आना कई तरह से लाभकारी भी होता है। प्रवासन पर हुए कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि विदेशी श्रमिकों का वेतन या रोजगार के स्तर पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। प्रवासन में वृद्धि से सार्वजनिक सेवाओं की मांग में बढ़ोतरी होती है, प्रवासी टैक्स भी प्रदान करते हैं। लेबर पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी की रवांडा नीति को बदलने का वादा किया है जिसके अनुसार ब्रिटेन में शरण मांग रहे शरणार्थियों को जबरन रवांडा भेज दिया जाना था।

उधर रिफॉर्म पार्टी के निगेल फराज हैं जो ब्रिटेन में प्रवासन को शून्य करने की वकालत करते हैं। उनका अच्छा खासा असर इसलिए भी है क्योंकि उनकी पार्टी का गठन ब्रेग्जिट के दौरान ही हुआ। वह शुरू में ब्रेग्जिट पार्टी कहलाई लेकिन फिर बाद में इसका नाम बदल कर रिफॉर्म पार्टी कर दिया गया। इन्हीं निगेल फराज ने ब्रिटेन चुनावों की एक डिबेट में इस चुनाव को 'इमिग्रेशन इलेक्शन' कहा, जिससे इन चुनावों में इस मुद्दे की महत्ता भी सिद्ध होती है। एक शोध की मानें तो 43 प्रतिशत ब्रिटिश नागरिकों का मानना है कि प्रवासन के फायदों से ज्यादा नुकसान हैं। कुशल श्रमिक वीजा के लिए वेतन सीमा लगभग दोगुनी कर दी गई तो आश्रितों के साथ देखभाल करने वाले कर्मचारियों को साथ लाने से प्रतिबंधित कर दिया। करीब एक वर्ष पहले सुनक ने 'स्टॉप द बोट्स' नाम से एक मुहिम भी चलाई जिसका मकसद नावों के माध्यम से बड़ी संख्या में इंग्लैंड में घुस रहे शरणार्थियों को रोकना था। सुनक ने नए नियम पेश कर प्रवासियों को ब्रिटेन में आने से रोकने के लिए कई प्रयास किए। इनमें विदेशी विद्यार्थियों को अपने परिवार के सदस्यों को साथ लाने से रोका गया। सरकार का यह भी कहना रहा है कि ज्यादा संख्या में छात्र व देखभाल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों तथा उनके आश्रितों के आगमन के कारण प्रवासन में वृद्धि हो रही है। इसके बावजूद, हालात ये हैं कि ब्रिटेन में शरणार्थी लगभग हर रोज दाखिल हो रहे हैं। हाल ही में इस साल का रेकॉर्ड तब कायम हो गया जब कुछ दिन पहले एक ही दिन में 882 शरणार्थी कई छोटे-छोटे जहाजों से इंग्लैंड में दाखिल हो गए। प्रवासन रोकने का वादा करने वाली कंजर्वेटिव पार्टी, अपना वादा निभाने में विफल रही, यह भी उसके पिछड़ने का एक अहम कारण है।

ब्रिटेन की प्रवासन रोकने की सभी नीतियां अब तक 'तुगलकी' और विफल साबित हुई हैं, फिर चाहे वह ब्रेग्जिट हो या 'स्टॉप द बोट्स' मुहिम। महंगाई और रोजगार जैसे प्रमुख मुद्दों को भी अब प्रवासियों व शरणार्थियों की बढ़ती संख्या से ही जोड़ कर देखा जा रहा है। इस बात को समझना होगा कि प्रवासन का यह मुद्दा ब्रिटेन तक सीमित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक पिछले वर्ष विश्वभर में 11 करोड़ से अधिक लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा जिसका मुख्य कारण कुछ देशों के बीच चल रही जंग और जलवायु परिवर्तन आदि हैं। इससे यह तो साफ हो जाता है कि जितनी जरूरत प्रवासन को रोकने की नीतियों की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत ऐसी नीतियों की है जो प्रभावित शरणार्थियों को इस तरह व्यवस्थित कर सकें कि ब्रिटेन जैसे देशों का पारिस्थितिक तंत्र भी प्रभावित न हो।

फैक्ट फ्रंट

हत्याकांड बन गया विश्व युद्ध का कारण

ऑस्ट्रिया राजसिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की 28 जून 1914 को बोस्निया के साराजेवो में हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ गया। इस हत्या का आरोप सर्बिया पर लगाया गया। दोनों के मध्य पहले से ही चल रहे कटु संबंधों के कारण ऑस्ट्रिया को सर्बिया से बदला लेने का मौका मिल गया। इस युद्ध में विभिन्न देश शामिल होते गए और अंततः युद्ध ने विश्वव्यापी रूप ले लिया। यूरोप में अशांति पहले से ही थी, इस हत्याकांड ने तो केवल आग में घी का काम किया।

प्रसंगवश

रैगिंग को रोकने के लिए संस्थानों को रहना होगा चौकस

रैगिंग बुराई ही नहीं, कानूनन अपराध भी है; आज के दौर में भी इसका जारी रहना चिंताजनक है, इसे रोका जाना चाहिए

उच्च शिक्षण संस्थानों की समाज और देश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। यहां से निकलने वाले युवा विभिन्न क्षेत्रों में अपने ज्ञान और बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करते हैं। उनसे बेहतर समझ और नैतिकता की अपेक्षा की जाती है। लेकिन जब इन संस्थानों में रैगिंग के मामले सामने आते हैं, तो चिंता होना स्वाभाविक हो जाती है। सख्त कानून और उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के बावजूद इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग के मामले सामने आने से इन शिक्षण संस्थानों का कुप्रबंधन भी उजागर हो जाता है। राजस्थान में डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज में भी इसी तरह का मामला सामने आया है। एक विद्यार्थी को रैगिंग के लिए भरी गर्मी में एक पहाड़ी पर ले जाया गया और उससे उठक-बैठक कराई गई। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे आइसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। रैगिंग के कारण उसकी किडनी और लिवर पर गंभीर असर हुआ। डायलिसिस तक की नौबत आ गई।

जाहिर है रैगिंग के नाम पर नए विद्यार्थियों का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न अभी नहीं रुका है। यह मामला तो इसलिए सामने आ गया कि विद्यार्थी की हालत ज्यादा बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पूछताछ में विद्यार्थी ने सच बता दिया। यदि तबीयत नहीं बिगड़ती तो इस बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि चाहे रैगिंग पर प्रतिबंध है, लेकिन छात्र-छात्रा इसके अब भी शिकार हो रहे हैं, लेकिन वे अपनी पीड़ा बताने में झिझक रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के कड़े रुख के बाद यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में एंटी रैगिंग कमेटियां बनाने के निर्देश दे रखे हैं। हर शैक्षणिक संस्थान में अब एंटी रैगिंग कमेटी है। कोई भी विद्यार्थी इस कमेटी के किसी भी सदस्य से मिलकर शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके बावजूद रैगिंग से जुड़ी शिकायत दर्ज करवाने में विद्यार्थी झिझक रहे हैं। जाहिर है शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन का या तो विद्यार्थियों से संवाद नहीं है या फिर जानबूझकर ऐसे मामलों की अनदेखी की जा रही है। जब मामला बढ़ जाता है तो जांच कमेटी का गठन और दोषी विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई जैसे कदम उठाए जाते हैं। रैगिंग बुराई ही नहीं, कानूनन अपराध भी है। इसे हर हालत में रोका जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन को चौकस रहना होगा और विद्यार्थियों से संवाद बनाए रखना होगा ताकि उसे समय रहते सही सूचना मिल सके और तुरंत उचित कदम उठाए जा सकें।

- ज्ञान चंद पाटनी
gyan.patni@epatrika.com

सामयिक : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर पैदा विवाद के बाद फोकस शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन पर होना चाहिए

शिक्षा प्रणाली पर जरूरी बहस की पर्याप्त वजह है एनटीए की नाकामी

पिछले कुछ दिनों से शिक्षा मंत्रालय का स्वायत्तशासी निकाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) विवादों में है। विवादों की शृंखला ने पूरे देश में छात्रों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इस निकाय पर उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी है। परीक्षा केंद्रों में कई अनियमितताओं और मानकों का अनुपालन न होने को लेकर एजेंसी पर कई आरोप हैं। नीट परिणाम, जो 4 जून को घोषित हुआ, से पूरे देश में अभ्यर्थियों में आक्रोश फैल गया। कई मुद्दे सामने आए, जैसे 1,500 से अधिक छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया जाना और सबसे बढ़कर प्रश्नपत्र का लीक होना। एनटीए, एनईईटी-यूजी और यूजीसी-नेट परीक्षा को कुशलता के साथ और त्रुटि रहित तरीके से आयोजित करने में पूरी तरह विफल रहा है। इस घटना ने न केवल छात्रों के आत्मविश्वास को डिगाया है, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता पर भी संदेह की छाप छोड़ दी है। हालांकि, एनटीए मुखिया का निलंबन और जांच आयोग का गठन वास्तविक मुद्दे को सुलझाने की विशुद्ध कोशिशों की तुलना में ज्यादा मजबूरी ही प्रतीत हुए। ऐसे वक्त में, जब हितधारक पारदर्शिता और जवाबदेही की सख्त मांग कर रहे हैं, यह देखा जाना है कि क्या ये कार्रवाई वास्तव में विश्वास बहाली के लिए पर्याप्त हैं अथवा लोगों के आक्रोश से बचने के लिए महज दिखावटी समाधान हैं।

ज्योतिका कालरा
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और एनएचआरसी की पूर्व सदस्य

@patrika.com

मुद्दा केवल नीट और नेट तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह हमारी शिक्षा व्यवस्था की समग्रता पर भी सवाल खड़े करता है। सबसे पहले, इस तरह की प्रवेश परीक्षा का अपरिहार्य होना अपने आप में ही बेतुकापन लिए हुए है, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी में आवेदन करने से पहले ही छात्र अर्हता परीक्षा दे चुके होते हैं। एक भारतीय छात्र स्कूली जीवन के रूप में औसतन 14 साल व्यतीत करता है। यह एक बड़ा सवाल है कि यदि यह अवधि उनकी बुद्धिमत्ता या क्षमताओं के स्तर को मापने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो हम कुछ घंटों में उनके स्तर को कैसे माप सकते हैं? इसके अलावा यह विचार भी उचित दृष्टिकोण वाला नहीं लगता कि जो भी प्रवेश परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेगा, वह सबसे योग्य होगा। वास्तव में, समूची स्कूली शिक्षा के महत्त्व को कम ही कर रही हैं कुछ घंटों की ये प्रवेश परीक्षाएं।

तर्क दिया जा सकता है कि ऐसी व्यवस्था को लागू करने के मूल में पूरे भारत के छात्रों की काबिलियत को एक सामान्य पैमाने यानी सीयूईटी स्कोर पर मापना है, चाहे वे किसी भी राज्य के हों। कथित तौर पर एक वजह यह भी दी जाती है कि कुछ राज्यों के बोर्ड अपने छात्रों को अंक देने में उदार थे, अन्य राज्यों की तुलना में। लेकिन क्या यह ज्यादा विवेकपूर्ण नहीं होता कि नई प्रणाली बनाने के बजाय राज्यों ने अपने मौजूदा शैक्षणिक ढांचे को मजबूत किया होता और कुछ मानदंड पेश किए होते। समस्या का हल कैसे निकाला जाए इसकी शुरुआत इस गलत दृष्टिकोण से भी कर सकते हैं कि राज्यों के बोर्ड या स्कूल अपने छात्रों की क्षमताओं का आकलन करने में सक्षम नहीं हैं। बात यहीं तक सीमित नहीं है। शिक्षा प्रणाली में एक और परत जोड़ने के गंभीर वित्तीय दुष्प्रभाव भी हैं – राज्यों के लिए भी और छात्रों के लिए भी।

एनटीए की विफलता से देश में जो तूफान उठा है, उसे खतरे की घंटी के रूप में देखा जाना चाहिए। यह हमें उन कमजोरियों का स्मरण कराता है जिनके कारण लंबे समय से भारत की शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंच रहा है। कड़े सुरक्षा उपाय और उन्नत तकनीक अपनाकर हम अधिक पारदर्शिता और समग्र दृष्टिकोण के साथ उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं जहां हर छात्र को योग्यता और उनकी कड़ी मेहनत से सफल होने का उचित मौका मिलेगा। हम सभी के लिए यह आत्मनिरीक्षण का समय है ताकि हमारे युवा भविष्य में असुरक्षित न रहें।

दबाव और तनाव मुक्त बनाना होगा प्रवेश परीक्षा की पूरी व्यवस्था को

लगभग पच्चीस वर्ष पहले, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे के निदेशक प्रो. सुहास सुखातमे ने जब अपना कार्यकाल पूरा किया तो उनका एक साक्षात्कार एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकशित हुआ था। उनसे पूछे गए कई सवालों में एक यह भी था कि निदेशक के रूप में पांच साल में उनके कुछ मुख्य कार्य कौन-से रहे। उन्होंने तुरंत ही एक लाइन में जवाब दिया- 'किसी ने भी मुझे अपने बच्चे के एडमिशन की व्यवस्था करने के लिए नहीं बुलाया।' यह जवाब गहरा महत्त्व लिए है। पहला, यह साफ है कि आप निदेशक को प्रभाव में लेकर अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा सकते। दूसरा, कोई भी इस 'तंत्र' में प्रभाव के इस्तेमाल के बारे में सोचता भी नहीं था। चाहे मंत्री हों या उद्योगपति, राजनीतिक नेता या फिर विशिष्ट वर्ग, किसी के लिए प्रवेश प्रक्रिया के बिना अन्य उपायों से प्रवेश दिलाना अकल्पनीय था। यह पैमाना अलिखित और आदर्श था, जो वर्षों से संहिता बन गया था। संयुक्त प्रवेश परीक्षा की पवित्रता में विश्वास के कारण यह मानदंड कायम रहा। आइआइटी में प्रवेश की प्रणाली लगभग चार दशकों तक चली जब देश में केवल पांच आइआइटी थे और प्रवेश और आवेदकों की संख्या का प्रबंधन मुश्किल नहीं था। तब आइआइटी रोटेशन के आधार पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन करते थे।

आइआइटी समूह ने लगातार यह सुनिश्चित किया कि मानदंड पवित्र और कायम रहें तथा इसकी समग्रता से समझौता न हो, पर यह स्थिति कायम नहीं रह सकी। आइआइटी में प्रवेश काफी चुनौतीभरा हो गया। कोचिंग क्लास उद्योग ने स्थिति को और विकट कर दिया। अंततोगत्वा आइआइटी की संख्या बढ़ी, सीट बढ़ीं और आवेदकों की संख्या भी। देश के सभी प्रमुख इंजीनियरिंग और मेडिकल सीटों के लिए 2013 के आसपास 'एक राष्ट्र, एक परीक्षा' पर गहन नीतिगत चर्चा हुई। इसका उद्देश्य पूरे देश में एक समान मानक बनाना था। कोचिंग उद्योग के चलते आवेदकों के लिए जिस तरह असमान माहौल तैयार हुआ, उसे लेकर भी गहरी चिंता थी। अंततः 'एक परीक्षा' मॉडल पर बात बनी। 2017 में अलग से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी स्थापित की गई और आज एनटीए चार बड़ी परीक्षाएं करा रहा है। इन परीक्षाओं को लेकर पिछले कुछ वर्षों का अनुभव बाधामुक्त नहीं रहा है। छात्रों और अभिभावकों में बेचैनी बढ़ी है। जेईई हो या नीट, प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों पर अमानवीय दबाव और इसके चलते कोटा में आत्महत्या की घटनाओं को भी नहीं भूलना चाहिए। इस साल दो बड़ी परीक्षाओं नीट (यूजी) और यूजीसी-नेट को लेकर बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ। नीट परीक्षा 571 शहरों और 4750 केंद्रों पर 24 लाख छात्रों ने दी थी, लेकिन बेतुके परिणाम सामने आए। 67 विद्यार्थियों को पूर्ण अंक प्राप्त हुए, जिनमें से छह विद्यार्थी एक ही केंद्र से एक ही क्रम में थे। इसके अलावा ग्रेस मार्क्स की वजह बताई गई कि प्रश्नपत्र देर से पहुंचे थे। अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है।

डॉ. अजीत रानाडे
वरिष्ठ अर्थशास्त्री व विचारक (द बिलियन प्रेस)

@patrika.com

बिहार और गुजरात में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है, न ही छात्रों-अभिभावकों के लिए अनकहा तनाव। ऐसे में बड़े पैमाने पर बदलाव और सुधारों की जरूरत है। तकनीक-आधारित समाधान भारत में कई जगह उपयोग में लिए जा चुके हैं, उन्हें समान रूप से अपनाने की जरूरत है। एक परीक्षा और एक नेशनल टेस्टिंग निकाय पर बहुत ज्यादा संसाधन झोंकना भी कम करना होगा। मांग और आपूर्ति में भारी अंतर को भी कम करना होगा। नहीं तो लाखों युवा उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए कष्टसाध्य पढ़ाई के दबाव और मनोवैज्ञानिक बोझ तले अपनी युवावस्था के महत्त्वपूर्ण वर्षों को गंवाते रहेंगे, जिनमें सफल होने की संभावना लॉटरी निकलने से भी ज्यादा दुष्कर है।

आत्म-दर्शन

सफलता की कुंजी

यदि हम अपने राष्ट्र को शिखरस्थ और सर्वसमर्थ देखना चाहते हैं तो शैक्षणिक गुणवत्ता, आत्म-अनुशासन तथा चरित्र निर्माण की दिशा में हमारी सक्रिय सहभागिता रहे। आत्म-अनुशासन और उच्च चरित्र ही राष्ट्र निर्माण के प्रारम्भिक साधन हैं। अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है- अनु और शासन। अनु उपसर्ग है जो शासन से जुड़ा है, जिससे अनुशासन शब्द बना है। इसका अर्थ है - किसी नियम के अधीन रहना या नियमों के शासन में रहना। हमारे जीवन के हर एक काम के लिए उत्कृष्ट अनुशासन की आवश्यकता होती है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में तो अनुशासन की बहुत आवश्यकता होती है। यह एक कटु सत्य है कि अनुशासन के बिना सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। जिस देश के लोग अनुशासित हैं, जहां की सेना अनुशासित है, वह देश निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा, वह सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ता रहेगा। जीवन में सफलता की कुंजी अनुशासन है। अनुशासन के आधार पर हमारे जीवन का भविष्य तय होता है।

स्वामी अवधेशानंद गिरि

@patrika.com

तुर्की : देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा तुज झील का गुलाबी रंग

तुर्की में दूसरी सबसे बड़ी झील है तुज झील, जिसे 2001 में विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। 1,665 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली यह झील दुनिया की सबसे बड़ी हाइपरसैलाइन झीलों में एक थी। अंकारा से 150 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व में सेंट्रल एनाटोलिया क्षेत्र में स्थित तुज झील अक्टूबर 2021 में पूरी तरह से सूख गई थी। कुछ पर्यटक अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य के बीच सैर का आनंद लेते हैं, जबकि अन्य चिकित्सीय लाभ प्राप्त करने के लिए झील के खारे पानी में नंगे पांव चलना पसंद करते हैं। झील में संचालित तीन खदानों से तुर्की में नमक की खपत के 63% हिस्से का उत्पादन होता है। शैवाल और बैक्टीरिया की अधिकता के कारण इसका रंग गुलाबी होने लगा है। रंग में इस बदलाव ने तुज झील को स्थानीय और विदेशी दोनों पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बना दिया है।

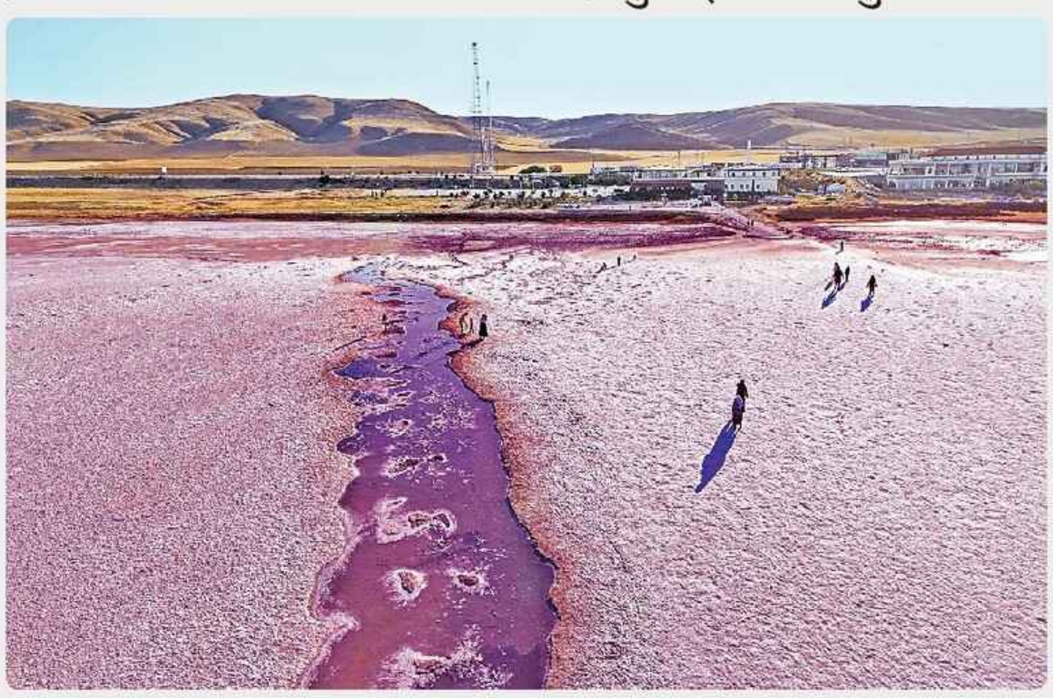

आपकी बात

सरकार की प्राथमिकता नहीं

सरकार की प्राथमिकता में जल प्रबंधन नहीं है। इसलिए इस तरफ खास ध्यान भी नहीं दिया जाता है। इससे जल संकट बना रहता है और लोग परेशान होते रहते हैं।

-संजय वर्मा, भोपाल, मप्र

आज का सवाल

खराब जीवनशैली सेहत को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'जल प्रबंधन को लेकर सरकारें गंभीर क्यों नहीं हैं?' प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।
https://shorturl.at/drpVZ

इसे स्कैन करें

https://epaper.patrika.com

दैनिक जागरण

हर इंसान इस पृथ्वी पर ईश्वर का मेहमान है

अनावश्यक आपत्ति

नई लोकसभा के गठन के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा, उससे मोदी सरकार के एजेंडे की ही झलक मिली। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि ऐसे अवसरों पर राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की रूपरेखा को ही रेखांकित करता है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हों, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण से यही स्पष्ट होता है कि यह सरकार पहले की तरह ही कार्य करेगी और उन कामों को पूरा करने पर विशेष ध्यान देगी, जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री पिछले कुछ समय से लगातार करते आ रहे हैं। इस सबके बाद भी वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि अपने तीसरे कार्यकाल में उन्हें संसद के भीतर और बाहर विपक्ष के तीखे तेवरों का सामना करना पड़ेगा। इसका एक बड़ा कारण उसके संख्याबल में वृद्धि होना है। संख्याबल में वृद्धि के चलते विपक्ष को जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल हुआ है, वहीं दूसरी ओर उसका मनोबल भी बढ़ा है। बीते तीन-चार दिनों में संसद में जो कुछ हुआ, उससे विपक्ष के बढ़े हुए मनोबल का ही पता चलता है। विपक्ष का उत्साहित होना स्वाभाविक है, लेकिन उचित यह होगा कि वह विरोध के लिए विरोध वाले रवैये का परित्याग करे। इसके स्थान पर उसे रचनात्मक विरोध का परिचय देना चाहिए। दुर्भाग्य से फिलहाल इसके आसार कम ही हैं और इसका संकेत राष्ट्रपति के अभिभाषण के कुछ बिंदुओं पर विपक्षी नेताओं की अनावश्यक आपत्ति से मिलता है। यह कोई नई-अनोखी या गोपनीय बात नहीं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की ओर से तैयार किया जाता है। आखिर ऐसे में यह कहने का क्या मतलब कि उनका अभिभाषण तो सरकारी भाषण है। ऐसा तो होता ही है।

यह आश्चर्यजनक है कि विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के उन बिंदुओं पर भी हंगामा किया, जिनका कोई औचित्य नहीं था। जब राष्ट्रपति ने प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की समस्या पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ठोस उपाय करने की जरूरत जताई तो विपक्ष को यह रास नहीं आया। क्या यह एक तथ्य नहीं कि बीते पांच वर्षों में केंद्रीय स्तर के साथ ही राज्य स्तर की भी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए हैं? विपक्ष तब भी आपे से बाहर होता हुआ दिखा, जब राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आपातकाल के काले कारनामों को याद किया। आखिर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस आपातकाल के जिक्र मात्र से क्यों भड़क जा रही है? कांग्रेस नेता आपातकाल का उल्लेख भर किए जाने से जिस तरह बिदक रहे हैं, उससे तो वे यही साबित कर रहे हैं कि आपातकाल का स्मरण किया जाना क्यों आवश्यक है। यह हैरानी ही नहीं, चिंता का भी विषय है कि कांग्रेस को आपातकाल के स्मरण पर भी आपत्ति है। बेहतर होगा कि सरकार का विरोध करते समय विपक्ष तनिक तार्किक रवैया अपनाए।

बढ़ानी होगी चौकसी

बिहार में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ और पाकिस्तानी अपराधियों की बढ़ती गतिविधियां चिंताजनक हैं। गत दिवस पुलिस ने पटना से दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम चंपारण के रहने वाले दोनों बदमाश पाकिस्तानी साइबर अपराधियों के संपर्क में थे। इन दोनों के अलावा राज्य के कई और युवक पाकिस्तानी अपराधियों के संपर्क में हो सकते हैं। संभव है कि जिस तरह सलमान खान पर हमला करने वाले युवकों की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम चंपारण से ही गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के संपर्क में रहने वाले आधा दर्जन युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उसी तरह इन साइबर अपराधियों के स्थानीय संपर्क सूत्र को भी खंगाला जाना चाहिए। प्रदेश में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन नए-नए मामले दर्ज हो रहे हैं। ये अपराधी कहीं से बैठकर लोगों को ठगी का शिकार बना लेते हैं। इनमें पाकिस्तानी मोबाइल नंबर का उपयोग अधिक हो रहा है। इसके अलावा देश की सुरक्षा से जुड़ी दस्तावेज को हनी ट्रैप के माध्यम से चुराने का मामला भी पकड़ में आया है। कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर के कटरा निबंधन कार्यालय में कार्यरत एक लिपिक ने आइएसआइ की महिला हैंडलर के हनी ट्रैप में फंसकर उसे रक्षा से जुड़ा दस्तावेज उपलब्ध करा दिया था। रवि यहां लिपिक बनने से पहले चेन्नई के अवाडी स्थित रक्षा मंत्रालय के भारी वाहन कारखाने में क्लर्क था। कंप्यूटर पर ड्यूटी के दौरान मिलने वाली गोपनीय दस्तावेज वह आइएसआइ एजेंट को बेच देता था। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने अलर्ट किया है और ऐसे मामलों की सूची मांगी है। बिहार में साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए साइबर थाने खोले गए हैं। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) भी मामलों की निगरानी करती है, लेकिन आम लोगों को भी सजग रहना होगा। संदिग्ध गतिविधियों वाले लोगों की जानकारी पुलिस को तत्काल उपलब्ध करानी चाहिए।

तिब्बत की आवाज बने भारत

शंकर शरण

जिस मुद्दे पर भारत ने चीन से धोखा खाया, उसे यानी तिब्बत को उठाकर ही सही मार्ग पाया जा सकता है

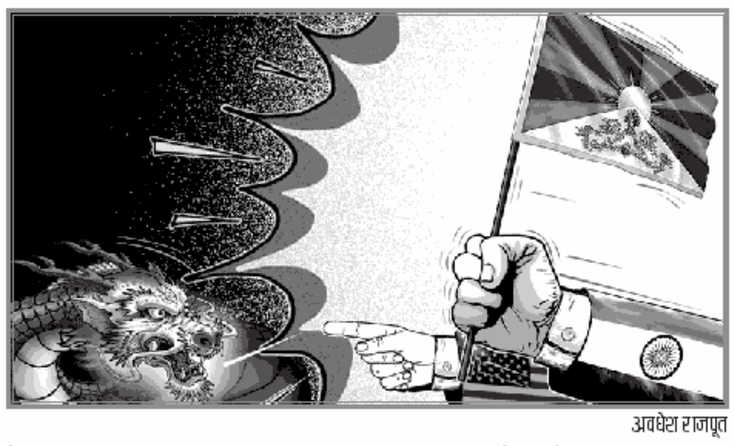

अवधेश राजपूत

अमेरिकी सांसदों का एक दल जिस तरह दलाई लामा से धर्मशाला आकर मिला, वह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दल के सांसदों में नैंसी पेलोसी भी थीं, जिन्होंने अमेरिकी संसद में 'रिसाल्व तिब्बत एक्ट' का विधेयक रखा है। इसमें तिब्बत समस्या के समाधान के लिए चीन पर दबाव डालने की सिफारिश है। इस विधेयक पर अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने से चीन पर तिब्बतियों से बातचीत करने का दबाव बनाने की अमेरिकी गंभीरता झलकेगी। इसका प्रभाव दुनिया के अनेक देशों पर भी पड़ सकेगा। इन देशों में सबसे महत्वपूर्ण भारत है। उल्लेखनीय केवल यह नहीं कि भारत ने अमेरिकी सांसदों के दल को धर्मशाला आकर दलाई लामा से मुलाकात करने की अनुमति दी, बल्कि इस दल से प्रधानमंत्री मोदी ने भी भेंट की। डोकलाम और गलवन घाटी पर भारत-चीन तनाव के संदर्भ में भी इसका संकेत स्पष्ट है। यदि भारत भी कूटनीति में चीन की तरह यथार्थवादी कदम उठाए तो आपसी संबंध सुधार की संभावना बढ़ेगी। केवल सदिच्छा और सांकेतिक बातों से भारत को आज तक कुछ लाभ नहीं हुआ। वस्तुतः तिब्बत ही भारत-चीन संबंधों की बीच की कड़ी है। इसकी अनदेखी से आपसी विश्वास नहीं बन सकेगा।

यहां स्मरणीय है कि बीजिंग में 1954 में हुआ पंचशील समझौता भारत-तिब्बत पर ही था। इस समझौते का शीर्षक ही है: ''चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और संबंध के बारे में।'' छह अनुच्छेदों के इस संक्षिप्त समझौते में कुल नौ बार तिब्बत का नाम आया है। इसमें से पांच अनुच्छेदों में केवल इसके वर्णन हैं कि भारत-तिब्बत संबंध पूर्ववत चलते रहेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से सौ-पचास साल कुछ नहीं होते। 1951 तक तिब्बत स्वतंत्र देश था। मार्च 1947 में दिल्ली में 'एशियन रिलेशंस कांफ्रेंस' में तिब्बत और चीन, दोनों ने स्वतंत्र देशों की तरह हिस्सा लिया था। 1914 में शिमला में चीन, तिब्बत और भारत ने आपसी सीमांकन समझौता भी किया था। यदि चीन 1890 के दस्तावेज का हवाला देकर डोकलाम को अपना बताता है, तो 1914 के दस्तावेज के अनुसार तिब्बत भी स्वतंत्र देश है। ऐसे तथ्य उठाकर ही भारत, चीन और तिब्बत, तीनों के बीच पहले की तरह परस्परता का संबंध बनने का मार्ग मिल सकता है। यह ठीक है कि 1949 में भारत से भूल हुई जब उसने चीनी कम्युनिस्टों को तिब्बत हड़पने दिया। उसके एवज में चीन ने भारत और तिब्बत को संतुष्ट करने के लिए पंचशील का उपाय किया। उसका सार यही था कि तिब्बत और भारत के सांस्कृतिक, व्यापारिक, सामाजिक संबंध पहले जैसे चलते रहेंगे-बिना किसी पासपोर्ट, वीजा या परमिट आदि के।

यह ऐतिहासिक सत्य है कि भारत और तिब्बत के संबंध सदियों से खुले और पारस्परिक थे, जिसमें चीन का कोई अवरोध न था। जब चीनी नेता पंचशील समझौते का हवाला देते हैं, तो भारतीय नेताओं को कहना चाहिए कि उसके अनुच्छेद दो और पांच के अनुरूप तिब्बती एवं भारतीय तीर्थयात्रियों की बेरोक-टोक यात्राएं पुनर्स्थापित की जाएं। वस्तुतः न्याय और व्यावहारिकता, दोनों का तकाजा है कि पंचशील समझौते के सभी छह अनुच्छेद लागू किए जाएं, अन्यथा तिब्बत और उसकी सहायता के लिए भारत समेत दुनिया के अन्य उदार देश उसी तरह स्वतंत्र हैं, जैसे अन्य देश किसी पीड़ित देश की मदद के लिए होते हैं। निर्मल वर्मा ने तिब्बत को 'संसार का अंतिम उपनिवेश' बताया था। भारत और तिब्बत को अपनी साझी चिंताओं और सांस्कृतिक जरूरतों पर बोलने का पूरा अधिकार है। यही पूरे मामले को सुलझाने का सूत्र है, पर अधिकांश नेता और बुद्धिजीवी 'तिब्बत रीजन आफ चाइना' की शब्दावली में सदैव चाइना पकड़ते हैं और तिब्बत भूल जाते हैं! वास्तव में होना उलटा चाहिए। सदैव तिब्बत का नाम लें और चीन को टोकें। भारत का पड़ोसी पहले तिब्बत है। उसके पार चीन है। पंचशील समझौता होने पर कई पत्र-पत्रिकाओं में खबर का शीर्षक था-भारत-तिब्बत समझौता। इसके दो-तीन दशक बाद भी दुनिया भर के नक्शों में तिब्बत अलग देश ही रहा। दुर्भाग्यवश भारतीय बुद्धिजीवी और नेता कई गंभीर चीजों का नाम लेते हैं, पर उसके अर्थ पर ध्यान नहीं देते, जबकि चीन यथार्थवादी होने के कारण तिब्बत और भारत दोनों के अधिकार से अवगत है। इसीलिए वह दलाई लामा पर सावधान रहता है। उनसे देसी-विदेशी नेताओं के मिलने-जुलने का विरोध करता है, जबकि भारत अपने कर्तव्य से चूक जाता है। यह विचित्र है कि जिस तिब्बत को लेकर भारत का समझौता बीजिंग से हुआ था, उस तिब्बत की बात भारत ही नहीं करता।

चीन द्वारा तिब्बत पर हमले के बाद संपूर्ण विश्व ने पहले भारत की ओर ही देखा था, क्योंकि उससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश भारत था। भारत द्वारा चीन का समर्थन करते रहने से ही दुनिया चुप रही। वरना तब तक कम्युनिस्ट चीन महाशक्ति क्या, मान्यता प्राप्त देश तक नहीं था! संयुक्त राष्ट्र में भी 1971 तक फारमोसा (ताइवान) को मान्यता थी। अमेरिका ने 1978 तक कम्युनिस्ट चीन से कूटनीतिक संबंध तक नहीं बनाए थे। यदि तिब्बत पर भारत आवाज उठाता, तो चीन मनमानी नहीं कर सकता था। वह भूल सुधारना भारत का अनिवार्य कर्तव्य है। उस पर चुप्पी रखने से भारत की हानि होती है। यदि भारत ने सहजता से तिब्बत का मुद्दा उठाया होता, तो चीन को भारत के साथ सद्भाव बनाने की चिंता होती। तिब्बत की स्थिति भी सुधरती। अभी तिब्बत असहाय लगता है, पर यदि भारत ने इसे विश्व-मंच पर उठा दिया, तो ऐसा नहीं रहेगा। चीनी सत्ता ने अपने देश में तानाशाही को औजार बनाया है, तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता भारत का साधन बन सकता है। तिब्बतियों को वैचारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अभियान चलाने में सहायता देना भारत के हाथ में है। ऐसा न करना स्वयं भारत की नैतिक प्रतिज्ञा के विरुद्ध है। विविध सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन, गैर राजनीतिक लोग भी तिब्बत पर आवाज उठा सकते हैं।

भारत-चीन संबंध और तिब्बत की स्वायत्तता का आपस में जुड़ाव है। वर्तमान स्थिति स्थाई नहीं है। चूंकि किसी भी नए घटनाक्रम से हालत बदल सकते हैं, अतः सभी को अपना धर्म निभाना चाहिए। इससे ही वांछित बदलाव होते हैं।

(लेखक राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

हार कर भी खुशी मनाती कांग्रेस

अवधेश कुमार

कांग्रेस को भाजपा की सीटें घटने के बजाय अपनी हार का मूल्यांकन करना चाहिए

कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी। प्रेट्र

गत दिनों राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर रायबरेली से सांसद रहने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम से कांग्रेस के अंदर यह विश्वास पैदा हुआ है कि अगर राहुल गांधी ने वहां ध्यान दिया तो अगले आम चुनाव में पार्टी की स्थिति बेहतर हो सकती है और लोकसभा में अंकगणित बदल सकता है। क्या इस चुनाव परिणाम के आधार पर माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में कांग्रेस के दिन वापस लौट सकते हैं? चूंकि भाजपा की सीटें घटीं और कांग्रेस तथा कुछ विपक्षी दलों की बढ़ीं, इसलिए उनके अंदर उम्मीद पैदा हुई है कि फिर से हमारा उत्थान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस एवं विपक्ष के अन्य दल यह न भूलें कि कांग्रेस 1991 के बाद केवल 2009 में ही 200 का आंकड़ा पार कर 206 की संख्या तक पहुंची थी। इसमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त 21 सीटों का बड़ा योगदान था। कांग्रेस का यह संकट आज का नहीं है। 1989 में भी उसे सिर्फ 197 लोकसभा सीटों पर ही विजय मिली थी। 1991 में भी 232 सीटें तब मिली थीं, जब राजीव गांधी की हत्या से कांग्रेस को सहानुभूति मिली थी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वह 200 के आंकड़े से नीचे ही होती। 1996 में उसे 140, 1998 में 141, 1999 में 114 तथा 2004 में 145 सीटें मिलीं। 2009 को छोड़ दें तो 2014 में 44, 2019 में 52 और 2024 में 99 सीटें मिलीं। इस तरह पिछले 35 वर्षों में कांग्रेस ने लोकसभा में केवल दो बार 200 का आंकड़ा पार किया। 2009 में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने सपा को छोड़ कांग्रेस के लिए मतदान किया और इस कारण उसकी सीटें बढ़ीं।

2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार का गठन इस कारण हुआ, क्योंकि भाजपा को 138 सीटें मिलीं और उसके विरोधी दलों ने कांग्रेस के इर्द-गिर्द मोर्चा बना लिया। 2009 में लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा उस तरह प्रखर राजनीतिक पार्टी के रूप में चुनाव में नहीं दिखी, जिससे उसका व्यापक समर्थन वर्ग खड़ा हो सके। नरेन्द्र मोदी के आते ही 2014 में पूरी स्थिति वास्तविकता पर लौट आई। एक समय कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी। बाद में जनाधार के स्तर पर कांग्रेस ने विचार, व्यवहार एवं व्यक्तित्व यानी नीति, रणनीति और नेता के स्तर पर ऐसा जनाकर्षक परिवर्तन नहीं किया, जो फिर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम आम भारतीय को उसका प्रतिबद्ध समर्थक बना दे। राहुल गांधी 2004 से सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में उसके पहले से सक्रिय हैं। प्रियंका वाड्रा भी लगातार सक्रिय हैं। बावजूद इसके कांग्रेस प्रदेश में अपने पैरों पर आज तक खड़ी नहीं हो सकी है। प्रियंका वाड्रा के कांग्रेस महासचिव बनने तथा उत्तर प्रदेश के प्रभारी होने पर 2019 में कांग्रेस से केवल सोनिया गांधी रायबरेली से निर्वाचित हुई थीं। दक्षिण में केरल में भी भाजपा के कमजोर होने के कारण कांग्रेस नेतृत्व या फिर वाम मोर्चा वाले गठबंधन के चलते ही वहां की ज्यादातर सीटें उसे मिलती रही हैं। आंध्र में कांग्रेस नहीं है। तमिलनाडु में द्रमुक गठबंधन के कारण उसे सीटें मिलती हैं। कर्नाटक में उसकी सरकार रहते हुए भी 1999 को छोड़कर लोकसभा चुनावों में लगातार भाजपा को ज्यादा सीटें मिलती रही हैं। तेलंगाना में अवश्य वह अपना आधार कुछ हद तक प्राप्त कर पाई है। ऐसे में भले राहुल गांधी उत्तर प्रदेश और प्रियंका वाड्रा केरल चली जाएं, इससे कांग्रेस के व्यापक विस्तार की संभावना दिखाई नहीं देती है।

भाजपा की सीटें घटना उसके स्वयं के लिए गंभीर चिंता का विषय है। चूंकि इसमें बड़ी भूमिका उसके कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं और प्रतिबद्ध समर्थकों की है, जिन्होंने या तो उदासीनता बरती, या बिल्कुल काम नहीं किया या विरोध कर दिया। कांग्रेस भाजपा को ज्यादा नुकसान पहुंचाने या कमजोर करने में वहीं सफल हुई, जहां वह गठबंधन में थी। जैसे- उत्तर प्रदेश में सपा के साथ उसके गठबंधन के कारण भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी बनी। गठबंधन में भी कांग्रेस 17 सीटों पर ही लड़ पाई। महाराष्ट्र में राकांपा (शरद पवार) और शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के साथ मिलकर ही कांग्रेस भाजपा को ज्यादा क्षति पहुंचा पाई। बिहार में अगर राजद वाला गठबंधन नहीं हो तो कांग्रेस कहीं नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से मिलकर भी सातों सीटें जीतने से कांग्रेस भाजपा को नहीं रोक पाई। जहां कांग्रेस ने भाजपा से सीधा मुकाबला किया उनमें राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्यों में उसने क्षति पहुंचाई, लेकिन भाजपा वहां कांग्रेस से पीछे नहीं गई। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि ऐसे राज्य रहे, जहां सीधे संघर्ष में कांग्रेस एक सीट नहीं पा सकी और भाजपा की एकतरफा जीत हुई। बंगाल में वाम मोर्चा से गठबंधन के बावजूद कांग्रेस सफल नहीं हुई। उसके नेता अधीर रंजन चौधरी तक हार गए। ओडिशा में लोकसभा एवं विधानसभा दोनों में वह हाशिये की पार्टी बनी रही। जबकि केरल में भाजपा इस बार एक सीट जीती है तो दो पर दूसरे स्थान में रही है। अगले चुनाव में अगर उसने अपना जनाधार थोड़ा बढ़ाया तो संभव है वहां भी कुछ सीटों का समीकरण बदले। इसी तरह तमिलनाडु में सीटें न जीतते हुए भी भाजपा ने अपना वोट बढ़ाया है।

आम चुनाव परिणाम के इन तथ्यों को ध्यान में रखें तो यथार्थ में कांग्रेस के लिए वैसी उत्साहजनक तस्वीर नहीं नजर आएगी, जैसी दिखाने की कोशिश हो रही है। लगता है कांग्रेस भाजपा की सीटें घटने को ही अपनी बड़ी सफलता मानकर आनंदित हो रही है और इस उत्साह में अपना सही मूल्यांकन नहीं कर पा रही है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन जीने का ढंग

यदि कोई व्यक्ति कलात्मक ढंग से जीता है तो उसका जीवन बहुत सार्थक और सफल बन जाता है। यदि वह जीवन जीने की कला को नहीं जानता तो उसका जीवन नीरस, बोझिल और निरर्थक हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है जीवन में सकारात्मक सोच रखना। जीवन के प्रति हर क्षण जागरूक होना। याद रखें कि दुनिया में सिर्फ दो ही व्यक्ति संपूर्ण हैं। एक मर चुका है, दूसरा अभी पैदा नहीं हुआ है। प्रसिद्धि एवं धन उस समुद्री जल के समान हैं, जितना ज्यादा हम पीते हैं, उतना ही प्यासे होते जाते हैं। जीवन में जितनी अपेक्षाएं बढ़ती हैं, उतने ही दुख भी बढ़ जाते हैं।

हम सब जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कुछ ऐसा, जिससे अलग पहचान बन सके। यह चाहते सब हैं, पर कामयाब बहुत कम ही हो पाते हैं। कारण कि हम खुद को पूरी तरह अपने काम में डुबो नहीं पाते। हम यह नहीं जानते कि हम क्या बन सकते हैं। कुछ बड़ा करने के लिए जरूरी है कि हम ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। इसके लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान होना बेहद जरूरी है। जीवन में अच्छा या बुरा, सब कुछ घटित होता रहता है। मूल बात है कि आप क्या सोच रहे हैं? अपने सोच के अलावा किसी और चीज पर हमारा काबू भी नहीं होता। हमारे ज्यादातर दुख हमारी अपनी उम्मीदों से पैदा होते हैं। इनमें से भी कई जमीन से न जुड़कर ख्याली होती हैं। इसी कारण एक बार असफल होने पर हम दोबारा कोशिश नहीं करते। वर्तमान जीवनशैली के चलते हमारे जीवन में भागदौड़, अनचाही प्रतिस्पर्धा, हड़बड़ी आदि कई ऐसे नकारात्मक तत्व समा गए हैं, जो जीवन को कठिन बना रहे हैं। शरीर स्वस्थ रहे, यह जीवन का पहला लक्ष्य है। दूसरा है मन स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। तीसरा है भावनाएं स्वस्थ रहें, निर्मल रहें। निषेधात्मक विचार न आएं, मैत्री और करुणा का विकास होता रहे। ये सब जीवनरूपी उद्यान को हरा-भरा बनाने के लिए जरूरी हैं।

ललित गर्ग

भारत का पहला 'साहित्य शहर'

देवेंद्रराज सुथार

साहित्य समाज के लिए एक दर्पण के रूप में कार्य करता है, जो इसके मूल्यों, संघर्षों और आकांक्षाओं को दर्शाता है

हाल में उत्तरी केरल में स्थित कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर भारत का पहला 'साहित्य शहर' (सिटी आफ लिटरेचर) घोषित किया गया है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में कालीकट के नाम से मशहूर कोझिकोड को साहित्य के शहर के रूप में मान्यता मिलना न केवल इसकी ऐतिहासिक विरासत का, बल्कि इसके मजबूत साहित्यिक बुनियादी ढांचे और पहलों का भी प्रमाण है। शहर में 500 से अधिक पुस्तकालय और 70 प्रकाशन गृह हैं, जो सालाना 400 से 500 किताबें प्रकाशित करते हैं। ये संस्थान शहर के निवासियों के बीच साहित्य और ज्ञान के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुस्तकालयों और प्रकाशन गृहों के इतने विशाल नेटवर्क की मौजूदगी यह सुनिश्चित करती है कि साहित्यिक संसाधन व्यापक पाठकों तक पहुंचें, जिससे पढ़ने और लिखने की संस्कृति को बढ़ावा मिले।

कोझिकोड के साहित्यिक परिदृश्य की जीवंतता इसके सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों द्वारा भी उजागर होती है। शहर में कई पुस्तक मेले, साहित्यिक उत्सव और लेखक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जो साहित्य के प्रति उत्साही लोगों के लिए लेखकों और उनके कार्यों से जुड़ने के लिए मंच प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम बौद्धिक आदान-प्रदान और रचनात्मकता प्रोत्साहित कर पाठकों और लेखकों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हैं। ऐसे कार्यक्रम न केवल साहित्य के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं, बल्कि शहर के सांस्कृतिक पर्यटन में भी योगदान देते हैं। ये कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं कि साहित्य सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए सुलभ हो, समावेशिता और सांस्कृतिक भागीदारी को बढ़ावा दे। साहित्यिक गतिविधियों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी मौखिक परंपराओं और लोककथाओं को संरक्षित करने में भी मदद करती है।

साहित्य समाज के लिए एक दर्पण के रूप में कार्य करता है, जो इसके मूल्यों, संघर्षों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। साहित्य जीवन को समृद्ध बनाता है, दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है और सहानुभूति पैदा करता है। साहित्य एक अधिक समावेशी और समझदार समाज का मार्ग प्रशस्त करता है। किसी भी समाज की सांस्कृतिक और बौद्धिक समृद्धि के लिए साहित्य के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। कोझिकोड का साहित्य के प्रति अपार प्रेम देश और दुनिया के लिए एक मिसाल है। हर शहर और गांव को साहित्य के प्रति ऐसा ही जुनून पैदा करना चाहिए, ताकि पढ़ने की संस्कृति विकसित हो सके। इसके लिए पुस्तकालयों की स्थापना, पुस्तक मेले का आयोजन और स्थानीय लेखकों को समर्थन देना महत्वपूर्ण है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

आपातकाल पर अपना सोच बदले कांग्रेस

'आपातकाल और कांग्रेस' शीर्षक से युक्त संपादकीय में आपातकाल की 50वीं बरसी पर देश की संसद में लाए गए निंदा प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसदों के विरोध को लेकर नेता विपक्षी दल राहुल गांधी को जो नसीहत दी गई है, वह कांग्रेस के लिए गौरतलब है। वस्तुतः आपातकाल के संदर्भ में कांग्रेस को अब अपना सोच बदल लेना चाहिए। राहुल गांधी अपनी दादी द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल को भुला देने की बात करते हैं, जबकि देश के भावी नेताओं को इसे हमेशा याद रखने की जरूरत है ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। लोकसभा में नेता विपक्षी दल का महत्वपूर्ण दायित्व संभालने वाले राहुल गांधी को भी अब आपातकाल को लेकर अपने सोच स्पष्ट कर देने चाहिए ताकि लोकसभा मंडप की अग्रिम पंक्ति में राहुल के साथ बैठने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव को असमंजस की स्थिति का सामना न करना पड़े। इस संदर्भ में यह स्मरणीय है कि 1975 के आपातकाल में समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव को भी जेल में बंद कर दिया गया था। इन्हीं मुलायम सिंह यादव ने उप्र में सपा की सरकार बनने पर आपातकाल के दौरान जेल में निरुद्ध किए गए लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन देकर सम्मानित किया था। ऐसे में उनके पुत्र अखिलेश यादव आज भले ही कांग्रेस के बगलगीर हों, लेकिन वह आपातकाल को कभी सही नहीं ठहरा सकते। संसद में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी को इसे समझने की जरूरत है। कांग्रेस पिछले 50 वर्षों से भले ही संविधान को कुचलने वाले आपातकाल को सही ठहराने की हिमाकत करती रही हो, लेकिन अब उसे सुधर जाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से 1975 के आपातकाल को संविधान विरोधी बताकर इसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूल के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक राहुल गांधी का संविधान बचाने वाला शिगूफा अर्थहीन ही रहेगा।

pandeyvp1960@gmail.com

मेलबाक्स

जनता को भ्रष्टाचार नहीं पसंद

आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार और राजनीतिक शुचिता की बात की थी। पार्टी द्वारा देश के बड़े-बड़े एवं वरिष्ठतम नेताओं पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए गए, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य कितना हास्यास्पद है कि केजरीवाल द्वारा आरोपित लगभग सभी नेता बाहर हैं और वह स्वयं शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं। देश में सबसे विचित्र राजनीतिक स्थिति तब उत्पन्न हुई जब आम आदमी पार्टी ने आइएनडीआइए में शामिल होकर स्वयं द्वारा निर्धारित आरोपितों से हाथ मिला लिया। क्या ऐसी ओछी राजनीति सुविधा और सत्तालोलुपता की राजनीति नहीं कहलाएगी? कितना दुखद है कि देश की राजधानी दिल्ली में वह भी मुख्यमंत्री आवास में आम आदमी पार्टी की वर्तमान राज्यसभा सांसद और पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल द्वारा मुख्यमंत्री के पीएस पर पिटाई के आरोप लगाए गए। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता द्वारा कांग्रेस एवं आप के गठबंधन को एक भी सीट न देना निश्चित ही लोगों के आक्रोश को दर्शाता है।

दीपक गौतम, सोनीपत

युवाओं के हाथ में भारतीय राजनीति

इस चुनाव में भारतीय राजनीति में नए पंक्ति के नेता उभरे, जिनमें अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। ये आगे चलकर भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। ये अपने व्यक्तित्व और प्रभावशाली नेतृत्व के बल पर देश के अंदर प्रभावशाली लीडर के रूप में उभरकर सामने आए हैं। जिस तरह इन्होंने अपने-अपने दलों की बागडोर संभाली और पार्टी को एक मुकाम तक पहुंचाया, इसमें इनकी राजनीतिक परिपक्वता साफ तौर पर झलकती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक युवाओं का देश है। ऐसे में भारतीय राजनीति में इस तरह के युवा प्रभावशाली नेताओं का आना भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत कहा जा सकता है।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,

डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा

ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*

दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

संपादकीय जागरण

10 शुक्रवार, 28 जून, 2024: आषाढ़ कृष्ण-7 वि. 2081

हर इंसान इस पृथ्वी पर ईश्वर का मेहमान है

अनावश्यक आपत्ति

नई लोकसभा के गठन के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा, उससे मोदी सरकार के एजेंडे की ही झलक मिली। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि ऐसे अवसरों पर राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की रूपरेखा को ही रेखांकित करता है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हों, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण से यही स्पष्ट होता है कि यह सरकार पहले की तरह ही कार्य करेगी और उन कामों को पूरा करने पर विशेष ध्यान देगी, जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री पिछले कुछ समय से लगातार करते आ रहे हैं। इस सबके बाद भी वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि अपने तीसरे कार्यकाल में उन्हें संसद के भीतर और बाहर विपक्ष के तीखे तेवरों का सामना करना पड़ेगा। इसका एक बड़ा कारण उसके संख्याबल में वृद्धि होना है। संख्याबल में वृद्धि के चलते विपक्ष को जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल हुआ है, वहीं दूसरी ओर उसका मनोबल भी बढ़ा है। बीते तीन-चार दिनों में संसद में जो कुछ हुआ, उससे विपक्ष के बढ़े हुए मनोबल का ही पता चलता है। विपक्ष का उत्साहित होना स्वाभाविक है, लेकिन उचित यह होगा कि वह विरोध के लिए विरोध वाले रवैये का परित्याग करे। इसके स्थान पर उसे रचनात्मक विरोध का परिचय देना चाहिए। दुर्भाग्य से फिलहाल इसके आसार कम ही हैं और इसका संकेत राष्ट्रपति के अभिभाषण के कुछ बिंदुओं पर विपक्षी नेताओं की अनावश्यक आपत्ति से मिलता है। यह कोई नई-अनोखी या गोपनीय बात नहीं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की ओर से तैयार किया जाता है। आखिर ऐसे में यह कहने का क्या मतलब कि उनका अभिभाषण तो सरकारी भाषण है। ऐसा तो होता ही है। यह आश्चर्यजनक है कि विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के उन बिंदुओं पर भी हंगामा किया, जिनका कोई औचित्य नहीं था। जब राष्ट्रपति ने प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की समस्या पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ठोस उपाय करने की जरूरत जताई तो विपक्ष को यह रास नहीं आया। क्या यह एक तथ्य नहीं कि बीते पांच वर्षों में केंद्रीय स्तर के साथ ही राज्य स्तर की भी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए हैं? विपक्ष तब भी आपे से बाहर होता हुआ दिखा, जब राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आपातकाल के काले कारनामों को याद किया। आखिर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस आपातकाल के जिक्र मात्र से क्यों भड़क जा रही है? कांग्रेस नेता आपातकाल का उल्लेख भर किए जाने से जिस तरह बिदक रहे हैं, उससे तो वे यही साबित कर रहे हैं कि आपातकाल का स्मरण किया जाना क्यों आवश्यक है। यह हैरानी ही नहीं, चिंता का भी विषय है कि कांग्रेस को आपातकाल के स्मरण पर भी आपत्ति है। बेहतर होगा कि सरकार का विरोध करते समय विपक्ष तनिक तार्किक रवैया अपनाए।

सुधार की कोशिश

राज्य की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए प्रदेश सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। हाल के दिनों में इसे लेकर कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए। कुछ निर्देशों पर एतराज भी जताया गया, किंतु अंततः इसके अच्छे परिणाम सामने आए। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति में खासी वृद्धि हुई। सुधार के क्रम में ही विभाग ने शिक्षकों के लिए ई-शिक्षा कोष मोबाइल एप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था की है। हालांकि, पहले दिन मंगलवार को इस एप के माध्यम से सरकारी स्कूलों के करीब पांच लाख शिक्षकों में महज अस्सी हजार ही हाजिरी बना सके। एप पर कम संख्या में उपस्थिति दर्ज होने का कारण पहले दिन कई जिलों में सर्वर का डाउन होना बताया गया। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की आनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को टैब उपलब्ध कराने की योजना है। वहीं, पहली जुलाई से स्कूलों के लिए नई समय-सारिणी जारी की गई है। जिसके तहत हरेक तरह की गतिविधि के लिए समय निर्धारित किए गए हैं। शिक्षकों को भी प्रतिदिन कम से कम साढ़े सात घंटे पढ़ाना होगा, साथ ही छात्र-छात्राओं के उन्नयन की दिशा में लगातार प्रयासरत रहना होगा। दरअसल, सरकार रियल टाइम मानीटरिंग का प्रयास कर रही है, जिसमें सबका सहयोग जरूरी है। विद्यार्थियों, अभिभावकों व शिक्षकों को भी यह सोचना होगा कि सरकार द्वारा शिक्षा मद में भारी-भरकम खर्च किए जाने के बावजूद शिक्षा व्यवस्था व गुणवत्ता में सुधार क्यों नहीं हो रहा। यह एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, जिसे सभी की भागीदारी के बिना निभाया नहीं जा सकता है।

सरकार की मंशा साफ है कि विद्यार्थी को हर हाल में पढ़ना होगा तथा शिक्षक को स्कूल आकर पढ़ाना ही होगा।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या राहुल गांधी के नेता-प्रतिपक्ष बनने का फैसला सही है?

आज का सवाल

क्या लोकसभा में आपातकाल पर लाए गए प्रस्ताव पर कांग्रेस की आपत्ति जायज है?

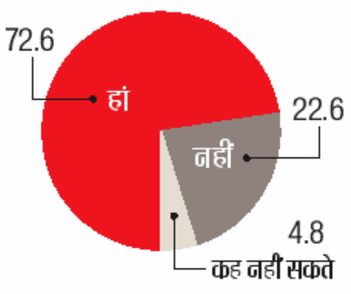

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

तिब्बत की आवाज बने भारत

शंकर शरण

जिस मुद्दे पर भारत ने चीन से धोखा खाया, उसे यानी तिब्बत को उठाकर ही सही मार्ग पाया जा सकता है

अमेरिकी सांसदों का एक दल जिस तरह दलाई लामा से धर्मशाला आकर मिला, वह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दल के सांसदों में नैंसी पेलोसी भी थीं, जिन्होंने अमेरिकी संसद में 'रिसाल्व तिब्बत एक्ट' का विधेयक रखा है। इसमें तिब्बत समस्या के समाधान के लिए चीन पर दबाव डालने की सिफारिश है। इस विधेयक पर अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने से चीन पर तिब्बतियों से बातचीत करने का दबाव बनाने की अमेरिकी गंभीरता झलकेगी। इसका प्रभाव दुनिया के अनेक देशों पर भी पड़ सकेगा। इन देशों में सबसे महत्वपूर्ण भारत है। उल्लेखनीय केवल यह नहीं कि भारत ने अमेरिकी सांसदों के दल को धर्मशाला आकर दलाई लामा से मुलाकात करने की अनुमति दी, बल्कि इस दल से प्रधानमंत्री मोदी ने भी भेंट की। डोकलाम और गलवन घाटी पर भारत-चीन तनाव के संदर्भ में भी इसका संकेत स्पष्ट है। यदि भारत भी कूटनीति में चीन की तरह यथार्थवादी कदम उठाए तो आपसी संबंध सुधार की संभावना बढ़ेगी। केवल सदिच्छा और सांकेतिक बातों से भारत को आज तक कुछ लाभ नहीं हुआ। वस्तुतः तिब्बत ही भारत-चीन संबंधों की बीच की कड़ी है। इसकी अनदेखी से आपसी विश्वास नहीं बन सकेगा।

यहां स्मरणीय है कि बीजिंग में 1954 में हुआ पंचशील समझौता भारत-तिब्बत पर ही था। इस समझौते का शीर्षक ही है: ''चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और संबंध के बारे में।'' छह अनुच्छेदों के इस संक्षिप्त समझौते में कुल नौ बार तिब्बत का नाम आया है। इसमें से पांच अनुच्छेदों में केवल इसके वर्णन हैं कि भारत-तिब्बत संबंध पूर्ववत चलते रहेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से सौ-पचास साल कुछ नहीं होते। 1951 तक तिब्बत स्वतंत्र देश था। मार्च 1947 में दिल्ली में 'एशियन रिलेशंस कांफ्रेंस' में तिब्बत और चीन, दोनों ने स्वतंत्र देशों की तरह हिस्सा लिया था। इससे पहले 1914 में शिमला में चीन, तिब्बत और भारत ने आपसी सीमांकन समझौता भी किया था। यदि चीन 1890 के दस्तावेज का हवाला देकर डोकलाम को अपना बताता है, तो 1914 के दस्तावेज के अनुसार तिब्बत भी स्वतंत्र देश है। ऐसे तथ्य उठाकर ही भारत, चीन और तिब्बत, तीनों के बीच पहले की तरह परस्परता का संबंध बनने का मार्ग मिल सकता है। यह ठीक है कि 1949 में भारत से भूल हुई जब उसने चीनी कम्युनिस्टों को तिब्बत हड़पने दिया। उसके एवज में चीन ने भारत और तिब्बत को संतुष्ट करने के लिए पंचशील का उपाय किया। उस समझौते का सार यही था कि तिब्बत और भारत के सांस्कृतिक, व्यापारिक, सामाजिक संबंध पहले जैसे चलते रहेंगे-बिना किसी पासपोर्ट, वीजा या परमिट आदि के।

अवधेश राजपूत

यह ऐतिहासिक सत्य है कि भारत और तिब्बत के संबंध सदियों से खुले और पारस्परिक थे, जिसमें चीन का कोई अवरोध न था। जब चीनी नेता पंचशील समझौते का हवाला देते हैं, तो भारतीय नेताओं को कहना चाहिए कि उसके अनुच्छेद दो और पांच के अनुरूप तिब्बती एवं भारतीय तीर्थयात्रियों की बेरोक-टोक यात्राएं पुनर्स्थापित की जाएं। वस्तुतः न्याय और व्यावहारिकता, दोनों का तकाजा है कि पंचशील समझौते के सभी छह अनुच्छेद लागू किए जाएं, अन्यथा तिब्बत और उसकी सहायता के लिए भारत समेत दुनिया के अन्य उदार देश उसी तरह स्वतंत्र हैं, जैसे अन्य देश किसी पीड़ित देश की मदद के लिए होते हैं। निर्मल वर्मा ने तिब्बत को 'संसार का अंतिम उपनिवेश' बताया था। भारत और तिब्बत को अपनी साझी चिंताओं और सांस्कृतिक जरूरतों पर बोलने का पूरा अधिकार है। यही पूरे मामले को सुलझाने का सूत्र है, पर अधिकांश नेता और बुद्धिजीवी 'तिब्बत रीजन आफ चाइना' की शब्दावली में सदैव चाइना पकड़ते हैं और तिब्बत भूल जाते हैं! वास्तव में होना उलटा चाहिए। सदैव तिब्बत का नाम लें और चीन को टोकें। भारत का पड़ोसी पहले तिब्बत है। उसके पार चीन है। पंचशील समझौता होने पर कई पत्र-पत्रिकाओं में खबर का शीर्षक था-भारत-तिब्बत समझौता। इसके दो-तीन दशक बाद भी दुनिया भर के नक्शों में तिब्बत अलग देश ही रहा। दुर्भाग्यवश भारतीय बुद्धिजीवी और नेता कई गंभीर चीजों का नाम लेते हैं, पर उसके अर्थ पर ध्यान नहीं देते, जबकि चीन यथार्थवादी होने के कारण तिब्बत और भारत दोनों के अधिकार से अवगत है। इसीलिए वह दलाई लामा पर सावधान रहता है। उनसे देसी-विदेशी नेताओं के मिलने-जुलने का विरोध करता है, जबकि भारत अपने कर्तव्य से चूक जाता है। यह विचित्र है कि जिस तिब्बत को लेकर भारत का समझौता बीजिंग से हुआ था, उस तिब्बत की बात भारत ही नहीं करता।

चीन द्वारा तिब्बत पर हमले के बाद संपूर्ण विश्व ने पहले भारत की ओर ही देखा था, क्योंकि उससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश भारत था। भारत द्वारा चीन का समर्थन करते रहने से ही दुनिया चुप रही। वरना तब तक कम्युनिस्ट चीन महाशक्ति क्या, मान्यता प्राप्त देश तक नहीं था! संयुक्त राष्ट्र में भी 1971 तक फारमोसा (ताइवान) को मान्यता थी। अमेरिका ने 1978 तक कम्युनिस्ट चीन से कूटनीतिक संबंध तक नहीं बनाए थे। यदि तिब्बत पर भारत आवाज उठाता, तो चीन मनमानी नहीं कर सकता था। वह भूल सुधारना भारत का अनिवार्य कर्तव्य है। उस पर चुप्पी रखने से भारत की हानि होती है। यदि भारत ने सहजता से तिब्बत का मुद्दा उठाया होता, तो चीन को भारत के साथ सद्भाव बनाने की चिंता होती। तिब्बत की स्थिति भी सुधरती। जिस मुद्दे पर भारत ने धोखा खाया, उसी को उठाकर यानी तिब्बत से अपने संबंध को महत्व देकर ही सही मार्ग पाया जा सकता है। अभी तिब्बत असहाय लगता है, पर यदि भारत ने इसे विश्व-मंच पर उठा दिया, तो ऐसा नहीं रहेगा। चीनी सत्ता ने अपने देश में तानाशाही को औजार बनाया है, तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता भारत का साधन बन सकता है। तिब्बतियों को वैचारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अभियान चलाने में सहायता देना भारत के हाथ में है। ऐसा न करना स्वयं भारत की नैतिक प्रतिज्ञा के विरुद्ध है। विविध सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन, गैर राजनीतिक लोग भी तिब्बत पर आवाज उठा सकते हैं।

भारत-चीन संबंध और तिब्बत की स्वायत्तता का आपस में जुड़ाव है। वर्तमान स्थिति स्थाई नहीं है। चूंकि किसी भी नए घटनाक्रम से हालत बदल सकते हैं, अतः सभी को अपना धर्म निभाना चाहिए। इससे ही वांछित बदलाव होते हैं।

(लेखक राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

हार कर भी खुशी मनाती कांग्रेस

अवधेश कुमार

कांग्रेस को भाजपा की सीटें घटने पर आनंदित होने के बजाय अपनी हार का मूल्यांकन करना चाहिए

गत दिनों राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर रायबरेली से सांसद रहने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम से कांग्रेस के अंदर यह विश्वास पैदा हुआ है कि अगर राहुल गांधी ने वहां ध्यान दिया तो अगले आम चुनाव में पार्टी की स्थिति बेहतर हो सकती है और लोकसभा में अंकगणित बदल सकता है। क्या इस चुनाव परिणाम के आधार पर माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में कांग्रेस के दिन वापस लौट सकते हैं? चूंकि भाजपा की सीटें घटीं और कांग्रेस तथा कुछ विपक्षी दलों की बढ़ीं, इसलिए उनके अंदर उम्मीद पैदा हुई है कि फिर से हमारा उत्थान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस एवं विपक्ष के अन्य दल यह न भूलें कि कांग्रेस 1991 के बाद केवल 2009 में ही 200 का आंकड़ा पार कर 206 की संख्या तक पहुंची थी। इसमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त 21 सीटों का बड़ा योगदान था। कांग्रेस का यह संकट आज का नहीं है। 1989 में भी उसे सिर्फ 197 लोकसभा सीटों पर ही विजय मिली थी। 1991 में भी 232 सीटें तब मिली थीं, जब राजीव गांधी की हत्या से कांग्रेस को सहानुभूति मिली थी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वह 200 के आंकड़े से नीचे ही होती। 1996 में उसे 140, 1998 में 141, 1999 में 114 तथा 2004 में 145 सीटें मिलीं। 2009 को छोड़ दें तो 2014 में 44, 2019 में 52 और 2024 में 99 सीटें मिलीं। इस तरह पिछले 35 वर्षों में कांग्रेस ने लोकसभा में केवल दो बार 200 का आंकड़ा पार किया। 2009 में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने सपा को छोड़ कांग्रेस के लिए मतदान किया और इस कारण उसकी सीटें बढ़ीं।

2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार का गठन इस कारण हुआ, क्योंकि भाजपा को 138 सीटें मिलीं और उसके विरोधी दलों ने कांग्रेस के इर्द-गिर्द मोर्चा बना लिया। 2009 में लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा उस तरह प्रखर राजनीतिक पार्टी के रूप में चुनाव में नहीं दिखी, जिससे उसका व्यापक समर्थन वर्ग खड़ा हो सके। नरेन्द्र मोदी के आते ही 2014 में पूरी स्थिति वास्तविकता पर लौट आई। एक समय कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी। बाद में जनाधार के स्तर पर कांग्रेस ने विचार, व्यवहार एवं व्यक्तित्व यानी नीति, रणनीति और नेता के स्तर पर ऐसा जनाकर्षक परिवर्तन नहीं किया, जो फिर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम आम भारतीय को उसका प्रतिबद्ध समर्थक बना दे। राहुल गांधी 2004 से सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में उसके पहले से सक्रिय हैं। प्रियंका वाड्रा भी लगातार सक्रिय हैं। बावजूद इसके कांग्रेस प्रदेश में अपने पैरों पर आज तक खड़ी नहीं हो सकी है। प्रियंका वाड्रा के कांग्रेस महासचिव बनने तथा उत्तर प्रदेश के प्रभारी होने पर 2019 में कांग्रेस से केवल सोनिया गांधी रायबरेली से निर्वाचित हुई थीं। दक्षिण में केरल में भी भाजपा के कमजोर होने के कारण कांग्रेस नेतृत्व या फिर वाम मोर्चा वाले गठबंधन के चलते ही वहां की ज्यादातर सीटें उसे मिलती रही हैं। आंध्र में कांग्रेस नहीं है। तमिलनाडु में द्रमुक गठबंधन के कारण उसे सीटें मिलती हैं। कर्नाटक में उसकी सरकार रहते हुए भी 1999 को छोड़कर लोकसभा चुनावों में लगातार भाजपा को ज्यादा सीटें मिलती रही हैं। तेलंगाना में अवश्य वह अपना आधार कुछ हद तक प्राप्त कर पाई है। ऐसे में भले राहुल गांधी उत्तर प्रदेश और प्रियंका वाड्रा केरल चली जाएं, इससे कांग्रेस के व्यापक विस्तार की संभावना दिखाई नहीं देती है।

कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी ● पीटीआई

भाजपा की सीटें घटना उसके स्वयं के लिए गंभीर चिंता का विषय है। चूंकि इसमें बड़ी भूमिका उसके कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं और प्रतिबद्ध समर्थकों की है, जिन्होंने या तो उदासीनता बरती, या बिल्कुल काम नहीं किया या विरोध कर दिया। कांग्रेस भाजपा को ज्यादा नुकसान पहुंचाने या कमजोर करने में वहीं सफल हुई, जहां वह गठबंधन में थी। जैसे-उत्तर प्रदेश में सपा के साथ उसके गठबंधन के कारण भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी बनी। गठबंधन में भी कांग्रेस 17 सीटों पर ही लड़ पाई। महाराष्ट्र में राकांपा (शरद पवार) और शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के साथ मिलकर ही कांग्रेस भाजपा को ज्यादा क्षति पहुंचा पाई। बिहार में अगर राजद वाला गठबंधन नहीं हो तो कांग्रेस कहीं नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से मिलकर भी सातों सीटें जीतने से कांग्रेस भाजपा को नहीं रोक पाई। जहां कांग्रेस ने भाजपा से सीधा मुकाबला किया उनमें राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्यों में उसने क्षति पहुंचाई, लेकिन भाजपा वहां कांग्रेस से पीछे नहीं गई। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि ऐसे राज्य रहे, जहां सीधे संघर्ष में कांग्रेस एक सीट नहीं पा सकी और भाजपा की एकतरफा जीत हुई। बंगाल में वाम मोर्चा से गठबंधन के बावजूद कांग्रेस सफल नहीं हुई। उसके नेता अधीर रंजन चौधरी तक हार गए। ओडिशा में लोकसभा एवं विधानसभा दोनों में वह हाशिये की पार्टी बनी रही। जबकि केरल में भाजपा इस बार एक सीट जीती है तो दो पर दूसरे स्थान में रही है। अगले चुनाव में अगर उसने अपना जनाधार थोड़ा बढ़ाया तो संभव है वहां भी कुछ सीटों का समीकरण बदले। इसी तरह तमिलनाडु में सीटें न जीतते हुए भी भाजपा ने अपना वोट बढ़ाया है।

आम चुनाव परिणाम के इन तथ्यों को ध्यान में रखें तो यथार्थ में कांग्रेस के लिए वैसी उत्साहजनक तस्वीर नहीं नजर आएगी, जैसी दिखाने की कोशिश हो रही है। लगता है कांग्रेस भाजपा की सीटें घटने को ही अपनी बड़ी सफलता मानकर आनंदित हो रही है और इस उत्साह में अपना सही मूल्यांकन नहीं कर पा रही है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन जीने का ढंग

यदि कोई व्यक्ति कलात्मक ढंग से जीता है तो उसका जीवन बहुत सार्थक और सफल बन जाता है। यदि वह जीवन जीने की कला को नहीं जानता तो उसका जीवन नीरस, बोझिल और निरर्थक हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है जीवन में सकारात्मक सोच रखना। जीवन के प्रति हर क्षण जागरूक होना। याद रखें कि दुनिया में सिर्फ दो ही व्यक्ति संपूर्ण हैं। एक मर चुका है, दूसरा अभी पैदा नहीं हुआ है। प्रसिद्धि एवं धन उस समुद्री जल के समान हैं, जितना ज्यादा हम पीते हैं, उतना ही प्यासे होते जाते हैं। जीवन में जितनी अपेक्षाएं बढ़ती हैं, उतने ही दुख भी बढ़ जाते हैं।

हम सब जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कुछ ऐसा, जिससे अलग पहचान बन सके। यह चाहते सब हैं, पर कामयाब बहुत कम ही हो पाते हैं। कारण कि हम खुद को पूरी तरह अपने काम में डुबो नहीं पाते। हम यह नहीं जानते कि हम क्या बन सकते हैं। कुछ बड़ा करने के लिए जरूरी है कि हम ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। इसके लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान होना बेहद जरूरी है।

जीवन में अच्छा या बुरा, सब कुछ घटित होता रहता है। मूल बात है कि आप क्या सोच रहे हैं? अपने सोच के अलावा किसी और चीज पर हमारा काबू भी नहीं होता। हमारे ज्यादातर दुख हमारी अपनी उम्मीदों से पैदा होते हैं। हम खुद से बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं। इनमें से भी कई जमीन से न जुड़कर ख्याली होती हैं। इसी कारण एक बार असफल होने पर हम दोबारा कोशिश नहीं करते। वर्तमान जीवनशैली के चलते हमारे जीवन में भागदौड़, अनचाही प्रतिस्पर्धा, हड़बड़ी आदि कई ऐसे नकारात्मक तत्व समा गए हैं, जो जीवन को कठिन बना रहे हैं। शरीर स्वस्थ रहे, यह जीवन का पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है मन स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। तीसरा लक्ष्य है भावनाएं स्वस्थ रहें, निर्मल रहें। निषेधात्मक विचार न आएं, मैत्री और करुणा का विकास होता रहे। ये सब जीवनरूपी उद्यान को हरा-भरा बनाने के लिए जरूरी हैं।

ललित गर्ग

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

आपातकाल पर अपना सोच बदले कांग्रेस

'आपातकाल और कांग्रेस' शीर्षक से युक्त संपादकीय में आपातकाल की 50वीं बरसी पर देश की संसद में लाए गए निंदा प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसदों के विरोध को लेकर नेता विपक्षी दल राहुल गांधी को जो नसीहत दी गई है, वह कांग्रेस के लिए गौरतलब है। वस्तुतः आपातकाल के संदर्भ में कांग्रेस को अब अपना सोच बदल लेना चाहिए। राहुल गांधी अपनी दादी द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल को भुला देने की बात करते हैं, जबकि देश के भावी नेताओं को इसे हमेशा याद रखने की जरूरत है ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। लोकसभा में नेता विपक्षी दल का महत्वपूर्ण दायित्व संभालने वाले राहुल गांधी को भी अब आपातकाल को लेकर अपने सोच स्पष्ट कर देने चाहिए ताकि लोकसभा मंडप की अग्रिम पंक्ति में राहुल के साथ बैठने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव को असमंजस की स्थिति का सामना न करना पड़े। इस संदर्भ में यह स्मरणीय है कि 1975 के आपातकाल में समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव को भी जेल में बंद कर दिया गया था। इन्हीं मुलायम सिंह यादव ने उग्र में सपा की सरकार बनने पर आपातकाल के दौरान जेल में निरुद्ध किए गए लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन देकर सम्मानित किया था। ऐसे में उनके पुत्र अखिलेश यादव आज भले ही कांग्रेस के बगलगीर हों, लेकिन वह आपातकाल को कभी सही नहीं ठहरा सकते। संसद में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी को इसे समझने की जरूरत है। कांग्रेस पिछले 50 वर्षों से भले ही संविधान को कुचलने वाले आपातकाल को सही ठहराने की हिमाकत करती रही हो, लेकिन अब उसे सुधर जाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से 1975 के आपातकाल को संविधान विरोधी बताकर इसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूल के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक राहुल गांधी का संविधान बचाने वाला शिगूफा अर्थहीन ही रहेगा।

pandeyvp1960@gmail.com

छात्रों के भविष्य व समाज पर गंभीर प्रभाव

नीट यूजी पेपर लीक की खबरें इन दिनों चरम पर हैं। इसका छात्रों के करियर पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ी के कारण योग्य व मेहनती छात्रों का हक मारा जाता है, जिससे उनकी मेहनत और भविष्य दोनों दांव पर लग जाते हैं। छात्रों में निराशा व हताशा बढ़ती है, कई बार वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जो लोग इस प्रकार के घोटालों में शामिल हैं, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। परीक्षा की व्यवस्था पारदर्शी बनाई जाए। यदि बिना योग्यता के चिकित्सक तैयार किए जाएंगे तो इसका व्यापक असर समाज पर पड़ेगा। यह ना केवल स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को गिराएगा, बल्कि मरीजों की जान को भी खतरे में डाल सकता है। ऐसे चिकित्सक, जिनके पास पर्याप्त ज्ञान और अनुभव नहीं होता, वे मरीजों का सही उपचार नहीं कर पाते, इससे चिकित्सा जगत में अविश्वास पैदा होता है। चिकित्सक ना केवल हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं बल्कि हमें जीवन जीने की नई आशा भी देते हैं। इसलिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि चिकित्सकों के पास उचित योग्यता और कौशल हो, ताकि वे समाज की सेवा में सक्षम हो सकें।

डा. पवन कुमार, गया

कट्टरता की राह छोड़े बांग्लादेश

हर्ष वी. पंत का आलेख द्विपक्षीय संबंधों का स्वर्णिम दौर पढ़ा। पाकिस्तान के अत्याचार से त्रस्त बांग्लादेश को भारत ने 1971 के युद्ध में स्वतंत्र कराया। प्रारंभ से ही बांग्लादेश और भारत के बीच मधुर संबंध रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना पहली विदेशी मेहमान बनकर आईं। दोनों देशों के बीच कई ऐतिहासिक समझौते हुए हैं, बांग्लादेश भारत के साथ मिलकर विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहता है। चीन के चंगुल में फंसकर श्रीलंका की बदहाली दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान भी चौतरफा संकट से घिरा हुआ है, इसलिए बांग्लादेश चीन की बजाय भारत को प्राथमिकता देता है। बांग्लादेश को अपने देश से घुसपैठ पर लगाम लगानी चाहिए। भारत की आत्मा हिंदुत्व है। भारत के कारण ही आज बांग्लादेश स्वतंत्र देश है, लेकिन वहां हिंदुओं पर घोर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश को कट्टरता छोड़कर मानवता की राह पर चलना चाहिए।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

प्रासंगिक रहेगी कबीरवाणी

जब दिलोदिमाग में जाति व धर्म की नफरत भरी हो तो शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं, वह तो मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं। कबीर ने मानव के ऐसे दोहरे चरित्र पर बहुत कुछ लिखा है। उनके सारे दोहे आचरण में सुधार के लिए हैं, उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं और रहेंगी।

प्रसिद्ध यादव, बाबूचक, पटना

पोस्ट

इसे 99 का अहंकार नहीं तो और क्या कहेंगे कि कांग्रेस ने के. सुरेश को स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाने के पहले टीएमसी से बात तक करना जरूरी नहीं समझा।

शालिनी कपूर तिवारी@ShaliniKTiwari

कुछ चीजें जो भारतीयों को गरीब बना रही हैं- सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्थिति के कारण निजी अस्पतालों में महंगा इलाज, खस्ता शिक्षा व्यवस्था के कारण बच्चों को विदेश पढ़ने भेजना और तड़क-भड़क से शादियां करना। अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

जलवायु परिवर्तन के रूप में तीसरा विश्व युद्ध पहले से ही चल रहा है, लेकिन हम इसे पहचान नहीं रहे हैं। जलवायु परिवर्तन कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं जानता। राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक या धार्मिक सीमाओं को भी नहीं पहचानता। यह एक ऐसा युद्ध है, जो हम खुद से लड़ रहे हैं। हम सभी इसकी कीमत चुका रहे हैं।

शेखर कपूर@shekharkapur

भले ही लोकसभा की सदस्यता लेते समय विभिन्न सदस्यों ने जो नारे लगाए, उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया गया हो, लेकिन डिजिटली तो वे सब लाइव हैं। क्या संसद अब ऐसे ही बाजारू ढंग से चलेगी?

जगदीश उपासने@jdupasane

जनपथ

संसद भारतवर्ष की गूंजे फिलीस्तीन,
करने 'शपथ जिहाद' हैं निकले असदुद्दीन।
निकले असदुद्दीन देख लें सेक्युलर भाई,
कैसे कट्टरपंथ ले रहा है अंगड़ाई!
ऐसे ही चुपचाप पार हो जाती है हद,
दोगे इक दिन सौंप पाक को तुम यह संसद!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 77

****

प्रवाह
महोत्सव विश्वास का 75
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

> बगैर लड़े शत्रु को अपने वश में करना ही युद्ध की सर्वोच्च कला है। - सन त्जू

लैंसेट के अध्ययन के अनुसार, करीब 50 फीसदी भारतीय शारीरिक श्रम से दूर भागने वाले हैं और अगर स्थितियां न सुधरीं, तो 2030 तक यह आंकड़ा साठ फीसदी तक पहुंचने की आशंका है। ऐसे में, समय रहते चेतना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ व सक्रिय भारत ही सही मायनों में विकसित भारत की ओर बढ़ सकता है।

ये सुस्ती क्यों

दलैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन का यह कहना कि करीब पचास फीसदी भारतीय विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सेहत के न्यूनतम मापदंडों पर खरे नहीं उतरते, स्वास्थ्य के प्रति हमारी लापरवाही को तो दर्शाता ही है, इस चिंताजनक तथ्य को भी रेखांकित करता है कि बड़ी संख्या में लोग अपनी जीवन-शैली में सुधार करने की जरूरत को नजर अंदाज कर रहे हैं। यह चिंताजनक इसलिए भी है कि आंकड़े और भी बदतर होती स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। वर्ष 2000 में देश में 22 फीसदी वयस्क शारीरिक रूप से पर्याप्त सक्रिय नहीं थे, तो 2010 में यह आंकड़ा 34 फीसदी और अब तो यह करीब 50 फीसदी तक पहुंच गया है। महिलाओं (57 फीसदी) की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है, जो पुरुषों (42 फीसदी) की तुलना में ज्यादा निष्क्रिय हैं। इसकी वजह दरअसल यह है कि ज्यादातर महिलाएं घरेलू काम को शारीरिक व्यायाम का विकल्प मानती हैं, जो आंशिक तौर पर ही सच है। फिर उनके समक्ष सांस्कृतिक बाधाएं भी होती हैं। ज्यादातर घरेलू महिलाएं घर की देखभाल के कामों में इस कदर डूब जाती हैं कि वे अपनी ही प्राथमिकता में खुद को पीछे धकेल देती हैं। रिपोर्ट का यह कहना भी चिंताजनक है कि भारतीय महिलाएं पड़ोसी देशों बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से भी बदतर स्थिति में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अगर कोई वयस्क प्रति सप्ताह 150 मिनट की मध्यम तीव्रता की या 75 मिनट की ज्यादा तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि नहीं करता, तो उसे निष्क्रिय माना जाएगा। बावजूद इसके कि भारतीयों में आनुवंशिक रूप से दूसरों की तुलना में हृदय रोग व मधुमेह जैसी गैर-संचारी बीमारियों के कम से कम एक दशक पहले विकसित होने का खतरा ज्यादा होता है, अगर देश के वयस्क शारीरिक गतिविधियों में भी कमी ला रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि वे अपने लिए ही जोखिम बढ़ा रहे हैं। दरअसल, भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में बढ़ते शहरीकरण ने उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है, जिससे एक

आरामदायक जीवन-शैली पैदा हुई है। यही वजह है, जैसा रिपोर्ट से भी पता चलता है, कि दुनिया के 195 देशों में से भारत अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि के मामले में 12वें स्थान पर पहुंच गया है और अगर चीजें नहीं सुधरीं, तो 2030 तक पर्याप्त शारीरिक श्रम न करने की वजह से देश की साठ फीसदी आबादी पर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा होगा। ऐसे में, यह बेहद जरूरी है कि लैंसेट के निष्कर्षों में निहित संदेश को पूरी गंभीरता से समझते हुए अपनी जीवन-शैली में सुधार किया जाए, क्योंकि स्वस्थ व सक्रिय भारत ही सच्चे अर्थों में प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन की दिशा में बढ़ सकता है।

बीजिंग की बौखलाहट

विशेषज्ञों का कहना है कि तिब्बत के बारे में भारत और अमेरिका के विचार एक जैसे हैं और दोनों का रुख एक समान है, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। अमेरिका और भारत अपने समन्वित कूटनीतिक कार्यों से चीन का मुकाबला करने के लिए अधिक मुखर और सहयोगी दृष्टिकोण का मंच तैयार कर रहे हैं।

अमेरिका और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों की पृष्ठभूमि में तथा अमेरिकी संसद द्वारा पारित रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को, जो तिब्बती लोगों को पूर्ण समर्थन देने का वादा करता है, अपनाने के बाद अमेरिकी संसद का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में भारत के धर्मशाला में दलाई लामा से मिला, जिससे चीन बुरी तरह भड़क गया। रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइकल मैककॉल के नेतृत्व में सात सदस्यीय उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने रिजॉल्व तिब्बत ऐक्ट के महत्व पर चर्चा की, जिसे राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जो तिब्बती लोगों के अधिकारों के प्रबल पैरोकार हैं।

इसी से संबंधित घटनाक्रम में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी और देश में हुए लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता, पारदर्शिता और व्यापकता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपना संदेश पोस्ट करते हुए लिखा कि 'प्रतिनिधिमंडल में शामिल अमेरिकी संसद के मित्रों के साथ विचारों का बहुत अच्छा आदान-प्रदान हुआ।' उन्होंने आगे कहा कि वह 'भारत-अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में मजबूत द्विदलीय समर्थन' को 'गहराई से' महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट में दलाई लामा के साथ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की बैठक का उल्लेख नहीं है। रणनीतिक दृष्टि से इसे गुप्त रखा गया है। निर्वासित तिब्बती सरकार की मेजबानी करने वाले भारत का तिब्बत के साथ एक अनूठा संबंध है।

के एस तोमर
राजनीतिक विश्लेषक

भारत सरकार अक्सर तिब्बती मुद्दे के प्रति अपने समर्थन और चीन के साथ व्यापक रणनीतिक व आर्थिक संबंधों के बीच संतुलन बनाते हुए कदम उठाती रही है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की धर्मशाला यात्रा के तुरंत बाद इस बैठक का समय चीन की आक्रामक नीतियों का मुकाबला करने में साझा मूल्यों और आपसी हितों को रेखांकित करने के लिए एक

समन्वित कूटनीतिक प्रयास का संकेत देता है। जैसी की उम्मीद थी, चीनी दूतावास की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई, जिसमें अमेरिका को गलत संदेश देने से बचने की चेतावनी दी गई। चीनी मिशन ने एक्स पर कहा, 'हम अमेरिकी पक्ष से आग्रह करते हैं कि वह दलाई समूह के चीन विरोधी अलगाववादी प्रकृति को पूरी तरह पहचाने, शिजांग मुद्दे पर अमेरिका ने चीन से जो वादा किया था, उसका सम्मान करे और दुनिया को गलत संदेश देना बंद करे।'

तिब्बती इतिहास एवं संस्कृति को कमजोर करने के लिए चीन तिब्बत को शिजांग कहता है, जिसे अक्तूबर, 1950 में उसने जबरन हड़प लिया था। दलाई लामा धर्मशाला में निर्वासित रहकर तिब्बती लोगों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। इन बैठकों पर चीनी प्रतिक्रिया संभवतः बहुआयामी होगी। कूटनीतिक मोर्चे पर बीजिंग वाशिंगटन और नई दिल्ली के समक्ष औपचारिक विरोध दर्ज कर सकता है। वह तिब्बत पर चीनी रुख को आंतरिक मामला बताते हुए उसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप की निंदा करेगा। हालांकि, व्यापक रणनीतिक निहितार्थ चीन के क्षेत्रीय कूटनीतिक दृष्टिकोण को फिर से निर्धारित करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि तिब्बत के बारे में भारत और अमेरिका के विचार एक जैसे हैं और दोनों का रुख एक समान है, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि चीन ने 1962 में भारत के साथ धोखा किया, जिसे 2020 में दोहराया गया, जब लद्दाख में टकराव हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजिंग के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए गंभीर पहल की थी, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला है।

इन बैठकों से पता चलता है कि अमेरिकी और भारतीय हितों के मेल से एशिया में एक नई भू-राजनीतिक परिदृश्य का विकास हो रहा है। दोनों देश खासकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और आक्रामक व्यवहार के प्रति समान रूप से आशंकित हैं। अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए अमेरिका और भारत चीनी महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के लिए एक नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता जता रहे हैं। बदले में चीन अपने गठजोड़ को मजबूत करने और क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने पर जोर दे सकता है। इसके तहत वह पाकिस्तान के साथ संबंधों को गहरा कर सकता है, अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ भागीदारी बढ़ा सकता है और रणनीतिक पैठ जमाने के लिए अपनी बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाओं में तेजी ला सकता है। इसके अलावा, चीन भारत के साथ विवादित सीमाओं पर अपनी सैन्य स्थिति को बढ़ा सकता है, खासकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के विवादास्पद क्षेत्रों में, ताकि अपने क्षेत्रीय दावों को पुख्ता किया जा सके।

तात्कालिक रणनीतिक गणनाओं से परे, ये बैठकें लोकतांत्रिक मूल्यों और तानाशाही शासन के बीच व्यापक वैचारिक प्रतिस्पर्धा को भी उजागर करती हैं। अहिंसक प्रतिरोध और आध्यात्मिक नेतृत्व के प्रतीक दलाई लामा उन मूल्यों के प्रतीक हैं, जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों की वैश्विक पैरोकारी करते हैं। उनके साथ जुड़कर, अमेरिका और भारत इन सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ, चीन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को बचाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तिब्बत, शिनजियांग और हांगकांग में चीनी गतिविधियों पर बढ़ती वैश्विक निगरानी बीजिंग को रक्षात्मक स्थिति में ले आई है। वैश्विक प्रभाव की लड़ाई में, सॉफ्ट पावर और नैतिक अधिकार तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। धर्मशाला और दिल्ली की बैठकें अमेरिका और भारत के सॉफ्ट पावर को बढ़ाने का काम करती हैं, जिससे उन्हें मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों का अगुआ माना जाता है।

जैसे-जैसे एशिया में भू-राजनीतिक बिसात जटिल होती जाएगी, कूटनीति और प्रतिरोध के बीच का अंतर-संबंध महत्वपूर्ण होता जाएगा। अमेरिका और भारत, अपने समन्वित कूटनीतिक कार्यों से, चीन का मुकाबला करने के लिए अधिक मुखर और सहयोगी दृष्टिकोण का मंच तैयार कर रहे हैं। इसमें न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना शामिल है, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समान विचारधारा वाले देशों के साथ व्यापक गठजोड़ को बढ़ावा देना भी शामिल है। edit@amarujala.com

जीवन धारा

सुकरात

खुशी हमेशा हमारी गतिविधियों का अंतिम लक्ष्य होती है, इसलिए यह बिना शर्त अच्छी है। खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि चीजों का उपयोग कैसे किया जाता है।

पैसा तभी अच्छा है, जब बुद्धिमानों के हाथों में हो

खुशी की कुंजी शरीर से ध्यान हटाकर आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करने में छिपी है। अनैतिक जीवन की तुलना में नैतिक जीवन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि यह खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है। खुशी सद्गुण, न्याय और मानव अस्तित्व के अंतिम अर्थ जैसी अवधारणाओं से भी जुड़ी है। खुशी हमेशा हमारी गतिविधियों का अंतिम लक्ष्य होती है, इसलिए यह बिना शर्त अच्छी है। खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि चीजों का उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पैसे का सही तरीके से उपयोग करेगा, जबकि एक अज्ञानी व्यक्ति पैसे का गलत इस्तेमाल करेगा और फिर उसका अंत पहले से भी बदतर होगा। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि पैसा अपने आप में किसी को खुश कर सकता है। पैसा केवल तभी अच्छा है, जब यह बुद्धिमान व्यक्ति के हाथों में हो। इसी तर्क को किसी भी बाहरी अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कोई भी संपत्ति, कोई भी गुण, यहां तक कि अच्छा दिखना या योग्यता।

हम सभी खुश रहना चाहते हैं, और हम चीजों के अच्छे उपयोग के कारण खुश होते हैं। इसमें ज्ञान ही वह चीज है, जो उपयोग की इस अच्छाई की समझ और सौभाग्य प्रदान करती है। इसलिए हर व्यक्ति को हर तरह से इसके लिए खुद को तैयार करना चाहिए यानी जितना संभव हो, उतना बुद्धिमान बनना। खुशी की कुंजी किसी व्यक्ति द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं में नहीं पाई जाती, बल्कि यह व्यक्ति के अपने भीतर ही मौजूद है, जो जीवन को एक दिशा देती है और ध्यान केंद्रित करती है। खुशी केवल हमारी इच्छाओं की संतुष्टि में निहित है। यह निर्धारित करने के लिए कि कौन-सी इच्छाएं संतुष्ट करने योग्य हैं? हमें अपनी आलोचनात्मक और चिंतनशील बुद्धि का उपयोग करना होगा। हमें मानव स्वभाव की समझ तक पहुंचना होगा और यह पता लगाना होगा कि मनुष्य में सबसे अच्छा क्या है, कौन-सी इच्छाएं परस्पर प्रबल होती हैं और कौन-सी हमें समग्र उद्देश्य और अच्छी तरह से काम करने की भावना प्राप्त करने से रोकती हैं। सभी लोग स्वाभाविक रूप से खुशी चाहते हैं। इसलिए हम सभी को न्यायपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। शरीर में स्वास्थ्य और आत्मा में न्याय के बीच एक समानता है। स्वास्थ्य शरीर के विभिन्न अंगों के बीच सामंजस्य के अलावा और कुछ नहीं है। इसी तरह न्याय भी एक समान प्रकार का सामंजस्य है, लेकिन यह आत्मा के विभिन्न भागों के बीच है। दूसरी ओर अन्याय आत्मा के विभिन्न भागों के बीच एक गृहयुद्ध की तरह है, जिसमें एक विद्रोह मौजूद रहता है और नियंत्रण शक्ति के रूप में तर्क को हड़प लेता है। इसके विपरीत, न्यायी आत्मा वह है, जिसमें मानसिक सामंजस्य होता है।

सदाचारी जीवन

सूत्र

न्यायी व्यक्ति पर कुछ भी फेंक दें, लेकिन वह कभी भी अपना आंतरिक संयम नहीं खोता और जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद शांति और स्थिरता बनाए रखता है। यही हमारे भीतर छिपी सच्ची खुशी है। खुशी सदाचार से भी जुड़ी है। अधार्मिक जीवन जीने की तुलना में सदाचारी जीवन जीने से कहीं ज्यादा खुशी का अनुभव होता है।

दूसरा पहलू

ब्लैक होल एक बेहद विशाल परिधि में फैली वह जगह है, जो अमूमन तब बनती है, जब किसी तारे की उम्र पूरी हो जाती है।

अगर आप ब्लैक होल में कूद जाएं

आपने टाइम मशीन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। वही टाइम मशीन, जिसके बारे में यह कल्पना की जाती है कि वह हमें अतीत या भविष्य में ले जा सकती है। ब्लैक होल दरअसल ऐसी ही एक प्राकृतिक टाइम मशीन है, जिसके माध्यम से अतीत और भविष्य की यात्रा की जा सकती है। दरअसल, ब्लैक होल एक बेहद विशाल परिधि में फैली वह जगह है, जो अमूमन तब बनती है, जब किसी तारे की उम्र पूरी हो जाती है और वह ढह जाता है। ग्रहों व तारों की तरह ब्लैक होल के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है।

भौतिक विज्ञान का एक सामान्य नियम है कि कोई वस्तु जितनी विशाल होगी, उसका गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र उतना ही शक्तिशाली होगा। इसलिए हम रॉकेट बनाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए हमें बहुत तेज यात्रा करनी होती है। विज्ञान अब तक जो सबसे तेज गति से चलने वाली चीज ढूंढ पाया है, वह प्रकाश है। लेकिन ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं पाता। अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत बताता है कि जब कोई बहुत विशाल वस्तु अंतरिक्ष में स्थित होती है, तो उसके चारों ओर की जगह उतनी ही ज्यादा खिंची या मुड़ी होती है। कोई भी विशाल ग्रह अंतरिक्ष में एक तरह की घाटी बनाता है। जब कोई भी वस्तु इनके नजदीक जाती है, तो वह घाटी में गिर जाती है। यही वजह है कि जब आप ब्लैक होल जैसी किसी विशाल वस्तु के एकदम पास आते हैं, तो उसकी ओर गिर जाते हैं। यही वजह है कि प्रकाश ब्लैक होल से बच नहीं पाता। वह बिंदु या घटना जब यह इतनी तीव्र हो जाती है कि प्रकाश भी न बच पाए, 'क्षितिज' (Horizon) कहलाता है।

सैम बरोन

अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत बताता है कि जब कोई विशाल वस्तु अंतरिक्ष में स्थित होती है, तो उसके चारों ओर की जगह उतनी ही ज्यादा खिंची या मुड़ी होती है।

ब्लैक होल पर एक साल का मतलब पृथ्वी पर अस्सी साल हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि ब्लैक होल के क्षितिज के नजदीक पहुंचने के लिए जो अंतरिक्ष यान चाहिए, वह अब तक बना नहीं है।

अंतरिक्ष की तरह समय का भी विस्तार है। विशाल वस्तु के पास रखी घड़ी, छोटी वस्तु के पास रखी घड़ी की तुलना में धीमी चलेगी। ब्लैक होल के पास रखी घड़ी पृथ्वी पर मौजूद घड़ी की तुलना में बहुत धीमी गति से चलेगी। ब्लैक होल पर एक साल का मतलब पृथ्वी पर अस्सी साल हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि ब्लैक होल के क्षितिज के नजदीक पहुंचने के लिए जो अंतरिक्ष यान चाहिए, वह अब तक बना नहीं है। दूसरी बात, क्षितिज तक पहुंचने और वहां से लौटने के लिए जरूरी है कि आपकी गति प्रकाश से तेज हो। जब आप क्षितिज से गुजरेंगे, तो आप नूडल की तरह पतले हो चुके होंगे या शायद शून्य में विचर रहे परमाणुओं की एक श्रृंखला मात्र रह जाएंगे। तो अगली बार जब नूडल्स खाइएगा, तब ब्लैक होल के बारे में जरूर सोचिएगा। - कन्वर्सेशन से

आंकड़े

तंबाकू की जकड़ में युवा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 14 से 49 वर्ष तक की उम्र के लगभग सभी धर्मों के लोग तंबाकू का सेवन करते हैं।

मुस्लिम	40.9%
बौद्ध	39.7%
हिंदू	39.1%
ईसाई	36.6%
जैन	29.7%

सिख 12.2% और अन्य धर्मों के लोग 45.8% तक तंबाकू का सेवन करते हैं। | स्रोत : NFHS-5

रत्नाकर ने जब अपने परिजनों से पूछा कि क्या तुम सब मेरे पाप के भागीदार बनोगे, तो सभी ने मना कर दिया। वह नारद जी के पास पहुंचे और रोने लगे।

नारद ने वाल्मीकि को दिया मंत्र

अंतर्यात्रा
संकलित

महर्षि वाल्मीकि का जन्म अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन डाकुओं के साथ रहने से वह लूट और हत्याएं करने लगे। उनका पूर्व का नाम रत्नाकर था। एक दिन जंगल में नारद जी जा रहे थे। रत्नाकर उनके ऊपर झपट पड़े और कहा, लाओ तुम्हारे पास क्या है? नारद जी बोले, मेरे पास तो यह वीणा है। रत्नाकर ने पूछा, इस वीणा का क्या करते हो, बजाकर दिखाओ? नारद जी ने मधुर स्वर में वीणा बजाकर भगवान के नाम का कीर्तन किया। इससे उसका दिल पसीजा। नारद ने कहा कि जीव हिंसा से बड़ा पाप लगता है।

रत्नाकर बोले-हमारा परिवार बड़ा है। उनका भरण-पोषण करना होता है। नारद ने कहा कि अपने परिवार वालों से पूछो कि क्या वे तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे। वह परिजनों के पास पहुंचे, तो सभी ने इन्कार करते हुए कहा कि हमारे लिए भोजन लाना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन तुम्हारा पाप हम अपने ऊपर नहीं ले सकते।

लौटकर वह नारद जी के पास पहुंचे और रोने लगे। नारद जी ने शांत करते हुए कहा कि तुम 'राम' नाम के मंत्र का जाप करो। तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन रत्नाकर ने कहा-भगवन! मुझसे राम नाम का जाप नहीं हो रहा है। कहा कि कुछ नहीं 'मरा-मरा' बोलो। रत्नाकर तपस्या में लग गए। धीरे-धीरे 'मरा-मरा' की जगह 'राम-राम' का जाप होने लगा। उनके ऊपर दीमकों ने वामी बना ली। इसी से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। बाद में वाल्मीकि ने *रामायण* की रचना की।

अमर उजाला — पुराने पन्नों से — 2 अप्रैल, 1953

बर्मा के मामले में नेहरू की गहरी दिलचस्पी

बर्मा के मामले में नेहरूजी की गहरी दिलचस्पी

क्या अमरीका से सीधी सहायता मिल रही है?

प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत सरकार ने राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा अमेरिका, ब्रिटेन व कई अन्य देशों की सरकारों से बर्मा (अब म्यांमार) में कूमिंगतांग (राष्ट्रवादी चीनी) सेनाओं की उपस्थिति के संबंध में बातचीत की है।

पृथ्वी में छिपी एक नई दुनिया

वैज्ञानिकों ने दक्षिण अमेरिका के अटाकामा मरुस्थल की तपती रेत के नीचे छिपे हुए जीवमंडल को उजागर किया है।

वीर सिंह | शोध

सार्वभौमिक गर्माहट, नित नए रिकॉर्ड बनाता सृष्टि का तापक्रम, और जीवन की कड़ियों को तोड़ने पर उतारू जलवायु परिवर्तन! ऐसे निराशाजनक भू-परिदृश्य में कोई सुखद समाचार मिले, तो मन हर्षित हो जाता है। पृथ्वी ग्रह, जो पूरे ब्रह्मांड में अब तक एकमात्र ज्ञात जिंदा ग्रह है, का जीवन के प्रति एक गहरा अनुराग है। जीवन के प्रति गहरी आत्मीयता संजोए और जीवन को निरंतर पोषित करती पृथ्वी का एक दिव्य दर्शन पृथ्वी पर सबसे शुष्क और जीव रहित अटाकामा रेगिस्तान के नीचे छिपे एक जीवमंडल की हाल में हुई एक खोज से हुआ है।

एक अभूतपूर्व खोज में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे विकट पर्यावरण और जीवन संभावनाओं को ठेंगा दिखाने वाली चरम पर पहुंची जलवायु वाले अटाकामा रेगिस्तान की तपती रेत के नीचे छिपे हुए जीवमंडल को उजागर किया है। अनंत

काल से जीवन से रहित माना जाने वाला अटाकामा अब नीचे की गहराइयों में पनप रहे सूक्ष्मजीवी जीवन की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला को प्रकट करता है।

अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ पेरू, बोलेविया, चिली और अर्जेंटीना के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए 1000 किलोमीटर तक विस्तार लिए हुए है। इसकी शुष्कतम जलवायु, जिसमें वस्तुतः नहीं के बराबर (मात्र 1 से 3 मिलीलीटर प्रतिवर्ष) वर्षा होती है, जो जीवन प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त नहीं है और अत्यधिक तापमान का उतार-चढ़ाव होता है, ने वैज्ञानिकों को इसकी तुलना मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली स्थितियों से करने के लिए प्रेरित किया है। इसकी दुर्गम सतह के उपरांत भी शोधकर्ताओं को लंबे समय से संदेह था कि ऊपर की कठोरता से सुरक्षित होकर निचली सतह पर जीवन बना रह सकता है।

वैज्ञानिकों के एक अंतरराष्ट्रीय समूह के नेतृत्व में हाल के अभियानों ने इन संदेहों की पुष्टि की है, क्योंकि उन्होंने रेगिस्तान की मिट्टी और चट्टानों की गहराई में खोज की है। डीएनए अनुक्रमण और समस्थानिक विश्लेषण सहित अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने इस असंभावित आवास में पनप रहे सूक्ष्मजीवों के एक विविध समुदाय की पहचान की है।

परियोजना की प्रमुख शोधकर्ता डॉ. ऐलेना रोड्रिग्ज इस खोज को 'उल्लेखनीय रहस्योद्घाटन' के रूप में वर्णित करती हैं। वह कहती हैं कि अटाकामा मरुस्थल को लंबे समय से रेत और चट्टान का एक बेजान विस्तार माना जाता रहा है, लेकिन हमारे निष्कर्ष इस धारणा को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। सतह के नीचे, जहां स्थितियां अधिक स्थिर हैं, हमने सूक्ष्मजीव जीवन के एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र का सामना किया है। खोजा गया एक नया जीवमंडल अपने भूमिगत पर्यावरण की चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ है। बैक्टीरिया, आर्किया और कवक सहित इन सूक्ष्मजीवों ने इस कठोर परिदृश्य में जीवित रहने के लिए सरल रणनीतियां विकसित की हैं। इनमें से कुछ खनिजों से भोजन करते हैं, जबकि अन्य ऊर्जा की लिए रासायनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर रहते हैं और इस प्रकार दुनिया से छिपकर अपने लिए एक अनूठा आश्रय बनाते हैं। यह अद्भुत खोज हमारे मन में जीवन के प्रति सम्मान और पवित्रता के भावों का बीजारोपण करती है।

इसके अतिरिक्त, अटाकामा मरुस्थल में खोजे गए सूक्ष्मजीव समुदाय मंगल जैसे अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना का सुराग दे सकते हैं। मंगल ग्रह की सतह से अपनी समानता के साथ अटाकामा मरुस्थल चरम वातावरण में जीवन की सीमाओं का अध्ययन करने और अलौकिक जीवन के लिए हमारी खोज को परिष्कृत करने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर सकता है।

जैस-जैसे शोधकर्ता अटाकामा मरुस्थल और पृथ्वी पर अन्य चरम वातावरणों की गहराई का पता लगाना जारी रखते हैं, वे निश्चित रूप से और भी अधिक आश्चर्यों को उजागर करेंगे। प्रत्येक नई खोज हमें जीवन की उत्पत्ति और ब्रह्मांड में इसकी क्षमता के रहस्यों को उजागर करने के समीप लाती है। अटाकामा ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर जीवन की अनंत संभावनाओं के विकास की खिड़की खोलता है।

चिंतन

अभिभाषण में सरकार का भविष्योन्मुख दृष्टिकोण

मोदी 3.0 सरकार के पहले संसद सत्र के संयुक्त सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में वो तेवर व क्लेवर नहीं दिखे, जिसकी देश को जरूरत है। संयम, संतुलन और रटे-रटाए अवधारणा का पुट अधिक दिखा। चुनावी वर्ष होने के नाते बीते छह माह के दौरान सरकार की आर्थिक व प्रशासनिक गति सुस्त रही है, कई बड़े फैसले बाट जोह रहे हैं, आर्थिक सुधार के अगले चरण की प्रतीक्षा है, महंगाई को लेकर चिंता बरकरार है, रोजगार सृजन की गति मंद है, ऐसे में अभिभाषण में नई सरकार के व्यापक रोडमैप की उम्मीद थी। इन सबके लिए शायद बजट तक प्रतीक्षा करनी पड़े। चूंकि अभिभाषण सरकार का विकास योजनाओं व भविष्य की योजनाओं का दृष्टिकोण होता है, इसलिए आशाएं अधिक थीं। यूं तो राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण में सरकार के सभी संकल्पों, दिशाओं और लक्ष्यों को समेटने का प्रयास किया है, लेकिन किसी क्रांतिकारी-परिवर्तनकारी ध्येय का जिक्र नहीं किया है। 18वीं लोकसभा के पहले संसद के चौथे दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण करीब 50 मिनट चला, जिसमें उन्होंने सरकार के लगभग हर मुद्दे पर बात की। नीट विवाद परीक्षा रद व पेपर लीक को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है, इसलिए अभिभाषण में पेपर लीक घटनाओं की जांच करने, पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने, परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने व नया कानून लागू करने की बात प्रमुखता से कही गई है। विपक्ष ने 'संविधान खतरे में है' के नैरेटिव के साथ भाजपा के खिलाफ चुनाव में कैंपेन किया था, सांसदों के शपथग्रहण के दौरान भी राहुल गांधी व अखिलेश यादव समेत अनेक विपक्षी सांसदों ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर शपथ ली है, इसके काउंटर के लिए अभिभाषण में सरकार ने कांग्रेस द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल को काला अध्याय बता कर कांग्रेस को एहसास दिलाया है कि पूर्व में कांग्रेस सरकर के दौरान ही आपातकाल के रूप में संविधान की धज्जियां उड़ी थी। एक दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद सदन में आपातकाल को लेकर निंदा प्रस्ताव पास किया गया। सरकार की रणनीतियों से तय है कि अगर कांग्रेस भाजपा को झूठे व भ्रमित नैरेटिव संविधान खतरे में बता कर घेरेगी, तो भाजपा भी कांग्रेस को आपातकाल की याद दिलाती रहेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिये नई सरकार ने अग्निवीर का जिक्र किए बिना सेना में सुधार व सेना को आत्मनिर्भर बनाने की अपी तैयारियां बताईं। जब नॉर्थ-ईस्ट में शांति के लिए सरकार के प्रयासों का जिक्र किया गया, तब विपक्ष ने मणिपुर के हालात को लेकर शोर-शराबा किया। अभिभाषण में महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों के कल्याण करने के बारे में बात हुई, चुनाव आयोग की तारीफ की गई, जीएसटी को अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मील का पत्थर बताया गया, कश्मीर में मतदान के रिकॉर्ड टूटने को घाटी का दुश्मनों को करारा जवाब कहा गया, प्राकृतिक खेती और उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त बनाने की बात कही गई, बुलेट ट्रेन, गरीबी उन्मूलन व 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत रणनीतिक 'गेटवे' बनाने का काम का जिक्र किया गया। सरकार की ओर से आगामी बजट में बड़े सुधारात्मक फैसले की उम्मीद जगाई गई है। अभिभाषण में विपक्ष को हर वक्त हंगामा को लेकर आईना भी दिखाया है कि नीतियों का विरोध और संसदीय कामकाज का विरोध अलग-अलग बातें हैं। दुष्प्रचार की चुनौती से निपटने के लिए नए रास्ते खोजने की जरूरत है। इस अभिभाषण में सरकार का विजनरी रोडमैप है, लेकिन यह और बेहतर हो सकता था। देश में पुलिस सुधार, प्रशासनिक, न्यायिक सुधार, राजनीतिक व चुनावी सुधार लंबित हैं, आर्थिक सुधार के नेक्स्ट स्टेप की जरूरत है, इन सब मुद्दों पर अभिभाषण चुप है।

मिसाल

डॉ. महेश परिमल

मिथक तोड़ती बेटियां

हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अनोखी घटना हुई। बीएसएनएल से सेवानिवृत्त हुए अनिल कुमार अपनी बेटी को उसके ससुराल से बैंड-बाजे के साथ घर लाए। उनका मानना था कि मैंने जिस तरह से बेटी को सम्मान के साथ उसके ससुराल भेजा है, तो अब उसे ससुराल से हमेशा-हमेशा के लिए अपने घर लाने के लिए भी उतना ही सम्मान दूंगा। हुआ यूं कि अनिल कुमार की बेटी उर्वी की शादी 8 साल पहले कंप्यूटर इंजीनियर के साथ हुई थी। ससुराल में उर्वी को सम्मान नहीं मिला। दहेज के कारण उसे प्रताड़ित किया जाता था। 8 साल तक बिटिया ने यह अपमान सहा। जब सहन नहीं हुआ, तो उसने माता-पिता से गुहार लगाई कि उसे अब मायके बुला लिया जाए। इससे पिता ने यह अनुकरणीय उदाहरण पेश करते हुए उसे ससम्मान घर वापसी कराई। हमारे समाज में बेटी यदि अपने ससुराल से मायके आ जाए, तो लोग उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। बेटी ने अपने ससुराल में किस तरह के ताने और प्रताड़ना सही होगी, यह जानने की कोशिश माता-पिता के अलावा और कोई नहीं करता। आखिर बेटी को भी सम्मान से जीने का हक है। उसने ससुराल की प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाकर कोई अपराध नहीं किया है। वह भी अपनी तरह से जीना चाहती है। बेटी को भी बेटे की तरह जीने का अधिकार होना चाहिए, यह बात समाज के लोग अक्सर करते हैं, पर जब उसे अमल में लाने की बात आती है, तो सभी परंपराओं की दुहाई देने लगते हैं। आजकल तलाकशुदा बेटी का जीवन बहुत ही ज्यादा दुश्वार हो गया है। वह भी अपने तरीके से जीवन जीना चाहती है। उस पर जीवन थोपा नहीं जा सकता। ससुराल में यदि उसे प्रताड़ना मिलती है, तो फिर माता-पिता के अलावा उसका कौन है? बेटी का घर आना माता-पिता के लिए दुःखों का पहाड़ टूटना ही समझा जाता है। शुरुआत में माता-पिता काफी कोशिशें करते हैं कि बेटी का घर बस जाए। बात नहीं बनने पर वे अपनी बेटी को घर बुलाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। बेटी को ससुराल में प्रताड़ना देने का रिवाज शिक्षित वर्ग में ही अधिक देखा जाता है। तलाक भी शिक्षित वर्ग में ही अधिक होते हैं। आखिर ऐसी शिक्षा का क्या महत्व, जो विवाह को स्थायित्व देने का काम न करती हो। समाज का एक वर्ग ऐसा भी है, जो विवाह के टूटने की बाट जोहता रहता है, विवाह टूटने के बाद वह उसका आनंद लेने लगता है। विवाह टूटने के मामले में आजकल के युवा एवं उसके माता-पिता अधिक जवाबदार माने जाते हैं। कई मामलों में बेटी के माता-पिता यह मानते हैं कि ससुराल में बेटी जिस तरह से रोज-रोज मर रही है, उससे अच्छा यही है कि उसकी घर वापसी कर दी जाए, ताकि वह स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सके। आखिर बिटिया कब तक लाचारी का जीवन जिएगी? लाचारी से भरा जीवन जीने से अच्छा यही है कि वह तलाक लेकर अपने माता-पिता के घर आ जाए। इन दिनों समाज में एक नई परंपरा देखने को मिल रही है। जिस तरह से बेटे को अपना जीवन जीने का हक है, उसी तरह बेटी को भी है। बेटी और बेटे के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन सच्चा और कौन झूठा है, इसे समझने में बरसों लग जाते हैं, इसलिए यही अच्छा है कि बेटी घर ही आ जाए। बेटी घर की इज्जत है, यह सूत्रवाक्य आज हमारे समाज में अमल में लाया जाता है, पर बेटी के भी अपने सपने होते हैं, वह भी खुलकर जीना चाहती है। आखिर अपनी इच्छाओं को मारकर कब तक जिया जाए? इसलिए कानपुर के अनिल कुमार ने एक नई परंपरा की शुरुआत कर समाज को दिशा देने की कोशिश की है। अनिल कुमार जैसी सोच बहुत कम लोगों की होती है। उन्होंने समझ लिया था कि बेटी को ससम्मान घर लाकर वे समाज के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, पर समाज को भी सोचना चाहिए कि कौन माता-पिता ऐसे होंगे, जो अपनी बेटी को उसके हाल पर छोड़ देना चाहते हैं। धनलिप्सा के कारण ससुराल वाले बेटी को बरसों से प्रताड़ित ही कर रहे हैं। आखिर इस कुप्रथा को खत्म करने की कोशिश भी तो होनी चाहिए। बेटी को नई जिंदगी देने के लिए माता-पिता का यह प्रयास आज भले ही अनुकरणीय न लगे, पर भविष्य में इसे सही मान लिया जाएगा, यह तय है। अब समाज को भी सारे मिथकों से दूर होना होगा। बेटी को लेकर गढ़े गए तमाम सूत्रवाक्यों को नई सिरे से पारिभाषित करना होगा। बेटी को भी जीने का हक है, इसे समझते हुए ही अनिल ने जो किया, उसे नमन करना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

शपथ ग्रहण

प्रभुनाथ शुक्ल

संसद की गरिमा बनाए रखना जरूरी

> शपथ ग्रहण समारोह चाहे जिस भाषा में हो लेकिन देश, संविधान और संसद की गरिमा का सम्मान आवश्यक है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जिस तरह हमारे माननीयों ने जिंदाबाद की संस्कृति का ईजाद किया वह पूरी तरह संसद की संस्कृति, संस्कार, विधान, व्यवस्था, गरिमा और मर्यादा के खिलाफ है। पुराने और कई वरिष्ठ सांसदों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश माननीयों ने संसद और लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी नहीं दिखाई। देश के मीडिया में शपथ ग्रहण समारोह की खूब चर्चा है। शपथ ग्रहण के लिए भी एक विशेष गाइडलाइन बननी चाहिए, जिसमें कोई भी निर्वाचित सांसद क्षेत्रवाद, धर्म-जाति, भाषा का नारा बुलंद नहीं कर सकता।

आप माननीय हैं। आप संविधान, विधान और व्यवस्था से ऊपर नहीं हैं। आपको न संसद की गरिमा का मान है न देश के गौरव का। शपथ ग्रहण में जिस तरह आपने अपने माननीय होने का परिचय दिया, वह हमारी संसदीय व्यवस्था का कभी हिस्सा नहीं हो सकता। आप अपनी हरकतों से खुद को भले गौरवान्वित महसूस कर रहे हों, लेकिन देश और लोकतंत्र शर्मसार है। आप के हाथों में संविधान की किताबें भले हों, लेकिन आपका व्यवहार संविधान की चौखट लांघता दिखा। 18वीं लोकसभा में 535 माननीय सांसदों ने शपथ ली, लेकिन किसी ने अपनी अमिट छाप नहीं छोड़ी। कुछ पुराने एवं वरिष्ठ माननीयों को छोड़कर। शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरह की छवि हमारे माननीयों की उभर कर आई है वह अपने आप में शर्मसार करती है। देश की आत्मा कहीं से भी झलकती हुई नहीं दिखी। अनेकता में एकता की कोई गंध और सुगंध नई आई। सत्ता और विपक्ष पूरी तरह से विभाजित दिखा।

माननीय सांसद देश, संविधान और संसद की व्यवस्था को ताक पर रखकर अपने-अपने राजनीतिक स्वार्थ, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद के अहम में टूटते और बिखरते दिखे। इस समारोह में देश की खूबसूरती हाशिये पर रही, जबकि क्षेत्रवाद, जाति और धर्म शीर्ष पर दिखा। यह अपने आप में विचारणीय बिंदू है। हम देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। देश की जनता ने जिन लोगों को चुनकर भेजा है उसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं यह अपने आप में विचरणीय प्रश्न है। इस पर विस्तृत विमर्श की जरूरत है। हम वोटबैंक और सत्ता के लालच में वैचारिक विभाजन के जरिये सामाजिक अलगाववाद की तरह बढ़ रहे हैं। अब इससे बड़ी हमारी सोच क्या हो सकती है कि हमने देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को चुनकर संसद भेज दिया है, जबकि चुनाव जीतने वाले जेल में बंद होने की वजह से शपथ भी नहीं ले पाए। यह क्षेत्रवाद का ही जहर है। फिर राष्ट्रीय एकता की बात कहां से कर सकते हैं।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) हैदराबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह संसद की गरिमा और व्यवस्था को तार-तार किया वह अपने आप में काबिलेगौर है। भारतमाता और संविधान की जय बोलने के बजाय जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा बुलंद किया। ओवैसी को सिर्फ एक क्षेत्र विशेष से प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन वह खुद को सरकार मान बैठे हैं। देश की नीति तय करने का अधिकार उन्हें किसने दिया। फिलिस्तीन-इजरायल, रूस-यूक्रेन के प्रति हमारी नीति क्या होगी यह सार्वभौमिक संसद और सरकार तय करेगी। निश्चित रूप ओवैसी की तरफ से दिया गया बयान बेहद घटिया और संसद की गरिमा के खिलाफ है। उनकी संसद सदस्यता खत्म करने के लिए राष्ट्रपति को जो पत्र दिए गए हैं उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। संसद में प्रतिपक्ष के नेता निर्वाचित हुए राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर शपथ ग्रहण करने पहुंचे। उन्होंने अपनी शपथ अंग्रेजी में ली और शपथ ग्रहण के बाद जय संविधान का नारा

लगाया। यह उनकी बचकानी हरकतें हैं। वह पुराने सदस्य हैं उन्हें राजनीतिक स्टंट से दूर रहना चाहिए। अपने गंभीर व्यक्तित्व का परिचय देना चाहिए, उस स्थिति में जब वे विपक्ष के नेता चुने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से पहली बार विजयी हुए चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक साथ कई नारे बुलंद किए जिसमें नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जवान, जय किसान, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद के नारे लगाए। इससे भी सत्ता और विपक्ष के सांसदों के बीच नोकझोंक हुई। रावण बसपा यानी मायावती को कमजोर होता देख दलितों को खुद का मसीहा दिखाने के लिए तेवरदार राजनीति का नैरेटिव गढ़ रहे हैं। उनकी राजनीति वोटबैंक के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन समाज और व्यवस्था के लिए बिल्कुल नहीं।

शपथ ग्रहण के दौरान भाजपा सांसदों ने धार्मिक नारों का उपयोग किया। बरेली सीट से भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार ने जहां जय हिंदू राष्ट्र का नारा दिया। वहीं मेरठ से टीवी सीरियल रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल जय श्रीराम का जयघोष किया। विपक्ष ने दोनों सांसदों के नारे का प्रबल विरोध किया। अरुण गोविल के जय श्री राम नारे के विरोध में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जय अवधेश नारा बुलंद किया, क्योंकि अयोध्या की फैजाबाद सीट से अवधेश कुमार निर्वाचित हुए हैं। इस सीट पर बीजेपी की हार को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है और अयोध्या के लोगों पर सोशल मीडिया पर टिप्पणियां की जा रही हैं, जबकि मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने शपथ ग्रहण के बाद राधे-राधे कर लोगों का अभिवादन किया। क्योंकि वह मथुरा से चुनकर आती हैं और मथुरा भगवान कृष्ण से जड़ा है। शपथ ग्रहण समारोह में सांसदों के व्यवहार और नारेबाजी को लेकर ऐसा लग रहा था जैसे नव निर्वाचित माननीयों में नारे लगाने की होड़ चल रही हो। इस नारेबाजी की होड़ में कोई पिछड़ना नहीं चाह रहा था। डीएमके सांसदों ने उदय नीति स्टालिन जिन्दाबाद के नारे लगाए, जबकि गाजियाबाद से निर्वाचित भाजपा सांसद अतुल गर्ग ने अटल बिहारी और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद उन्होंने डॉ. हेडगेवार जिंदाबाद के भी नारे लगाए। पूर्वांचल की भदोही लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद डॉ विनोद बिंद ने जय बिंद, समाज, जय निषाद जैसे जातिवादी नारों का प्रयोग किया। देवरिया से संसद पहुंचे शशांक मणि ने अपने अंतिम उद्बोधन में जय देवरिया का नारा लगाया। देश के विभिन्न हिस्सों से चुनकर आए माननीय सांसदों का व्यवहार संसद के प्रति कितना उत्तरदायी था यह कहना बड़ा मुश्किल है। पुराने और कई वरिष्ठ सांसदों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश माननीयों ने शपथ ग्रहण के दौरान संसद और लोकतंत्र के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई। देश के मीडिया में शपथ ग्रहण समारोह की खूब चर्चा है। अब वक्त आ गया है जब शपथ ग्रहण के लिए भी एक विशेष गाइडलाइन बननी चाहिए, जिसमें कोई भी निर्वाचित सांसद क्षेत्रवाद, धर्म-जाति, भाषा का नारा बुलंद नहीं कर सकता।

शपथ ग्रहण समारोह चाहे जिस भाषा में हो लेकिन देश, संविधान और संसद की गरिमा का सम्मान आवश्यक है। अगर जिंदाबाद करना है तो सिर्फ भारत माता और संविधान की करिये। सत्ता हो या विपक्ष सभी को इस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। सरकार को आगे आकर मानसून सत्र में इस पर गंभीर चर्चा करानी चाहिए। विपक्ष को इस पर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह सवाल सिर्फ सत्ता-विपक्ष का नहीं बल्कि देश, संसद और लोकतंत्र की गरिमा का है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए एक विशेष नियम और कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह हमारे माननीयों ने जिंदाबाद की संस्कृति का ईजाद किया वह पूरी तरह संसद की संस्कृति, संस्कार, विधान, व्यवस्था, गरिमा और मर्यादा के खिलाफ है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

रिलेशनशिप को रखना है स्ट्रांग

संकलित

दर्शन

किसी संबंध का आरंभ आकर्षण से होता है। यदि आप आसानी से उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो आकर्षण समाप्त हो जाता है। किंतु यदि प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो उसके प्रति प्रेम का जन्म होता है। जब आप प्रेम का अनुभव करते हैं तो कुछ समय के पश्चात मांग उठती है। जब आप मांगना शुरू करते हैं, तो प्रेम घट जाता है। मांग प्रेम को नष्ट कर देती है। आनंद दूर हो जाता है, तो आप कहते हैं, 'ओह, मैंने यह संबंध बनाकर भूल की है।' फिर उससे बाहर निकलने के लिए संघर्ष और पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इससे बाहर निकलने के बाद आप एक अन्य संबंध बनाते हैं, और वही कहानी दोहराई जाती है। किसी भी संबंध को बनाए रखने में तीन बातें आवश्यक हैं : समुचित धारणा, समुचित अवलोकन और समुचित अभिव्यक्ति। अक्सर लोग कहते हैं कि कोई भी उन्हें नहीं समझता है। कोई भी मुझे नहीं समझता है, ऐसा कहने के बजाय आप कह सकते हैं कि मैं स्वयं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता हूं। यदि आप एक स्पेनिश व्यक्ति से रूसी भाषा बोलते हैं, तो वह निश्चित रूप से नहीं समझेगा। सही धारणा तब हो सकती है, जब आप स्वयं को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखते हैं। सही धारणा, फिर सही अवलोकन। आपकी धारणा समुचित हो सकती है, लेकिन आप प्रतिक्रिया किस प्रकार देते हैं? आप अपने भीतर कैसा अनुभव करते हैं? अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करना दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। आपके भीतर संवेदना तथा प्रवृत्तियों के अवलोकन के साथ संस्कारों का अवलोकन भी आवश्यक है।

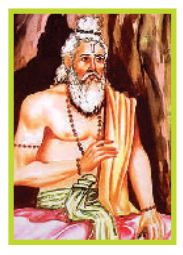

अच्छे कार्य करने से गुरु शिष्य को कभी न रोके

संकलित

प्रेरणा

दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य बताए गए हैं। भगवान शिव ने शुक्राचार्य को मृत संजीवन विद्या दी थी। इस विद्या से शुक्राचार्य मरे हुए दैत्यों को फिर से जीवित कर देते थे। जब दैत्यराज बलि का राज था। तब एक दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और बलि के पास पहुंचे। बलि अपनी दानवीरता की वजह से बहुत प्रसिद्ध थे। वे किसी भी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे। बलि ने वामन देव को देखा तो वह उनके पास पहुंचा। वामन देव ने राजा बलि से तीन पग भूमि दान में मांगी। शुक्राचार्य वामन देव को पहचान गए थे कि ये विष्णु जी हैं। इसलिए उन्होंने बलि को दान देने से रोकना चाहा। राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और वामन देव को दान देने के लिए तैयार हो गए। तब शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में सूक्ष्म रूप में बैठ गए, जिससे की पानी बाहर न आए और राजा बलि भूमि दान करने का संकल्प न ले सकें। वामन भगवान जानते थे कि शुक्राचार्य बलि के कमंडल में बैठे हैं। उन्होंने बलि के कमंडल में एक तिनका डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके बाद शुक्राचार्य कमंडल से बाहर आ गए और बलि ने वामन देव को भूमि दान दे दी। अगर कोई गुरु अपने शिष्य को नेक काम करने से रोकता है तो उसे इसका बुरा फल भोगना पड़ता है।

अंतर्मन

आज की पाती

ड्रोन से की जाए वनों की निगरानी

हर वर्ष गर्मियों में देश के कुछ वन संपदा के धनी राज्यों में जंगलों में भयंकर आग लगने की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने को मिलती हैं। आग किसी भी कारण से जंगलों में लगती है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग गर्मियों के दिनों में बेकार की घास-फूस को जलाने के लिए जंगलों या खेतों में आग लगा देते हैं, जिससे उसी फालतू की घास-फूस के साथ ही सैकड़ों वृक्ष भी आग की बलि चढ़ जाते हैं, जो कि प्रकृति से खिलवाड़ है और हरी-भरी वादियों के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लोग इस बात का ध्यान रखें कि यह आग खेतों के साथ लगते जंगलों में न फैले। जब हरे-भरे जंगल नष्ट हो जाते हैं तो कई हिंसक जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में आ जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वन विभाग को चाहिए कि इस तरह की घटनाओं पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखे। – *शेखर मेहता, कांकेर*

ट्रेंड

मेरा युवा भारत अभियान

विकसित भारत के निर्माण में होगी युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित। सरकार ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी और बढ़ाने के लिए 'मेरा युवा भारत' अभियान की शुरुआत की है। इसमें अब तक डेढ़ करोड़ से अधिक युवाओं का पंजीकरण हो चुका है।
-मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री

वास्तविक प्रकृति को जानें

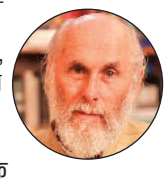

एआई हमें प्रबुद्ध युग में मार्गदर्शन नहीं कर सकता। केवल ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता और स्व की पहचान ही ऐसा कर सकती है। कृत्रिम, रासायनिक, यांत्रिक या मात्रात्मक हर चीज से परे शुद्ध चेतना के रूप में वास्तविक प्रकृति को जानें जो मन की रचनाएं हैं।
-डॉ डेविड फ्रॉली, अमेरिकी हिंदू लेखक

स्वाध्याय महान तप

सनातन हिन्दू वैदिक संस्कृति में स्वाध्याय महान तप है, जो हमारी जीवनचर्या का आवश्यक अंग होना चाहिए। ग्रंथों का अध्ययन वैचारिक नवीन्यता के साथ लक्ष्य की संप्राप्ति में सहायक है। अतः आत्म-सामर्थ्य के लिए सद्ग्रन्थों की ओर लौटें।
-अवधेशानंद, आध्यात्मिक गुरु

नारे को ठुकराया

मोदी सरकार द्वारा लिखित राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनकर ऐसा लगा जैसे मोदी जनादेश को नकारने की हर संभव कोशिश कर रहें हैं। जनादेश उनके खिलाफ था, क्योंकि देश की जनता ने 400 पार के नारे को ठुकराया।
-मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष

करंट अफेयर

चीन ने अध्ययन के लिए सभी देशों के वैज्ञानिकों को बुलाया

चीन के अंतरिक्ष अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि चांद पर एक ऐतिहासिक अभियान को पूरा करने के बाद पृथ्वी पर लौटे चांग ई-6 द्वारा जुटाये गये नमूनों के अध्ययन के लिए वे दुनियाभर के वैज्ञानिकों का स्वागत करते हैं लेकिन अन्वेषण की इस प्रक्रिया में कुछ सीमाएं हैं, विशेषरूप से अमेरिका के साथ। अधिकारियों ने अभियान की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने के लिए बीजिंग में आयोजित एक टेलीविजन समाचार सम्मेलन में बताया कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह का सहयोग, नासा के साथ प्रत्यक्ष द्विपक्षीय सहयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिकी कानून को हटाने पर निर्भर होगा। चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के उपाध्यक्ष बियान झिगांग ने बताया, 'अमेरिक-चीन अंतरिक्ष सहयोग में बाधा की जड़ वुल्फ संशोधन में बरकरार है।' उन्होंने कहा, 'अगर अमेरिका वास्तव में नियमित अंतरिक्ष सहयोग शुरू करना चाहता है तो मुझे लगता है कि उन्हें इस बाधा को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।' वुल्फ संशोधन 2011 में प्रभावी हुआ था और यह संशोधन अमेरिका और चीन के बीच केवल उन द्विपक्षीय सहयोग को मंजूरी देता है, जिसमें एफबीआई यह प्रमाणित कर सके कि कार्य के दौरान चीनी पक्ष के साथ सूचना साझा करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

ऑफ बीट

एक हजार और प्रजातियों पर अस्तित्व का खतरा मंडराया

अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संगठन के मुताबिक करीब 45 हजार प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है जो पिछले साल के मुकाबले एक हजार अधिक है। संगठन ने इस स्थिति के लिए जलवायु परिवर्तन, आक्रामक प्रजातियों और मानव गतिविधियों जैसे अवैध व्यापार और बुनियादी ढांचा विस्तार को जिम्मेदार ठहराया है। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वरसेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) ने बृहस्पतिवार को लुप्त होने के खतरे का सामना कर रही प्रजातियों की नवीनतम सूची जारी की। संगठन ने अपने 60वें वर्ष में जारी इस सूची में विलुप्ति के खतरे का सामना कर रहे जानवरों और पौधों के बारे में चेतावनी दी है, लेकिन साथ ही इबेरियन लिंक्स (वनबिलाव)जैसी प्रजातियों के संरक्षण में मिली सफलता पर भी प्रकाश डाला है। सूची में अब 1,63,040 प्रजातियों को शामिल किया गया है जो पिछले साल से लगभग 6,000 अधिक हैं। आईयूसीएन ने खुलासा किया कि चिली के अटाकामा तटीय रेगिस्तान में पाए जाने वाले कोपियापोआ कैक्टस, बोर्नियन हाथी और ग्रेन कैनरिया की विशालकाय छिपकली विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही प्रजातियों में शामिल हैं। कोपियापोआ कैक्टस के विलुप्ति के कारणों में सोशल मीडिया का चलन प्रमुख है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।